



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 9, 1973/ज्याइस्था 19, 1895

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9, 1973/JYAISTHA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1973

का. आ. 1588.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 48-राजगीर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बखिरदू सपुत्र श्री जोधू, ग्राम व पो. आ. राजाट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बखिरदू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद्

के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. हि.प्र.वि.स./48/72(6)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1973

S.O. 1588.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bakhirdu, S/o Shri Jodhu, Village and P.O. Rajot, Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh, a contesting candidate for general election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from 48-Rajgir Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason for justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bakhirdu to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HP-LA/48/72(6)]

आवृत्ति

नई दिल्ली, 9 मई, 1973

का. आ. 1589.—यत्तः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 57 कुल्लू निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमर चन्द सुपुत्र श्री खेमू राम, मिनरवा स्टूडियो, आखाड़ा बाजार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत्तः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री अमर चन्द को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. वि.प्र.-वि.स./57/72(7)]

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1973

S.O. 1589.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amar Chand S/o Shri Khemu Ram, Minerva Studio, Akhara Bazar, Kulu, District Kulu, Himachal Pradesh, a contesting candidate for general election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from 57-Kulu Assembly Constituency held in March, 1972, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason for justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amar Chand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HP-LA/57/72(7)]

आवृत्ति

का. आ. 1590.—यत्तः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 95 बुलडाना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मालासकर रघुनन्दन राम कृष्ण म्. व. डा. बाराखोडी, तालुक मलकापुर, जिला बुलडाना, महाराष्ट्र, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्तः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण

नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मालासकर रघुनन्दन राम कृष्ण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा.-वि. स./95/72(20)]

ORDER

S.O. 1590.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Palaskar Raghunandan Ramakrishna, At & Post Borakhedi, Tq. Malkapur, District Buldana (Maharashtra), a contesting candidate for the election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 95-Buldana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the people Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

2. And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Palaskar Raghunandan Ramakrishna to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/95/72 (20)]

नई दिल्ली, 14 मई, 1973

का. आ. 1591.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्देश देता है कि उसकी अधिसूचना सं. 434/केल/71, तारीख 6 जनवरी, 1971 में निम्नीलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में क्रम सं. 13 के सामने मद्र सं. 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "4-जिला कलक्टर, कोट्टायम के वैयक्तिक सहायक (भूमि सुधार)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं. 434/केल/73(1)]

ए. एन. सैन, सचिव

New Delhi, the 14th May, 1973

S.O. 1591.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434/KL/71 dated the 6th January, 1971, namely :—

In column 3 of the table appended to the said notification for the existing entry at item 4 against serial No. 13 the entry "4-Personal Assistant (Land Reforms) to the District Collector, Kottayam" shall be substituted.

[No. 434/KL/73(1)]

A. N. SEN, Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

का. आ. 1592.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग पंजाब राज्य की सरकार के परामर्श से श्री प्रीतमोहिनंदर सिंह के स्थान पर श्री कुलवंत सिंह अहलुवालिया, आयुक्त गृह तथा उद्योग, पंजाब को 7 मई, 1973 से अगले आदर्शों तक पंजाब राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्दिष्ट करता है।

[सं. 154/पंजाब/73]

बी. एन. भारद्वाज, सचिव

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1592.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Punjab, hereby nominates Shri Kulwant Singh Ahluwalia, Commissioner for Home and Industries, Punjab, as the Chief Electoral Officer for the State of Punjab with effect from the 7th May, 1973 and until further orders vice Shri Pritmohinder Singh.

[No. 154/PB/73]

B. N. BHARDWAJ, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और वीमा विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1973

आय-कर

का. आ. 1593.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सर्वश्री परमजीत सिंह, डी. आर. आप्टे और जी. एस. सुब्रामनियम के, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, जो अधिसूचना सं. (फा. सं. 16/139/69-आई टी. सी. सी.) तारीख 31 जुलाई, 1969, सं. 179 (फा. सं. 404/62/71-आई टी. सी. सी.) तारीख 14 जून, 1971 और संख्या 183 (फा. सं. 404/66/72-आई टी. सी. सी.) तारीख 8 सितम्बर, 1972 के अधिस्तंभित करती है, तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[सं. 330 (फा. सं. 404/124/73-आई टी. सी. सी.)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 18th April, 1973

INCOME-TAX

S.O. 1593.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of the clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises S/Shri Paramjit Singh, D. R. Apte and G. S. Subramanian who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. This notification which supercedes Notification No. 111 (F. No. 16/139/69-ITCC) dated 31st July, 1969, No. 179 (F. No. 404/62/71-ITCC) dated 14th June, 1971 and No. 183 (F. No. 404/66/72-ITCC) dated 8th September, 1972 shall come into force with immediate effect.

[No. 330 (F. No. 404/124/73-ITCC)]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1973

का. आ. 1594.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सर्वश्री के. के. कालिया और के. एस. गोविंदया को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. क्रमशः अधिसूचना सं. 20 (फा. सं. 404/26/71-आई टी. सी. सी.) तारीख 4 फरवरी, 1971 और सं. 67 (फा. सं. 404/104/72-आई टी. सी. सी.), तारीख 12 मई, 1970 द्वारा की गई थी के. के. तिवारी और श्री आर. आर. गोस्वामी की नियुक्ति 1 मई, 1973 से रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना 1 मई, 1973 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 336 (फा. सं. 404/128/73-आई टी. सी. सी.)]

एम. एन. नाम्बियार, अवर सचिव

New Delhi, the 24th April, 1973

S.O. 1594.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri K. K. Kalia and K. S. Gogia who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointment of Shri K. K. Tewari and Shri R. R. Goswami made in the Notifications No. 20 (F. No. 404/26/71-ITCC) dated 4th February, 1971 and No. 67 (F. No. 404/104/72-ITCC) dated 12th May, 1970 respectively is cancelled with effect from 1st May, 1973.

3. This Notification shall come into force with effect from 1st May, 1973.

[No. 336 (F. No. 404/128/73-ITCC)]

M. N. NAMBIAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1973

का. आ. 1595.—आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कादरी श्री मंजूनाथ मंदिर, मंगलोर को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए देश में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा के स्थान के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 333-फा. सं. 176/2/73-आई टी. (ए. आई.)]

वी. बी. श्रीनिवासन, अवर सचिव

New Delhi, the 21st April, 1973

S.O. 1595.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Kadri Shri Manjunatha Temple, Mangalore to be a place of public worship of renown throughout the country for the purposes of the said section.

[No. 333—F. No. 176/2/73-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

का. आ. 1596.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट, 1948) (1948 का 15) की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से, एतद्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि. (इण्डस्ट्रियल रिक्न्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.) [कम्पनीज एक्ट, 1956 (1956 का 1) के अधीन गठित एवम् पंजीकृत कम्पनी] को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्थान अधिसूचित करती हैं।

[सं. 1/12/73-आई. एफ. 2]
डी. के. सेन, उप सचिव

(Banking Department)

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1596.—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, in consultation with the Industrial Development Bank of India, hereby notifies the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited [a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)], as a financial institution for the purposes of the said section.

[No. 1-12/73/IF II]
D. K. SEN, Dy. Secy.

का. आ. 1597.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10वां) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के उपबन्ध नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लि., कलकत्ता, पर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे, जहां तक उक्त उपबन्ध भारतवर्ष में उक्त बैंक के महाप्रबन्धक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिस्टर एच. एम. जैकसन के दी हर्ट्स्ट इण्डिया क्लिनिक लि. का गवर्नर होने पर रोक लगाते हैं।

[सं. 15(17)-बी. ओ. 3/73]

व. म. सुक्थनकर, निदेशक

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1597.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to National and Grindlays Bank Ltd., Calcutta, for a period of one-year from the date of this notification, in so far as the said provisions prohibit Mr. H. M. Jackson, its General Manager and Chief Executive Officer in India, from being a Governor of the East India Clinic Ltd.

[No. 15(17)-B.O. III/73]
D. M. SUKTHANKAR, Director.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

का० आ० 1598.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुमरण में मई 1973 की 11 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

| वेयताएँ | रुपये | रुपये | प्रास्तियाँ | रुपये | रुपये |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट | 18,02,11,000 | | सोने का सिक्का और बुलियन — | | |
| | | | (क) भारत में रखा हुआ | 182,53,11,000 | |
| | | | (ख) भारत के बाहर रखा हुआ | | |
| संचालन में नोट | 5696,10,38,000 | | विदेशी प्रतिभूतियाँ | 171,65,38,000 | |
| | | | जोड़ | | 354,18,49,000 |
| जारी किये गये कुल नोट | | 5714,12,49,000 | रुपये का सिक्का | | 5,58,37,000 |
| | | | भारत सरकार की रुपया प्रति- | | 5354,35,63,000 |
| | | | भूतियाँ | | |
| | | | वैश्वी विनियम बिल और दूसरे | | |
| | | | वाणिज्य-पत्र | | |
| कुल यताएँ | | 5714,12,49,000 | कुल प्रास्तियाँ | | 5714,12,49,000 |

एस. जगन्नाथन, गवर्नर

11 मई 1973 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्य-कलाप का विवरण

| देयताएँ | रुपये | प्रास्तियाँ | रुपये |
|--|----------------|---|----------------|
| चुकता पूंजी | 5,00,00,000 | नोट | 18,02,11,000 |
| प्रारक्षित निधि | 150,00,00,000 | रुपये का सिक्का | 4,82,000 |
| राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि | 209,00,00,000 | छोटा सिक्का | 3,57,000 |
| | | खरीदे और भुनाये गये बिल :— | |
| | | (क) देशी | 18,83,60,000 |
| राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि | 45,00,00,000 | (ख) विदेशी | .. |
| | | (ग) सरकारी खजाना बिल | 315,24,53,000 |
| राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ निधि) | 175,00,00,000 | विदेशों में रखा हुआ बकाया* | 217,27,79,000 |
| जमा राशियाँ :— | | निवेश** | 362,31,11,000 |
| (क) सरकारी | | ऋण और अग्रिम :— | |
| (i) केन्द्रीय सरकार | 55,89,97,000 | (i) केन्द्रीय सरकार को | .. |
| (ii) राज्य सरकारें | 17,96,28,000 | (ii) राज्य सरकारों को† | 83,00,18,000 |
| (ख) बैंक | | ऋण और अग्रिम :— | |
| (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 333,03,31,000 | (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ‡ | 58,82,60,000 |
| (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 14,32,67,000 | (ii) राज्य सहकारी बैंकों को @ | 222,99,24,000 |
| (iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 1,25,25,000 | (iii) दूसरों को | 5,39,12,000 |
| (iv) अन्य बैंक | 37,02,000 | राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश | |
| | | (क) ऋण और अग्रिम :— | |
| | | (i) राज्य सरकारों को | 65,51,65,000 |
| | | (ii) राज्य सहकारी बैंकों को | 20,44,94,000 |
| | | (iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को | .. |
| | | (iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को | 29,70,00,000 |
| (ग) अन्य | 83,58,68,000 | (ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश | 11,24,73,000 |
| | | राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम | |
| वेय बिल | 67,86,27,000 | राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से | 28,94,88,000 |
| अन्य देयताएँ | 451,64,30,000 | ऋण अग्रिम और निवेश | |
| | | (क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम | 95,09,35,000 |
| | | (ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबेंचरों में निवेश | .. |
| | | अन्य प्रास्तियाँ | 57,00,13,000 |
| | | | |
| रुपये | 1609,94,35,000 | रुपये | 1609,94,35,000 |

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परंतु राज्य सरकारों को किये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

‡रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम किये गये 15,22,50,000/- रुपये शामिल हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 22nd May, 1973

S. O. 1598.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 11th day of May 1973

Issue Department

| Liabilities | Rs. | Rs. | Assets | Rs. | Rs. |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| Notes held in the Banking Department | 18,02,11,000 | | Gold Coin and Bullion:— | | |
| Notes in circulation | 56,96,10,38,000 | | (a) Held in India | 1,82,53,11,000 | |
| Total Notes issued | | 57,14,12,49,000 | (b) Held outside India | | |
| | | | Foreign Securities | 1,71,65,38,000 | |
| | | | Total | | 3,54,18,49,000 |
| | | | Rupee Coin | | 5,38,37,000 |
| | | | Government of India Rupee Securities | | 53,54,35,63,000 |
| | | | Internal Bills of Exchange and other commercial paper | | |
| Total Liabilities | | 57,14,12,49,000 | Total Assets | | 57,14,12,49,000 |

S. Jagannathan, Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 11th May, 1973

| Liabilities | Rs. | Assets | Rs. |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Capital Paid Up | 5,00,00,000 | Notes | 18,02,11,000 |
| Reserve Fund | 1,50,00,00,000 | Rupee Coin | 4,82,000 |
| National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund | 2,09,00,00,000 | Small Coin | 3,57,000 |
| National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund | 45,00,00,000 | Bills Purchased and Discounted:— | |
| National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund | 1,75,00,00,000 | (a) Internal | 18,83,60,000 |
| Deposits:— | | (b) External | |
| (a) Government | | (c) Government Treasury Bills | 3,15,24,53,000 |
| (i) Central Government | 55,89,97,000 | Balances Held Abroad* | 2,17,27,79,000 |
| (ii) State Governments | 17,96,28,000 | Investments** | 3,62,31,11,000 |
| (b) Banks | | Loans and Advances to:— | |
| (i) Scheduled Commercial Banks | 3,33,03,31,000 | (i) Central Government | |
| (ii) Scheduled State Co-operative Banks | 14,32,67,000 | (ii) State Governments@ | 83,00,18,000 |
| (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks | 1,25,25,000 | Loans and Advances to:— | |
| (iv) Other Banks | 37,62,000 | (i) Scheduled Commercial Banks† | 58,82,60,000 |
| (c) Others | 83,58,68,000 | (ii) State Co-operative Banks†† | 2,22,99,24,000 |
| Bills Payable | 67,86,27,000 | (iii) Others | 5,39,12,000 |
| Other Liabilities | 4,51,64,30,000 | Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund | |
| Rupees | 16,09,94,35,000 | (a) Loans and Advances to:— | |
| | | (i) State Governments | 65,51,65,000 |
| | | (ii) State Co-operative Banks | 20,44,94,000 |
| | | (iii) Central Land Mortgage Banks | |
| | | (iv) Agricultural Refinance Corporation | 29,70,00,000 |
| | | (b) Investment in Central Land Mortgage Banks Debentures | |
| | | Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund | 11,24,73,000 |
| | | Loans and Advances to State Co-operative Banks | 28,94,88,000 |
| | | Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund | |
| | | (a) Loans and Advances to the Development Bank | 95,09,35,000 |
| | | (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank | |
| | | Other Assets | 57,00,13,000 |
| | | Rupees | 16,09,94,35,000 |

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs.15,22,50,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17 (4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Including Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN, Governor

Dated the 16th day of May 1973.

[No. F. 1 (1)/73-BO.]

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

का० आ० 1599—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मई 1973 की 18 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

| देयताएँ | रुपये | रुपये | आस्तियाँ | रुपये | रुपये |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट | 32,29,84,000 | | सोने का सिक्का और बुलियन :— | | |
| संचालन में नोट | 5705,23,19,000 | | (क) भारत में रखा हुआ | 182,53,11,000 | |
| जारी किये गये कुल नोट | | 5737,53,03,000 | (ख) भारत के बाहर रखा हुआ | | |
| | | | विदेशी प्रतिभूतियाँ | 171,65,38,000 | |
| | | | जोड़ | | 354,18,49,000 |
| | | | रुपये का सिक्का | | 3,98,93,000 |
| | | | भारत सरकार की रुपया प्रति- | | 5379,35,61,000 |
| | | | भूतियाँ | | |
| | | | देशी विनिमय बिल और दूसरे | | |
| | | | वाणिज्य-पत्र | | |
| कुल देयताएँ | | 5737,53,03,000 | कुल आस्तियाँ | | 5737,53,03,000 |

एम० एस० शिरालकर, उप गवर्नर

18 मई, 1973 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

| देयताएँ | रुपये | आस्तियाँ | रुपये |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------|
| धुकता पूंजी | 5,00,00,000 | नोट | 32,29,84,000 |
| भारक्षित निधि | 150,00,00,000 | रुपये का सिक्का | 4,85,000 |
| राष्ट्रीय कृषि ऋण | | छोटा सिक्का | 3,63,000 |
| (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि | 209,00,00,000 | खरीदे और भुनाये गये बिल | |
| राष्ट्रीय कृषि ऋण | | (क) देशी | 17,84,99,000 |
| (स्थिरीकरण) निधि | 45,00,00,000 | (ख) विदेशी | |
| राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण | | (ग) सरकारी खजाना बिल | 311,86,99,000 |
| (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि | 175,00,00,000 | विदेशों में रखा हुआ बकाया* | 230,28,30,000 |
| जमा राशियाँ :— | | निवेश** | 234,65,84,000 |
| (क) सरकारी | | ऋण और भ्रमिः :— | |
| (i) केन्द्रीय सरकार | 59,96,91,000 | (i) केन्द्रीय सरकार को | |
| (ii) राज्य सरकारें | 8,71,90,000 | (ii) राज्य सरकारों को | 120,16,82,000 |
| (ख) बैंक | | ऋण और भ्रमिः :— | |
| (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 324,46,43,000 | (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† | 122,19,45,000 |
| (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 14,35,65,000 | (ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡ | 217,27,46,000 |
| (iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 1,33,36,000 | (iii) दूसरों को | 5,12,97,000 |
| (iv) अन्य बैंक | 33,46,000 | राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से ऋण, | |
| (ग) अन्य | 73,64,82,000 | भ्रमिः और निवेश | |
| देय बिल | 64,51,89,000 | (क) ऋण और भ्रमिः :— | |
| अन्य देयताएँ | 468,98,14,000 | (i) राज्य सरकारों को | 65,51,65,000 |
| | | (ii) राज्य सहकारी बैंकों को | 19,67,75,000 |
| | | (iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को | |
| | | (iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को | 29,70,00,000 |
| | | (ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबैंचरों में निवेश | 11,24,73,000 |
| | | राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और | |
| | | भ्रमिः | |
| | | राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और भ्रमिः | 29,34,83,000 |
| | | राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से | |
| | | ऋण, भ्रमिः और निवेश | |
| | | (क) विकास बैंक को ऋण और भ्रमिः | 95,09,35,000 |
| | | (ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबैंचरों में | |
| | | निवेश अन्य आस्तियाँ | 57,93,11,000 |
| रुपये | 1600,32,56,000 | रुपये | 1600,32,56,000 |

*नकदी, भावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण, (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त ऋण और भ्रमिः शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी भ्रमिः-ड्राफ्ट शामिल हैं।

‡ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सीमादी बिलों पर भ्रमिः दिये गये 17,17,50,000 रुपये शामिल हैं।

§ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और भ्रमिः शामिल नहीं हैं।

तारीख : 23 मई, 1973.

एम० एस० शिरालकर, उप गवर्नर

[म० फ० 1(i)/73-बी०ओ०-1]

ब० ब० मीरबन्दाणी, अवर सचिव

New Delhi, the 25th May, 1973

S. O. 1599.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 18th day of May 1973
ISSUE DEPARTMENT

| Liabilities | Rs. | Rs. | Assets | Rs. | Rs. |
|--|-----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| Notes held in the Banking Department | 32,29,84,000 | | Gold Coin and Bullion:— | | |
| Notes in circulation | 57,05,23,19,000 | | (a) Held in India | 1,82,53,11,000 | |
| Total Notes issued | | 57,37,53,03,000 | (b) Held outside India | .. | |
| | | | Foreign Securities | 1,71,65,38,000 | |
| | | | Total | | 3,54,18,49,000 |
| | | | Rupee Coin | | 3,98,93,000 |
| | | | Government of India Rupee Securities | | 53,79,35,61,000 |
| | | | Internal Bills of Exchange and other commercial paper | | .. |
| Total Liabilities | | 57,37,53,03,000 | Total Assets | | 57,37,53,03,000 |

Dated the 23rd day of May 1973.

S. S. SHIRALKAR, Dy. Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 18th May 1973

| Liabilities | Rs. | Assets | Rs. |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Capital Paid Up | 5,00,00,000 | Notes | 32,29,84,000 |
| Reserve Fund | 1,50,00,00,000 | Rupee Coin | 4,85,000 |
| National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund | 2,09,00,00,000 | Small Coin | 3,63,000 |
| National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund | 45,00,00,000 | Bills Purchased and Discounted:— | |
| National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund | 1,75,00,00,000 | (a) Internal | 17,84,99,000 |
| Deposits — | | (b) External | 3,11,86,99,000 |
| (a) Government | | (c) Government Treasury Bills | 2,30,28,30,000 |
| (i) Central Government | 59,96,91,000 | Balances Held Abroad* | 2,34,65,84,000 |
| (ii) State Governments | 8,71,90,000 | Investments** | |
| (b) Banks | | Loans and Advances to:— | |
| (i) Scheduled Commercial Banks | 3,24,46,43,000 | (i) Central Government | 1,20,16,82,000 |
| (ii) Scheduled State Co-operative Banks | 14,35,65,000 | (ii) State Governments† | 1,22,19,45,000 |
| (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks | 1,33,36,000 | (i) Scheduled Commercial Banks‡ | 2,17,27,46,000 |
| (iv) Other Banks | 33,46,000 | (ii) State Co-operative Banks£ | 5,12,97,000 |
| (c) Others | 73,64,82,000 | (iii) Others | |
| Bills Payable | 64,51,89,000 | Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund | |
| Other Liabilities | 4,68,98,14,000 | (a) Loans and Advances to:— | |
| | | (i) State Governments | 65,51,65,000 |
| | | (ii) State Co-operative Banks | 19,67,75,000 |
| | | (iii) Central Land Mortgage Banks | 29,70,00,000 |
| | | (iv) Agricultural Refinance Corporation | 11,24,73,000 |
| | | (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures | |
| | | Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund | |
| | | Loans and Advances to State Co-operative Banks | 29,34,83,000 |
| | | Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund | |
| | | (a) Loans and Advances to the Development Bank | 95,09,35,000 |
| | | (b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank | .. |
| | | Other Assets | 57,93,11,000 |
| Rupees | 16,00,32,56,000 | Rupees | 16,00,32,56,000 |

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

†Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

‡Includes Rs. 17,17,50,000 Advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

£Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 23rd day of May 1973.

S. S. SHIRALKAR Dy. Governor
[No. F. 1 (1)/73-BO. I]
C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

आयकर

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1973

का. आ. 1600.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं. 99 (फा. सं. 261/19/72-आई टी जे) तारीख 31 मई, 1972 से संलग्न अनुसूची में निम्नीलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में स्तंभ 2 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त (अपील), जम्मू रेंज, जम्मू के सामने क्रम सं. 1(3) की प्रविष्टि "आयकर अधिकारी, चम्बा और कांगड़ा, जिला पठानकोट," के स्थान पर "आयकर सर्किल, कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर और उना, जिला पठानकोट" प्रतिस्थापित की जाएगी।

यह अधिसूचना 8-1-1973 से प्रभावी होगी।

[सं. 257(फा. सं. 261/19/72-आई टी जे)]

स्पष्टीकारक टिप्पण.—यह संशोधन आयकर आयुक्त के प्रभाग में आयकर सर्किल चम्बा और कांगड़ा जिले पठानकोट के आयकर सर्किल कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर और उना जिले पठानकोट के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के कारण आवश्यक हो गया है।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 4th January, 1973

INCOME TAX

S.O. 1600.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its Notification No. 99 (F. No. 261/19/72-ITJ) dated the 31st May, 1972, viz;

In the said Schedule under column 2 against A.A.C., Jammu Range Jammu, at Sr. No. 1(iii), for the existing entry "Income-tax Officer, Chamba and Kangra, Districts at Pathankot" "Income-tax Circle Kangra, Chamba, Hamirpur and Una Districts at Pathankot" shall be substituted.

This Notification shall take effect from 8-1-1973.

[No. 257 (F. No. 261/19/72-ITJ)]

Explanatory Note :

The amendment has become necessary consequent on redesignation of Income Tax Circle Chamba and Kangra Districts, Pathankot as 'Income-tax Circle Kangra, Chamba Hamirpur and Una Districts at Pathankot' in Commissioner of Income-tax's charges.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

का० आ० 1601.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वगत अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित करते हुये, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1

में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उनके स्तम्भ 2 में की नत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वाडों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

| नाम | आयकर सर्किल, वाडें, जिला |
|--------------|---|
| (1) | (2) |
| कालीकट | 1. आयकर सर्किल, कालीकट 2. कम्पनी सर्किल, कालीकट 3. विशेष सर्वेक्षण सर्किल एर्नाकुलम (जो उत्साहित कर दिया गया है) उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार की मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर सर्किल की अधिकारिता में है या जो उनके भीतर रहते हैं। 4. सम्पदा-शुल्क एवं आयकर सर्किल, कालीकट |
| एर्नाकुलम | 1. आयकर सर्किल, मन्नारवेरी 2. आयकर सर्किल, एर्नाकुलम 3. कम्पनी सर्किल, एर्नाकुलम 4. वेतन सर्किल, एर्नाकुलम 5. केंद्रीय सर्किल, एर्नाकुलम 6. सम्पदा-शुल्क एवं आयकर सर्किल, एर्नाकुलम 7. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, एर्नाकुलम (जो उत्साहित कर दिया गया है) उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर सर्किल की अधिकारिता में है या जो उनके भीतर रहते हैं। 8. विशेष सर्किल, एर्नाकुलम |
| त्रिचूर | 1. आयकर सर्किल, पालघाट 2. आयकर सर्किल, त्रिचूर 3. आयकर सर्किल, अलवाई 4. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, एर्नाकुलम (जो उत्साहित कर दिया गया है) उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार के मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर सर्किल की अधिकारिता में हैं या जो उनके भीतर रहते हैं। 5. केंद्रीय सर्किल, त्रिचूर (जो उत्साहित कर दिया गया है) 6. आयकर सर्किल, कनानोर |
| त्रिवेन्द्रम | 1. आयकर सर्किल, त्रिवेन्द्रम 2. वेतन सर्किल, त्रिवेन्द्रम 3. कम्पनी सर्किल, त्रिवेन्द्रम (जो उत्साहित कर दिया गया है) 4. आयकर सर्किल, कवीलीन 5. आयकर सर्किल, मन्नेल्ली 6. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, एर्नाकुलम (जो उत्साहित कर दिया गया है) उन व्यक्तियों की बाबत जिनके |

(1)

(2)

कारबार का मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर सर्किलों की अधिकारिता में है या जो उनके भीतर रहने हैं।

7. विशेष अन्वेषण सर्किल, त्रिवेन्द्रम (जो उत्सादित कर दिया गया है)।
8. आयकर सर्किल, कोट्टायम
9. आयकर सर्किल, तिरुवाला

2. जहाँ तक इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तर्गत कर दिया गया है वहाँ उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जायेंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

3. यह अधिसूचना 15 जनवरी, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं० (263 फ० सं० 261/8/72-आई० टी० जे०)]

स्पष्टीकारक टिप्पण —

आयुक्त के प्रभार में के सहायक आयुक्तों (अपील) में आई के पुनःसंगठन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया है।

New Delhi, the 11th January, 1973

S. O. 1601.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax, of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or super tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in the column 2 thereof :

SCHEDULE

| Name | Income-tax Circle, Ward, District |
|---------------------|--|
| (1) | (2) |
| Calicut | 1. Income-tax Circle, Calicut. 2. Companies Circle, Calicut 3. Special Survey Circle, Ernakulam (since abolished) in respect of persons who have their principal place of business in or reside within the jurisdiction of the Income-tax circles mentioned above. 4. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Calicut. |
| Ernakulam | 1. Income-tax Circle, Mattancherry. 2. Income-tax Circle Ernakulam. 3. Companies Circle, Ernakulam. 4. Salary Circle, Ernakulam. 5. Central Circle, Ernakulam 6. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Ernakulam. |

(1)

(2)

7. Special Survey Circle, Ernakulam (since abolished) in respect of persons who have their principal place of business in or reside within the jurisdiction of the Income-tax Circles mentioned above.

8. Special Circle, Ernakulam.

Trichur 1. Income-tax Circle, Palghat.

2. Income-tax Circle, Trichur.

3. Income-tax Circle, Alwaye.

4. Special Survey Circle, Ernakulam (since abolished) in respect of persons who have their principal place of business in or reside within the jurisdiction of the Income-tax Circles mentioned above.

5. Central Circle, Trichur (since abolished).

6. Income-tax Circle, Cannanore.

Trivandrum 1. Income-tax Circle, Trivandrum.

2. Salary Circle, Trivandrum.

3. Companies Circle Trivandrum (since abolished).

4. Income-tax Circle, Quilon.

5. Income-tax Circle, Alleppey.

6. Special Survey Circle, Ernakulam (since abolished) in respect of persons who have their principal place of business in or reside within the jurisdiction of the Income-tax Circles mentioned above.

7. Special Investigation Circle, Trivandrum (since abolished).

8. Income-tax Circle, Kottayam.

9. Income-tax Circle, Tiruvalla.

2. Where an Income-tax Circle, ward, or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, ward, or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

3. This Notification shall take effect from 15th January, 1973.

[No. 263 (F.No. 261/8/72-ITJ)]

Explanatory note :

The amendment has become necessary consequent on reorganisation of work amongst the Appellate Assistant Commissioners of Commissioners' charge.

क्र. भा. 1602.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं. 236 (फा. सं. 261/4/72-आई टी जे) तारीख 4/12/1972 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

उक्त अनुसूची में, स्तंभ 3 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त (अपील), विशेष रेंज 7, मुम्बई के सामने निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

एस. आई. बी. 7 आयकर अधिकारी का प्रभार

यह अधिसूचना 15 जनवरी, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं. 264 (फा. सं. 261/9/72-आई. टी. जे.)]

स्पष्टीकरण टिप्पणः—यह संशोधन आयकर अधिकारी, एस. आई. बी. 7, मुम्बई पर सहायक आयुक्त (अपील) विशेष रेंज 7, मुम्बई के अधिकारिता के समनुद्देशन के कारण आवश्यक हो गया है।

S.O. 1602.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its Notification No 236 (F. No. 261/4/72-ITJ) dated 4-12-1972 viz.,

In the said Schedule, under Column 3, against A.A.C. Special Range-VII, Bombay the following shall be added:—

S.I.B. VII I.T.O's charge.

This notification shall take effect from 15th January, 1973.

[No. 264 (F. No. 261/9/72-ITJ)]

Explanatory Note :

The amendment has become necessary on account of assignment of jurisdiction to A.A.C. Special Range VII, Bombay over the I.T.O., S.I.B. VII, Bombay.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

क्र. भा. 1603.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं. 100 (फा. सं. 261/7/72-आई टी जे) तारीख 31 मई, 1972 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

(2) उक्त अनुसूची में रेंज-1, जबलपुर के सामने स्तंभ 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित लुप्त कर दिया जाएगा, अर्थात्:—

सं. 6 आयकर अधिकारी, ख वार्ड, कटनी,

सं. 7 आयकर अधिकारी, ग वार्ड, कटनी,

(3) उक्त अनुसूची में रेंज-2 जबलपुर के सामने स्तंभ 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

8. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, कटनी

9. आयकर अधिकारी, ग-वार्ड, कटनी

10. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, कटनी के आदेश के विरुद्ध ऐसे सभी मामलों में जिनमें अधिकारिता आयकर अधिकारी, ख वार्ड, कटनी और आयकर अधिकारी ग-वार्ड, कटनी में आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की अधिसूचना सं. 26/आई टी/एस पी/72 तारीख 25-7-1972 के अनुसार निहित कर दी गई है, के खिलाफ सहायक आयकर

आयुक्त (अपील), विशेष रेंज, जबलपुर के सामने लम्बित सभी अपीलें।

(4) उक्त अनुसूची में इन्दौर रेंज, इन्दौर के सामने स्तंभ 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

15. ऐसे मामलों की सभी अपीलें जो सहायक आयकर आयुक्त (अपील), विशेष रेंज, इन्दौर के सामने लम्बित हैं जिनकी बाबत अधिकारिता आयकर अधिकारी, छ, ट, ड और घ वार्ड, इन्दौर के आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश, भोपाल की अधिसूचना सं. 16/आई टी/एस पी/72 तारीख 24 जुलाई, 1972 और आयकर अधिकारी, खासगोन का आयकर आयुक्त की अधिसूचना सं. 27/आई टी/एस पी/72 तारीख 29-7-72 के अनुसार अधिकारिता निहित कर दी गई है।

यह अधिसूचना 15 फरवरी, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं. 294(फा. सं. 261/2/73-आई. टी. जे.)]

एस. एन. एल. अग्रवाल, अवर सचिव

स्पष्टीकरण टिप्पणः

यह संशोधन प्रत्येक सहायक आयुक्तों (अपील) के पास पर्याप्त कार्यभार के प्रयोजन के लिए कार्य के पुनः आवंटन के कारण आवश्यक हो गया है।

New Delhi, the 12th February, 1973

S.O. 1603.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 100 (F. No. 261/7/72-ITJ) dated 31st May, 1972 as amended from time to time, viz:—

(2) In the said Schedule against Range I, Jabalpur under column 2 the following shall be omitted, namely—No. 6 Income-tax Officer, B-Ward, Katni; No. 7 Income-tax Officer, C-Ward, Katni.

(3) In the said Schedule against Range II, Jabalpur under column 2 the following shall be added namely:—

8. Income-tax Officer, B-Ward, Katni.

9. Income-tax Officer, C-Ward, Katni.

10. All appeals pending with A.A.C. Special Range, Jabalpur against the order of Income-tax Officer, A-Ward, Katni in the cases in which the present jurisdiction is vested on Income-tax Officer, B-Ward, Katni and Income-tax Officer, C-Ward, Katni as per Notification F. No. 26/IT/MP/72 dated 25-7-1972 of the Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh, Bhopal.

(4) In the said Schedule against Indore Range, Indore under column 2 the following shall be added namely:—

15. All appeals pending with A.A.C. Special Range Indore, in the cases in which the present jurisdiction is vested on Income-tax Officers, G. K. M. & Q. Wards, Indore vide Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh, Bhopal's Notification No. 16/IT/MP/72 dated 24th July, 1972 and Income-tax Officer, Khargone vide Commissioner of Income-tax's Notification No. 27/IT/MP/72 dated 29th July, 1972.

This Notification shall take effect from 15th February, 1973

[No. 294(F. No. 261/2/75-ITJ)]

S. N. L. AGARWALA, Under Secy.

Explanatory Note :

The amendment has become necessary on account of re-allocation of work for purpose of adequate work load with each Appellate Assistant Commissioners.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973

1

2

का.प्र.० 1604.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुये, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार केलिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :-

अनुसूची

| रेंज | आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों |
|--------------------------|---|
| (1) | (2) |
| 1. अमृतसर रेंज | 1. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जम्मू और केन्द्रीय रेंज अमृतसर के सामने स्तम्भ 2 में उल्लिखित आयकर सफिलों, वार्डों या जिलों से भिन्न सभी आयकर सफिल, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालय अमृतसर में थे या हैं। |
| 2. केन्द्रीय रेंज अमृतसर | 2. वेतन सफिल जालंधर, जिला I (जिला I (viii) से I(xiv), II, III अमृतसर को छोड़कर) की अधिकारिता में निवास करने वाले व्यक्तियों की बाबत। |
| | 1. सभी केन्द्रीय सफिल जिनका मुख्यालय अमृतसर, अम्बाला, श्री नगर या केन्द्रीय सफिल VIII, नई दिल्ली में था या है। |
| | 2. विशेष सर्वेक्षण सफिल अमृतसर 14-7-67 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका कारबार का मुख्य स्थान केन्द्रीय सफिल, I, II, III, अमृतसर में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं)। |
| | 3. विशेष सर्वेक्षण सफिल पटियाला 14-7-67 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका कारबार का मुख्य स्थान केन्द्रीय सफिल, अम्बाला में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं)। |
| | 4. वेतन सफिल, जालंधर 14-7-67 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है (उन व्यक्तियों की बाबत जो केन्द्रीय सफिल I, II, III, अमृतसर की अधिकारिता के भीतर निवास करते हैं)। |

3. अम्बाला रेंज

सभी आयकर सफिल, वार्ड और जिले जिनका मुख्यालय—(i) अम्बाला, (ii) सोनीपत, (iii) करनाल, (iv) यमुना नगर, (v) शिमला, (vi) पानीपत में है।

4. जालंधर रेंज

1. सभी आयकर सफिल, वार्ड और जिले जिनका मुख्यालय :—

- (i) जालंधर
- (ii) होशियारपुर
- (iii) बटाला
- (iv) कलेक्शन वार्ड, चंडीगढ़, उन व्यक्तियों की बाबत जिनका कारबार का मुख्य स्थान आयकर अधिकारी, होशियारपुर की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं।

2. केन्द्रीय सफिल जिनका मुख्यालय लुधियाना में है।

3. विशेष सर्वेक्षण सफिल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आयकर अधिकारी, जालंधर, बटाला, होशियारपुर और केन्द्रीय सफिल, लुधियाना की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं)।

4. वेतन सफिल, जालंधर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आयकर अधिकारी, जालंधर, बटाला और होशियारपुर की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं)।

5. जम्मू रेंज

1. सभी आयकर सफिल, वार्ड और जिले, जिनका मुख्यालय—

- (i) जम्मू
- (ii) श्रीनगर (केन्द्रीय सफिल श्रीनगर को छोड़कर)
- (iii) आयकर सफिल चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिले, पठानकोट
- (iv) पठानकोट
- (v) गुरदासपुर
- (vi) मंडी
- (vii) जिले 1
- (viii) से 1 (xiv), अमृतसर

2. विशेष सर्वेक्षण सफिल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आयकर अधिकारी पठानकोट या गुरदासपुर की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं)।

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|------------------|---|--|--|
| | 3. वेतन सफिल, जालंधर, (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आय-कर अधिकारी, पठानकोट, गुरदासपुर और जिला 1(vii) से 1(xiv), अमृतसर की अधिकारिता में है या जो उनके भीतर निवास करते हैं) । | | बरनाला और भाटिंडा की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं) । |
| 6. लुधियाना रेंज | 1. सभी आय-कर सफिल, वार्ड या जिले जिनका मुख्यालय— (i) लुधियाना (केन्द्रीय सफिल, लुधियाना को छोड़कर) (ii) अमोहर (iii) मोगा (iv) फिरोजपुर और (v) खन्ना में है । 2. वेतन सफिल, जालंधर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आय-कर अधिकारी, लुधियाना (केन्द्रीय सफिल लुधियाना को छोड़कर), अमोहर, मोगा, फिरोजपुर और खन्ना की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं) । 3. विशेष सर्वेक्षण सफिल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आय-कर अधिकारी, लुधियाना (केन्द्रीय सफिल, लुधियाना, अमोहर, मोगा, फिरोजपुर और खन्ना को छोड़कर) की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं) । | 3 रोहतक रेंज. | सभी आय-कर सफिल, वार्ड और जिले जिनका मुख्यालय— (i) रोहतक (ii) फरीदाबाद (iii) हिनार (iv) मिरसा (v) गुडगाव (vi) रिवाड़ी (vii) नारनौल (viii) जीद में है । |
| 7. पटियाला रेंज | 1. सभी आय-कर सफिल वार्ड और जिले, जिनका मुख्यालय— (i) पटियाला (ii) संगरूर (iii) मलेरकोटला (iv) बरनाला (v) भाटिंडा (vi) चंडीगढ़ में है [परन्तु यह कि आय-कर अधिकारी कलेक्शन वार्ड चंडीगढ़ के होशियारपुर सफिल के निर्धारितियों की बाबत आवेशों के सबंध में अधिकारिता आय-कर आयुक्त (अपील) के पास होगी, जिनकी होशियारपुर में अधिकारिता है] 2. विशेष सर्वेक्षण सफिल, पटियाला (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आय-कर अधिकारी, चंडीगढ़, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला बरनाला और भाटिंडा की अधिकारिता में है या जो उसके भीतर निवास करते हैं) । 3. वेतन सफिल, जालंधर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान आय-कर अधिकारी, चंडीगढ़, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, | | जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तर्गत हो गया हो वहां उस आय-कर सफिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख से उस रेंज के, जिसकी उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी, जो उनके सबंध में कार्यवाही करेंगे । जहां सभी सफिल, वार्ड और जिले जिनका किसी स्थान विशेष पर मुख्यालय है, सहायक आयुक्त (अपील) को समनुदेशित कर दिए गए हैं, वहां वह भ्रम समाप्त हो गए, उन मुख्यालयों पर सफिल, वार्ड और जिला की बाबत भी अधिकारिता रखेगा । यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1973 से प्रवृत्त होगी । [सं० 273 (फा० नं० 261/4/73-आई० टी० जे०)] |
| | | स्पष्टीकारक टिप्पण : | |
| | | यह संशोधन "ख" रेंज रोहतक के उत्पादन और सहायक आयुक्तों (अपील) में कार्य के पुनःआवटन के कारण आवश्यक हो गया है । | |
| | | New Delhi, the 29th January, 1973 | |
| | | S. O. 1604— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax of Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof : | |
| | | SCHEDULE | |
| | | Range | Income-tax Circles, Wards and Districts |
| | | (1) | (2) |
| | | 1. Amritsar Range | 1. All Income-tax Circles, Wards or Districts which had or have their headquarters at Amritsar other than those mentioned in column 2 against Appellate Assistant Commissioners of Income-tax, Jammu and Central Range, Amritsar. |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|----------------------------|---|-------------------|--|
| 2. Central Range, Amritsar | <p>2. Salary Circle, Jullundur [in respect of persons who reside in the jurisdiction of Districts I (excluding District I (viii) to I (xiv), II and III, Amritsar].</p> <p>1. All Central Circles which have or had their headquarters at Amritsar, Ambala, Srinagar and Central Circle-VIII, New Delhi.</p> <p>2. Special Survey Circle, Amritsar upto and including 14-7-1967 (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Central Circles I, II, III, (Amritsar).</p> <p>3. Special Survey Circle, Patiala upto and including 14-7-1967 (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Central Circle, Ambala).</p> <p>4. Salary Circle, Jullundur upto and including 14-7-1967 (in respect of persons who reside in the jurisdiction of Central Circles, I, II, III, Amritsar).</p> | 6. Ludhiana Range | <p>2. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Pathankot and Gurudaspur.</p> <p>3. Salary Circle, Jullundur [in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of the Income-tax Officers, Pathankot, Gurudaspur and District I (viii) to I (xiv), Amritsar].</p> <p>1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—</p> <p>(i) Ludhiana (except Central Circles, Ludhiana) (ii) Abohar (iii) Moga (iv) Ferozepur and (v) Khanna.</p> <p>2. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Ludhiana (except Central Circles, Ludhiana), Abohar, Moga, Ferozepur and Khanna).</p> <p>3. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Ludhiana (except Central Circles, Ludhiana, Abohar, Moga, Ferozepur and Khanna).</p> |
| 3. Ambala Range | <p>All Income-tax Circles, Wards and Districts having headquarters at :—</p> <p>(i) Ambala (ii) Sonapat (iii) Karnal (iv) Yamuna Nagar (v) Simla (vi) Panipat.</p> | 7. Patiala Range | <p>1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—</p> <p>(i) Patiala (ii) Sangrur (iii) Malerkotla (iv) Barnala (v) Bhatinda (vi) Chandigarh (provided that the jurisdiction in respect of the orders passed by the I.T.O. Collection Ward, Chandigarh in respect of the assessee of Hoshiarpur Circles would be with the A.A.C. of Income-tax holding jurisdiction over Hoshiarpur).</p> <p>2. Special Survey Circle, Patiala (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Chandigarh, Patiala, Sangrur, Malerkotla, Barnala and Bhatinda).</p> <p>3. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers Chandigarh, Patiala, Sangrur, Malerkotla, Barnala and Bhatinda).</p> |
| 4. Jullundur Range | <p>1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—</p> <p>(i) Jullundur (ii) Hoshiarpur (iii) Batala (iv) Collection Ward, Chandigarh in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officer, Hoshiarpur.</p> <p>2. Central Circles having headquarters at Ludhiana.</p> <p>3. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Jullundur, Batala, Hoshiarpur and Central Circles, Ludhiana).</p> <p>4. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Jullundur, Batala and Hoshiarpur).</p> | 8. Rohtak Range | <p>All Income-tax Circles, Wards and Districts having headquarters at :—</p> <p>(i) Rohtak (ii) Faridabad (iii) Hissar (iv) Sirsa (v) Gurgaon (vi) Rewari (vii) Narnaul (viii) Jind.</p> |
| 5. Jammu Range | <p>1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—</p> <p>(i) Jammu (ii) Srinagar (except Central Circle Srinagar) (iii) Income-tax Circle, Chamba, Kangra, Hamirpur & Una Districts at Pathankot (iv) Pathankot (v) Gurudaspur (vi) Mandi (vii) Districts I (viii) to I (xiv), Amritsar.</p> | | |

Where an Income-tax Circle, Ward and District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all Circles, Wards and Districts having Headquarters at a particular place have been assigned to an Appellate Asstt. Commissioner, he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and Districts at those headquarters since abolished also.

This Notification shall take effect from 1st February, 1973,
[No. 273 (F.No. 261/4/73- I T J)]

Explanatory Note :

The amendment has become necessary consequent upon the abolition of 'B' Range Rohtak and re-allocation of the work amongst the Appellate Assistant Commissioners.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1973

आ० का० 1605 -- आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं० 123 (फा० सं० 261/9/72-आई टी० जे०) तारीख 26 जून, 1972 का प्रांशिक रूपांतरण करते हुए निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सफिलों, वार्डों और जिलों में आय-कर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :-

अनुसूची

| क्रम सं० | रेंज | आय-कर वार्ड/सफिल और जिला |
|----------|-----------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 21. | ड० रेंज, मुम्बई | 1. आय-कर अधिकारी के प्रभाराधीन 1 से 3 तक को छोड़कर छ-वार्ड 2. आय-कर अधिकारी के प्रभाराधीन 1, 2, 8 और 9 को छोड़कर छ-वार्ड 3. आय-कर अधिकारी के प्रभाराधीन 1, 2, 3, 6 और 10 को छोड़कर सी०एस०डी० (पूर्व) । |
| 24. | छ-रेंज, मुम्बई | 1. आयकर अधिकारी के प्रभाराधीन 1 से 9 को छोड़कर ड० वार्ड 2. आयकर अधिकारी के प्रभाराधीन 1, 2, 3, 4 और 9 को छोड़कर सी०एस०डी० (पश्चिम) । |

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलों, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष सम्बन्ध थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके संबंध में कार्यवाही करेंगे।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं०. 281 (फा० सं०. 261/5/73- आई. टी. जे.)]

के० प्रार० रायबन, सचिव

स्पष्टीकारक दिव्यण

यह संशोधन आयुक्त के प्रभार के भीतर एक नए रेंज, उदाहरणतया छ-रेंज के सृजन के परिणाम स्वरूप आवश्यक हो गया है।

New Delhi, the 30th January, 1973

S. O. 1605. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of the Boards, Notification No. 123 (F.No. 261/9/72-ITJ) dated the 26th June, 1972 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to income-tax or super tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof

SCHEDULE

| Sl. No. | Range | Income-tax Circle, Ward and District. |
|---------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21. | E Range, Bombay | 1. G-Ward except 1st to 3rd ITOs Charges. 2. GA-Ward except 1st, 2nd 8th and 9th ITOs Charges, 3. B.S.D.(East) except 1st, 2nd 3rd, 6th and 10th ITOs Charges. |
| 24. | G-Range, Bombay | 1. E-Ward except 1st to 9th ITOs Charges. 2. B.S.D.(West) except 1st, 2nd 3rd, 4th and 9th ITOs Charges. |

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioners of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1st February 1973.

[No. 281(F. No. 261/5/73-ITJ)]

Explanatory Note :

The amendment has become necessary consequent on creation of a new range, viz., G. Range, within the Commissioner's charge.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1973

का. आ. 1606.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसके समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं. 95 (फा. सं. 261/6/72-आई. टी. जे.) तारीख 29 मई, 1972, अधिसूचना सं. 250 (फा. सं. 261/6/72-आई. टी. जे.) तारीख 28-12-1972 द्वारा यथासंशोधित, से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

उक्त अनुसूची में स्तंभ (1) के अन्तर्गत 'क' रेंज कांयम्बटूर, 'ख' रेंज कांयम्बटूर तथा स्तंभ 2 के अन्तर्गत उनके सामने उल्लिखित आयकर सर्किल, वार्ड और जिले लुप्त कर दिए जाएंगे और निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

- | | |
|-----------------------------|---|
| कांयम्बटूर रेंज, कांयम्बटूर | 1. कांयम्बटूर सर्किल |
| | 2. विरोध सर्वेक्षण सर्किल, कांयम्बटूर |
| | 3. उटाकमण्ड सर्किल (सभी अनुभाग) |
| | 4. सम्पदा शुल्क एवं आयकर सर्किल कांयम्बटूर |
| | 5. अतिरिक्त लाभ कर सर्किल, कांयम्बटूर और इरोड |
| | 6. सर्किल 1, कांयम्बटूर |
| | 7. नगर सर्किल 1 (सभी अनुभाग) कांयम्बटूर |
| | 8. इरोड सर्किल (सभी अनुभाग) |
| | 9. कम्पनी सर्किल 3 और 4, कांयम्बटूर |
| | 10. सर्किल 2, कांयम्बटूर |
| | 11. नगर सर्किल 2, (सभी अनुभाग) कांयम्बटूर |
| | 12. वंनन सर्किल, कांयम्बटूर |
| | 13. पॉलेथी सर्किल (सभी अनुभाग) |
| | 14. तिरुपुर सर्किल |

यह अधिसूचना पहली मार्च 1973 से प्रभावी होगी।

[सं. 309 (फा. सं. 261/3/73-आई. टी. जे.)]

सी. बी. पदमानाभन, अवर सचिव

स्पष्टीकरण टिप्पण:—

यह संशोधन, सहायक आयुक्त (अपील), 'ख' रेंज कांयम्बटूर के पद के उत्पादन पर और सहायक आयुक्त (अपील) के रेंज के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप आवश्यक हो गया है।

New Delhi, the 28th February, 1973

S.O. 1606.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following

amendments in the Schedule appended to its Notification No. 95 (F. No. 261/6/72-ITJ) dated the 29th May, 1972 as amended by Notification No. 250 (F. No. 261/6/72-ITJ) dated 28th December, 1972, namely:

In the said Schedule under column (1), 'A' Range Coimbatore and 'B' Range Coimbatore and under column (2), the Income-tax Circles, Wards and Districts noted there against shall be deleted and following shall be substituted: namely:—

Coimbatore Range,
Coimbatore.

1. Coimbatore Circle.
2. Special Survey Circle, Coimbatore.
3. Ootacamund Circle (all Sections).
4. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Coimbatore.
5. Excess profits Tax Circles, Coimbatore and Erode.
6. Circle I, Coimbatore.
7. City Circle I (all Sections), Coimbatore.
8. Erode Circle (all Sections).
9. Company Circles III and IV, Coimbatore.
10. Circle II, Coimbatore.
11. City Circle II (all Sections), Coimbatore.
12. Salary Circle, Coimbatore.
13. Pollachi Circle (all Sections)
14. Tirupur Circle.

This Notification shall take effect from 1st March, 1973.

[No. 309 (F. No. 261/3/73-ITJ)]

C. V. PADMANABHAN, Under Secy.

Explanatory Note

This amendment has become necessary consequent on the abolition of the office of the Appellate Assistant Commissioner, B-Range, Coimbatore and reorganisation of the Appellate Assistant Commissioners Ranges.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1973

का. आ. 1607.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं. 217 [फा. सं. 185/61/72-आई. टी. (ए. आई.)], तारीख 10-11-1972 को निम्न प्रकार से उपांतरित करता है:—

क. सं. 61 के सामने, स्तंभ 6 के अन्तर्गत आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल 2, कलकत्ता के स्थान पर आयकर आयुक्त, दिल्ली 1, नई दिल्ली पड़े।

[सं. 2 (फा. सं. 185/61/72-आई. टी. (ए. आई.))]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th April, 1973

S.O. 1608.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby modifies its notification No. 217 [F. No. 185/61/72-IT(AI)], dated 10-11-1972 as under:—

Against S. No. 61, under column 6 for the Commissioner of Income-tax, West Bengal II, Calcutta read The Commissioner of Income-tax, Delhi I, New Delhi.

[No. 2 F. No. 185/61/72-IT(AI)]

नई दिल्ली 19 अप्रैल, 1973

(राजस्व और धीमा विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1973

आयकर

क्रा० आ० 1609 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित आयकर अधिकारी को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित कृत्यों का पालन करने के लिए निर्देश देता है।

अनुसूची

| आयकर अधिकारियों के पदाभिधान | कृत्य |
|--|---|
| प्रथम आयकर अधिकारी, वेतन-संश्लि 2, मद्रास। | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के अधीन कृत्यों का पालन करना और ऐसे नियोजकों, से विवरणियों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना, जो अपने इन कर्मचारियों या निर्देशकों, प्रबन्ध निर्देशकों, प्रबन्धकों, सचिवों और कोष-पाला, आदि को वेतनों का सदाय करने के लिए उत्तरदायी है, जिनके कार्यालय मद्रास नगर में और चिंगलपेट जिले के सैदापेट, श्रीपेराम्बुदुर, त्रिवेल्लोर और पोन्नरी के राजस्व ताल्लुको में स्थित है, और जो उन कर्मचारियों के मामले से भिन्न है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 126 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आते हैं। |

2. यह अधिसूचना 1 मई, 1973 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 3- फा० सं० 187/4/73-आई०, टी० (ए० आई०)]

बी० बी० श्रीनिवासन अवग्रमचिक्

New Delhi, the 19th April, 1973

S.O.1609.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby directs the Income-tax Officer mentioned in column (1) of the Schedule to perform the functions mentioned in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

| Designation of the Income-tax Officers | Functions |
|---|--|
| 1st Income tax Officer, Salaries Circle II, Madras. | To perform the functions under Section 206 of the Income-tax Act, 1961 and to call for and receive the returns from the employers responsible for paying salaries to their employees or directors, managing directors, Managers, Secretaries and treasurers, etc., whose offices are situated in the City of Madras and the revenue taluks of Saidapet, Sriperumbudur, Trivellore and Ponneri of Chingleput District other than the cases of employees covered by the notification issued under Section 126 of the Income-tax Act, 1961. |

2. This Notification shall take effect from the 1st of May 1973.

[No. 3—F. No. 187/4/73-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

क्रा. आ. 1610.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर. एस. निगम को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर बसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2. अधिसूचना सं. 255 (फा. सं. 404/131/71-आई. टी. सी. सी.) तारीख 27 अगस्त, 1971 द्वारा की गई श्री के. प्रसाद की नियुक्ति 15 मई, 1973 से रद्द की जाती है।

यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 340 (फा. सं. 404/130/73-आई. टी. सी. सी.)]

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 30th April, 1973

INCOME-TAX

S.O. 1610.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri R. S. Nigam who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri K. Prasad made in Notification No. 255 (F. No. 404/131/71-ITCC) dated 27th August, 1971 is cancelled with effect from 15th May, 1973.

3. This Notification shall come into force with effect from 15th May, 1973.

[No. 340 (F. No. 404/130/73-ITCC)]

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

क्रा. आ. 1611.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री एस. भाष्यम को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर-बसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2. श्री वी. द्रवियम की अधिसूचना सं. 174 (फा. सं. 404/291/72-आई टी सी सी), तारीख 4 सितम्बर, 1972 के अन्तर्गत की गई नियुक्ति 15-5-73 से रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना 15 मई, 1973 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 347 (फा. सं. 404/138/73-आई. टी. सी. सी.)]

एम. एन. नाम्बियार, अवग्रमचिक्

New Delhi, the 10th May, 1973

S.O. 1611.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri S. Bashyam who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri V. Draviam made under Notification No. 174 (F. No. 404/291/72-ITCC) dated the 4th September, 1972 is cancelled with effect from 15-5-1973.

3. This Notification shall come into force with effect from 15-5-1973

[No. 347 (F. No. 404/138/73-ITCC)]

M. N. NAMBIAR, Under Secy

नई दिल्ली, 30 मई, 1973

बीमा

का. आ. 1612.—विश्व बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विस्तृत मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 771 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1972 में निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में, स्तम्भ (2) में, धारा 64-य ड से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि को मद (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद के पहले निम्नीलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के उपखण्ड (झ) में मद (क) के पश्चात्, निम्नीलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(कक) 31 मई, 1970 से पूर्व किसी भी समय सर्वेक्षण या हानि निर्धारण-काम किया हो, चाहे ऐसे सर्वेक्षण या हानि-निर्धारण-काम की रिपोर्ट ऐसे आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित हो या न हो

[फा. सं. 56(60)-बीमा-1/71]

राम प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 1973

INSURANCE

S.O. 1612.—In exercise of the powers conferred by section 35 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 771 (E), dated the 29th December, 1972, namely :—

In the Table below the said notification, in column (2) the existing entry relating to section 64UM shall be numbered as item (2), and before the item as so numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“(1) In sub-section (1), in clause (D), in sub-clause (i), after item (a), the following item shall be inserted, namely :—

“(aa) has carried out survey or loss assessment work at any time prior to the 31st May, 1970 whether or not the report of such survey or loss assessment work was signed by such applicant;”.

[F. No 56(60)-Ins. 1/71]

RAM PARKASH, Under Secy.

शुद्धी-पत्र

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1972

का. आ. 1613.—इस कार्यालय की ऊपर बताई गई अधिसूचना की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त अधिसूचना में बताए गये तैयार व परीक्षित खाद्य पदार्थ वाले मद के स्थान पर जिनका उल्लेख स्तंभ 3 में क्रम सं. 1 से लेकर 19 तक किया गया है, स्तंभ 4 में, क्रम संख्या 2 के सामने “धातु अन्तर्वेष्टक” जोड़ दिया जाए।

ए. एस. आई. जाफर, समाहर्ता

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th December, 1972

S.O. 1613.—Attention is invited to this Office Notification cited above. In the said notification the words ‘Metal Containers’ may be added in Col. 4 against S. No. 2 for items of Prepared or Preserved foods noted in Sl. No. 1 to 19 of Column 3.

A. S. I. JAFFAR, Collector.

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय
शिलांग, 20 जनवरी, 1973

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का. आ. 1614.—केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम 1944 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा इस समाहर्ता-कार्यालय के केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के सहायक समाहर्ता तथा उससे ऊपर के ऑफिस के अधिकारियों को, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम 1944 के नियम 173(एल) के अधीन समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

[सं. 1/के. उ. शु./73]

एच. आर. साईम, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISEShillong, the 29th January, 1973
CENTRAL EXCISE

S.O. 1614.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise Officers of and above the rank of an Assistant Collector of Central Excise of this Collectorate, to exercise within their respective jurisdictions, the powers of the Collector under Rule 173(L) of the Central Excise Rules, 1944.

[No. 1/CE/73].

H. R. SYIEM, Collector

बम्बई, 18 अप्रैल, 1973

का० आ० 1615.— 1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम-वली के पाँचवें नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, तथा दिनांक 14 फरवरी, 1968 की, इस समाहर्ता कार्यालय की अधिसूचना संख्या सी० ई० आर० 5/1/68 के अधीन संशोधित समाहर्ता कार्यालय की दिनांक 20/26 अप्रैल 1967 की अधिसूचना संख्या सी० ई० आर० 5/1/67 का आंशिक संशोधन करते हुए, मैं अनुलग्न सारणी के स्तंभ 3 में उल्लिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को, समाहर्तालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई के अन्तर्गत उनके अपने अधिकार क्षेत्र में, स्तंभ 2 में बताई गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अन्तर्गत, उक्त सारणी के स्तंभ 4 में दी गई सीमाओं तक समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार देता हूँ।

क्रम सं. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम अधिकारियों का पद सीमाएँ, यदि कोई हों

| | | |
|--------------|------------------------------------|--|
| 1. 191-ए (2) | सहायक समाहर्ता, | अभिनिर्माण सूत्र के अनुमोदन के अधिकार को छोड़कर, |
| (3) (4) | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसके अधि- | जिसका प्रयोग उपसमाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई द्वारा किया जाएगा। |
| और (5) | कार क्षेत्र में वह कारखाना है। | |
| 2. 191-ए (7) | -यथोपरि | 3 महीने की ऐसी अवधि बहाने से सम्बंधित अधिकार को छोड़कर, जिसके दौरान उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ अभिनिसंशुधाला से, 191-क नियम के अधीन, पंजीकृत प्राप्तकर्ता कारखानों को भेजी जाती हैं। |

[सं. सी० ई० आर० 5/1/1973]

बी० एस० चावला, समाहर्ता

Bombay, the 18th April, 1973

CENTRAL EXCISE

S. O. 1615.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 and in partial modification of this Collectorate Notification No. CER/5/1/1967 dated the 20th/26th April, 1967 as modified under Collectorate Notification No. CER/5/1/1968 dated the 14th February, 1968, I empower the Central Excise Officers specified in Column 3 of the sub-joined Table to exercise within the jurisdiction of the Bombay Central Excise Collectorate, the powers of the Collector under the Central Excise Rules enumerated in column No. 2 thereof, subject to the limitations set out in column 4 of the said table.

| Sr. No. | Central Excise Rules | Rank of Officer | Limitations, if any. |
|---------|-------------------------|---|--|
| 1. | 191-A(2)(3) (4) and (5) | Assistant Collector of Central Excise having jurisdiction over the factory. | Except in regard to the approval of the manufacturing formulae, which power shall be exercised by the Deputy Collector of Central Excise, Bombay. |
| 2. | 191-A(7) | Do. | Except the power to extend the period of three months within which the excisable goods are to be conveyed from the manufacturing factory to the receiving factory registered under Rule 191-A. |

[No. CER/5/1/1973]

B. S. CHAWLA, Collector

पूना, 14 अप्रैल, 1973

का० प्रा० 1616.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 173 ज के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा कर दिये हुए माल को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए फैक्टरी या मालगोदाम में रखने या लाने के लिए, इस समाहृतियों की 12-2-1968 की अधिसूचना सं० के० उ० नि० 4/68 के अधिक्रमण में संलग्न परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित क्रियाविधि विहित करता हूँ, जिस का पालन 14 जुलाई 1969 की भारत सरकार की अधिसूचना सं० 182/69 के० उ० द्वारा यथाप्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम 1944 के अध्याय 7 'क' में निर्धारित स्वयम्निकासी पद्धति के अधीन काम करने वाले प्रत्येक निर्धारित द्वारा किया जाएगा :-

- (क) फैक्टरी में अन्य चीजों के निर्माण में उपयोग करने के लिए प्राप्त/रख लिया गया माल; अथवा
- (ख) दोबारा बनाने, परिष्कृत करने, सुधार करने, दुबस्त करने या इसी प्रकार के अन्य किसी काम के लिए फैक्टरी में वापस लिया गया माल; अथवा
- (ग) जबकि ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिन पर निर्धारित का नियंत्रण नहीं हो सकता, शुल्क भरा कर देने के बाव भी माल भेजा न जा सकता हो, जैसे रेलवे पर बुकिंग स्वगित हो जाना, रेलवे बैगन उपलब्ध न होना या बाह्य खराब हो जाना; अथवा
- (घ) जब परीक्षण के लिए या डिजाइनों या निर्माण की पद्धति का अध्ययन करने के लिए माल की आवश्यकता हो; अथवा
- (ण) जब खुदरा बिक्री या मानार्थ भेंट के रूप में भेजने या भ्रमण भ्रमण ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक दोबारा पैक करने के लिए माल को फैक्टरी परिसर में स्टोर करने की आवश्यकता हो ।

परिशिष्ट 'क'

(क) फैक्टरी में अन्य चीजों के निर्माण में उपयोग करने के लिए प्राप्त/रख लिया गया माल :-

- (1) निर्धारित शुल्क दिए हुए माल को फैक्टरी में रखने के चौबीस घंटे के अंदर उसकी सूचना फैक्टरी पर क्षेत्राधिकार रखनेवाले केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक को, संलग्न प्रपत्र में लिखित रूप में देना, और उसकी एक प्रति संबंधित सहायक समाहर्ता को भेजेगा ।
- (2) अगर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कोई अधिकारी निरीक्षण/जांच के लिए भेजा गया हो, तो माल और शुल्क जमा करने के कागजपत्र उसे दिखाये जाने चाहिए ।
- (3) निर्धारित रख लिए गए/प्राप्त, निपटारे गए माल का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में रखेगा ।
- (4) इस प्रकार का माल शुल्क न दिये हुए माल से अलग स्टोर किया जाना चाहिए और स्टोर करने का यह स्थान शुल्क न दिये हुए माल के लिए बने हुए बंद स्टोर रूम से बिल्कुल अलग होना चाहिए ।

प्रपत्र

फैक्टरी में उपयोग के लिए फैक्टरी परिसर में प्राप्त/रखे गये, शुल्क दिये हुए माल का हिसाब

फैक्टरी का नाम

पता

लाइसेंस नंबर

माल का वितरण

प्राप्तियाँ

| तारीख | माल जमा | फैक्टरी का नाम जहाँ से प्राप्त हुआ | कागजातों की संख्या और तारीख | मात्रा | योग | निर्माता के हस्ताक्षर |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| निर्गम | | माल बाकी | | निर्माता के हस्ताक्षर | | अभ्युक्ति |
| कागजातों की संख्या और तारीख | | मात्रा | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |

टिप्पणी—हर किस्म के माल के लिए अलग अलग हिमाब रखा जाना चाहिये ।

- (5) भंडारों और हिसाब की जांच कोई भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी किसी भी समय कर सकेगा ।

(ख) दोबारा बनाने, परिष्कृत करने, सुधार करने, दुबस्त करने या इसी प्रकार के अन्य किसी काम के लिए फैक्टरी में वापस किया गया माल :-

(i) जब बिजली के पंखों, इलेक्ट्रिक बैटरियों, बिजली के बल्बों, टायरों तथा द्यूबों, आई-सी-इंजनों, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन्स्यूलर सीटों, रेफ्रिजरेटिंग तथा एयर कंडीशनिंग के सामानों, सीमेंट, ऊनी कपड़ों और चीनी के सिवाय अन्य द्रव्यशुल्कमाल दोबारा बनाने, परिष्कृत करने,

सुधार करने या इसी प्रकार के अन्य किसी काम के लिए फैक्टरी में वापस किया गया हो ।

- (i) निर्धारित अपनी फैक्टरी में माल प्राप्त होने के चौबीस घंटे के अंदर फैक्टरी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक को, संलग्न प्रपत्र में लिखित रूप में उसकी सूचना देगा । और उसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता को भेजेगा ।
- (ii) दोबारा बनने, परिष्कृत होने, सुधारने अथवा दुरुस्त होने तक वह माल बन्द स्टोर रूम से दूर अलग ही रखा जाएगा ।
- (iii) यदि केन्द्रीय उत्पादशुल्क का कोई अधिवारी निरीक्षण/जांच के लिए भेजा जाए, तो माल और शुल्क जमा करने से संबंधित कागजात निरीक्षण/जांच के लिए उसे दिखाए जाने चाहिये ।
- (iv) इस मास को दोबारा प्रसंस्कृत करने, दोबारा बनाने, परिष्कृत करने, सुधारने, दुरुस्त करने या इसी प्रकार की किसी अन्य प्रतिक्रिया के अंतर्गत खाने के काम को नया माल बनाने के काम से अलग ही रखना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में ऐसे माल को नये माल के उत्पादन के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए ।
- (v) यदि ऐसे माल के पुनः प्रसंस्करण, पुनर्निर्माण और दुरुस्ती आदि के लिए किसी ऐसे सघटक (कंपोनेन्ट) की आवश्यकता हो, जिन पर शुल्क लगता है, तो दुरुस्ती, दोबारा बनाने आदि के लिए माल लेने से पहले उन सघटकों (कंपोनेन्ट) का शुल्क हमेशा की तरह जमा कर दिया जाना चाहिए ।
- (vi) इस प्रकार का दोबारा प्रसंस्कृत, दोबारा बना माल, बन्द स्टोर रूम में रखे शुल्क न दिये हुए माल से अलग ही रखा जाना चाहिए ।
- (vii) दुरुस्ती, सुधार वाले दत्तशुल्क माल के लिए बने हुए गेट पास कर सबसे ऊपर इस प्रकार प्रमुखता से लिखा रहना चाहिए—“दुरुस्त किये गए दोबारा प्रसंस्कृत मास का दोबारा निर्गम ।”
- (viii) प्राप्त हुआ इस प्रकार का मास, फैक्टरी में वापस होने के बाद माल का प्रसंस्करण तथा प्रसंस्करण, दोबारा बनाने के बाद उपलब्ध मात्रा आदि का विस्तृत विवरण निर्धारित द्वारा अनुलग्न प्रपत्र में रखा जाएगा ।

केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम 1944 के नियम 173 ज के अधीन दोबारा प्रसंस्करण, दोबारा बनने, दुरुस्ती आदि के लिए प्राप्त दत्तशुल्क माल का विवरण

फैक्टरी का नाम और पता
साईसेस नं०

| प्राप्तियां | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|---|
| फैक्टरी में कहाँ से प्राप्त | माल का पहचान के | प्राप्त | निर्धारित | | |
| प्राप्त होने | हुआ | ध्वज निशान सहित | मात्रा | या उसके | |
| की तारीख | | ब्रांड का नाम | | अधिकर्ता | |
| | | या सख्या | | के हस्ताक्षर | |
| | | यदि कोई | | | |
| | | हो | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

पुनः प्रसंस्करण/दुरुस्ती के व्यौरे

| | | | | |
|--|---|---|---|----|
| ऐसे माल को दोबारा प्रसंस्करण यदि किसी ऐसे सघटकों (कम्पा- दोबारा प्रसंस्कृत के बाद उपलब्ध सघटक (कम्पो- करने, दोबारा मात्रा नेन्ट) कम प्रयोग वाले शुल्क की बनाने, दुरुस्त हुआ है जिस पर राशि और गेट करने आदि के उत्पाद-शुल्क पास की संख्या व्यौरे लगता है, तो और तारीख उसका व्यौरे | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---|----|

निर्गम

| तारीख | गेट पास | मात्रा | अभ्युक्ति निर्धारित या | शुल्क की | अभ्युक्ति |
|-------|---------|--------|------------------------|-----------|-----------|
| | की | | उसके अभि- वापसी यदि | | |
| | सख्या | | कर्ता के | कोई की | |
| | और | | हस्ताक्षर | गयी हो तो | |
| | तारीख | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | 17 |

टिप्पणी .—(i) हिमाय, रूपेश रखा जाना चाहिए ।

(ii) खराब चीनी/सीमेन्ट के मामले में अगर भिन्न भिन्न मात्रा के अनुसार निशुल्क निकासी की पद्धति अपनाई गयी हो तो कालम 8 में संशोधन करके उसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सूचित निशुल्क प्रेषण के लिए स्वीकृत मात्रा ।'

(ix) इस प्रकार रखे गये अभिलेख तथा संबंधित कागजातों की किसी भी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है ।

(x) यदि निर्माता फैक्टरी में प्राप्त दत्त-शुल्क माल अलग से प्रसंस्कृत करके या दोबारा बनाकर और उसके प्रसंस्करण, पुनर्निर्माण के बाद उसे बिना शुल्क बाहर भेजना चाहता हो, तो उसे उपर्युक्त क्रियाविधि अपनानी चाहिए । किन्तु यदि निर्माता उपर्युक्त क्रियाविधि नहीं अपना सकता, तो वह ऐसे माल को पुनः प्रसंस्करण, पुनर्निर्माण आदि के साथ केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम 1944 के 173 'ठ' या 100 के अधीन निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार शुल्क की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है ।

II. परिष्करण, प्रसंस्करण आदि के लिए फैक्टरी में वापस लाई गई खराब चीनी/सीमेन्ट

(1) माल फैक्टरी में मिलने के चौबीस घंटे के अंदर निर्धारित फैक्टरी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक को, संलग्न प्रपत्र में लिखित रूप में सूचित करेगा और उस की एक प्रति केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता को भेजेगा ।

(2) जब तक खेप की केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी द्वारा जांच नहीं कर ली जाती, तब तक उसे अलग ही रखा जाएगा ।

(3) इस उद्देश्य से भेजा गया केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी फैक्टरी में आए हुए माल का वजन करेगा, माल का नमूना लेगा, सामान्य टेस्ट-मेंमो तैयार करेगा, और उपलब्ध होने योग्य चीनी/सीमेन्ट का पता लगाने के लिए वह नमूना रसायनिक परीक्षक के पास भेजेगा ।

- (4) रसायनिक परीक्षक से टेस्ट-रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादशुल्क के सञ्चालक अधीक्षक को यह सूचित करेगा कि उस फैक्टरी में लाए गए खराब माल के बदले में कितना माल निशुल्क बाहर भेजने की अनुमति देनी है।
- (5) सहायक समाहर्ता से आदेश प्राप्त हो जाने पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क का संबंधित अधीक्षक निर्धारित की रसायनिक विश्लेषण के परिणाम की सूचना देगा, और रसायनिक परीक्षक द्वारा निश्चिन की गई उपलब्ध होने योग्य मात्रा के बराबर माल निशुल्क बाहर भेजने की अनुमति देगा।
- (6) पुनः प्रस्तुत मात्रा का हिसाब केन्द्रीय उत्पादशुल्क के दाते में दिया जाना चाहिए।
- (7) चीनी/सीमेन्ट के ऐसे निशुल्क निकाल के लिए बनाये जाने वाले गेट पास पर सबसे ऊपर इस प्रकार प्रमुखता से लिखा जाए "अधीक्षक के आदेश सख्त। . . . तारीख . . . के अन्तर्गत बिना शुल्क निकासी के लिए"
- (8) निर्धारित फैक्टरी में प्राप्त खराब चीनी/सीमेन्ट और फैक्टरी में उसके प्रसंस्करण का विस्तृत विवरण ऊपर (ख) (i) (viii) में उल्लिखित प्रपत्र में संरक्षित। जिसकी जाच कोई भी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी हर समय कर सकेगा। यह हिसाब केन्द्रीय उत्पादशुल्क के हिसाब के अतिरिक्त होगा।

(III) दुर्घटन करने, सुधारने आदि के लिए फैक्टरी में लाये गये इलेक्ट्रिक बैटरियां, पक्के बिजली के बल्ब, टायर तथा ट्यूब, आई०सी० छजन, बिजली की मोटरों, डब्ल्यू०आर०सेट, रेफ्रिजरेटिंग तथा एयर कंडीशनिंग के सामान।

- (1) निर्धारित, फैक्टरी में माल प्राप्त होने के चौबीस घंटे के अन्दर उसकी सूचना फैक्टरी पर क्षेत्राधिकार रखनेवाले केन्द्रीय उत्पादशुल्क के अधीक्षक को, सलग्न प्रपत्र में लिखित रूप में देगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता को भेजेगा।
- (2) इस प्रकार प्राप्त माल इस उद्देश्य से निश्चिन किसी अलग जगह में जमा किया जाएगा। और दुर्घटनी, सुधार आदि का काम जहां तक हो सके, किसी अलग भाग में किया जाएगा जो उत्पादन करने वाले खंड से अलग होगा। जब कभी भी यह कार्य उत्पादन करने वाले भाग में ही किया जाय, तब उसकी पूर्वसूचना केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित अधीक्षक को दी जानी चाहिए।
- (3) दुर्घटनी, सुधार आदि के लिए उपयोग में आने वाले शुल्क देने योग्य माल का शुल्क निर्धारित उन्हें ले जाते समय और दुर्घटनी के लिए उनका उपयोग करने से पहले ही दे देगा जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है।
- (4) दुर्घटन किये गये/सुधारे गये सभी माल को भेजने का काम इस उद्देश्य से रखे गये भिन्न गेट पास के जरिए किया जाना चाहिए, जिस पर सबसे ऊपर प्रमुख रूप से यह लिखा रहेगा, "दुर्घटन किए गए/द्वारा प्रस्तुत वस्तु शुल्क माल का बाहर निकाल"।
- (5) निर्धारित वापस किये गये माल का एक विस्तृत विवरण उपर्युक्त प्रपत्र (ख) (i) (viii) में रहेगा।
- (6) निर्माता फैक्टरी में माल प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर उस माल से दुर्घटनी/सुधार करके उसे भेज देगा। समय की यह अवधि केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक

द्वारा तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगी। बशर्तें दुर्घटनी/सुधार के लिए फैक्टरी में लायी गयी ऐसी बैटरियों, पक्के आदि की संख्या किसी भी एक समय निर्धारित की वार्षिक उत्पादन के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस सीमा का बिजली की मोटरों, बिजली की बैटरियों और बिजली के पक्के के लिए 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटिंग तथा एयरकंडीशनिंग के सामानों, बिजली की मोटरों, आई०सी० छजन, बिजली के पक्के तथा बिजली की बैटरियों के सञ्चय में उन्हें भेजने की सामान्य अवधि एक मास के बन्ने तीन मास की होगी। उचित मामलों में उसे नौ मास तक बढ़ाने की अनुमति अधीक्षक द्वारा और उससे आगे बढ़ाने की अनुमति समाहर्ता द्वारा दी जाएगी।

(IV) नियम 173 ठ और 173 ड तथा 100 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत द्वारा बनाने, परिष्कृत करने, सुधारने के लिए फैक्टरी में वापस किया गया माल।

(1) निर्धारित की संचालित नियमों में निर्धारित और समय समय पर विहित क्रियाविधि का पालन करना चाहिये और संबंधित नियमों के अधीन निर्धारित क्रियाविधि के अधीन पहल से ही विहित विवरण के अतिरिक्त ऊपर (ख) (1) (VIII) में उल्लिखित प्रपत्र में इस प्रकार प्राप्त माल, उस पर किया गया प्रसंस्करण और उसे ले आने आदि के बारे में उसे एक विवरण रखना चाहिये। सीमेन्ट और चीनी के बारे में संबंधित नियमों के अधीन निर्धारित क्रियाविधि के अतिरिक्त ऊपर (II) के अधीन निर्धारित क्रियाविधि भी अपनायी जानी चाहिये। ऊनी कपड़ों के मामले में नियम 173 ज की व्यवस्थाओं के अधीन शुल्क दिये हुए कपड़ों के पुनः प्रसंस्करण की अनुमति नहीं दी जाएगी। किन्तु केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम 1914 के नियम 173 ठ की व्यवस्थाओं के अधीन ऐसे कपड़ों के पुनः प्रसंस्करणों की अनुमति दी जाएगी।

(ग) (I) जब कि ऐसी परिस्थितियों के कारण, जिनसे निर्धारित की नियंत्रण नहीं हो सकता, शुल्क अदा कर देने के बाद भी माल न भेजा जा सकता हो जैसे रेलवे पर बूकंग स्वयंसेवक हो जाना, रेलवे बैगन उपलब्ध न होना या बाह्य खराब हो जाना।

(1) फैक्टरी में जिस माल पर इस प्रकार का शुल्क दिया हुआ माल रखा जाएगा, उसे निर्माण का लाइसेंस जारी करने या लाइसेंस के नवीकरण के लिए लक्ष्य अधिकारी द्वारा यथाविधि घोषित और अनुमानित किया जाएगा।

(2) ऐसे माल को स्टोर करने का स्वयंसेवक पर उन सभी मामलों में अर्थ होना चाहिए, जहां शुल्क न दिये हुए माल का निर्माण होता है, या जहां ऐसा माल स्टोर कर के रखा जाता है।

(3) निर्धारित की चाहिए कि वह फैक्टरी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक का सलग्न प्रपत्र में विवरण हो मे उन कारणों की सूचना दे, जिनकी वजह से गेट पास में दिखाने गये समय और तारीख से चौबीस घंटे के अंदर वस्तु शुल्क माल फैक्टरी से हटाया नहीं जा सका। सूचना की एक प्रति केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता को भेजी जानी चाहिए।

(4) यदि केन्द्रीय उत्पादशुल्क का कोई अधिकारी भेजा गया हो, तो उस के द्वारा निरीक्षण/जाच के लिए उस के सम्मुख शुल्क देने के संबंधित कागजात और माल प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(5) निर्माता अपने पास रखे गये, भेजे गये और बाकी बचे हुए सभी दत्त शुल्क माल का हिसाब निम्नलिखित प्रपत्र में रखेगा।

| तारीख | माल का विवरण | माल जमा | प्राप्तिपत्रों | योग | लाइसेंसी के हस्ताक्षर |
|-------|-----------------|------------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| | | | गेट पास की संख्या और तारीख | मात्रा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 7 |

| निर्गम | माल बाकी | लाइसेंसी के हस्ताक्षर |
|----------------------------------|----------|--------------------------|
| गेट पास की संख्या और तारीख | मात्रा | |
| 8 | 9 | 10 |
| | | 11 |

(6) भंडारी और हिसाब की जांच किसी भी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी द्वारा किसी भी उपयुक्त समय पर की जा सकेगी।

(7) गेट पासों की सभी प्रतियां, जिनके जरिये माल बाहर भेजा जाना हो, उपयुक्त रूप से पुष्टीकृत की जानी चाहिये। और जब माल भेज दिया जाय तब उन पर दोबारा उपयुक्त प्रविष्टि कर दी जानी चाहिये।

II जब शुल्क देने के बाद भेजा गया माल, रेलवे पर बुकिंग अचानक रुक जाने के कारण, फैक्टरी में वापस लाया गया हो।

(1) निर्माता, माल मिलने के चौबीस घंटे के अंदर, उत्पादशुल्क वाले माल की हर खेप फैक्टरी में दोबारा आने के संबंध में संबंधित केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक को संलग्न प्रपत्र में लिखित रूप में सूचना देगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता को भेजेगा।

(2) यदि केन्द्रीय उत्पादशुल्क का कोई अधिकारी निरीक्षण/जांच के लिए भजा गया हो, तो शुल्क देने से संबंधित कागजात और माल उसके संमुख प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

(3) माल, उत्पादन के स्थल और शुल्क न दिया हुआ माल रखने के लिये अनुमोदित भंडारकक्ष से भिन्न स्थान पर अलग जमा किया जाना चाहिये, और दूसरे माल से उस की भिन्नता प्रकट करने के लिए उसके साथ एक स्टॉक कार्ड लगा दिया जाना चाहिये, जिस पर प्रमुखता के साथ "दोबारा/वापस लाया गया माल" लिखा रहना चाहिये और जिस में (i) प्राप्ति की तारीख (ii) प्राप्त मात्रा (iii) निकासी की अनुमति के कागजातों की संख्या और तारीख और (iv) दोबारा भेजने की तारीख और (v) भेजी गयी मात्रा आदि ब्यौरे दिये जाने चाहिए।

(4) जिस गेट पास के जरिये माल पहली बार भेजा गया था, फैक्टरी में माल वापस प्राप्त होने पर उस गेट पास की सभी प्रतियों पर समय और तारीख देने हुए पुष्टीकृत कर देना चाहिये। माल दोबारा भेजते समय इन गेट पासों पर उपयुक्त प्रविष्टि की जानी चाहिये।

(5) निर्माता को उपर्युक्त ग (i) के अधीन विहित प्रपत्र में एक ब्यौरा रखना चाहिये।

(घ) परीक्षण या टिप्पणियों अथवा निर्माण की पद्धति आदि का अध्ययन करने के लिए फैक्टरी में दोबारा मंगाया गया माल।

(1) निर्धारित, उत्पादशुल्क योग्य चीजों के दत्त शुल्क नमूने फैक्टरी में प्राप्त होने के चौबीस घंटे के अंदर उस की सूचना संलग्न प्रपत्र में लिखित रूप में संबंधित केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक को भेजेगा, और उस की एक प्रति केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता के पास भेजेगा।

(2) जरूरत होने पर, नमूने लेने के लिए, केन्द्रीय उत्पादशुल्क के अधिकारी के सम्मुख माल प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) निर्धारित ऐसे माल की प्राप्ति और निबंदारे के बारे में एक सामान्य ब्यौरा रखेगा। इस ब्यौरे की किसी भी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी द्वारा हर समय जांच की जा सकेगी।

(ङ) खुदरा बिक्री के लिए प्या मानार्थ भेंट के रूप में भेजने के लिये या अलग अलग ब्राह्मों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पैकेजों में दोबारा पैक करने के लिए फैक्टरी परिसर में स्टोर करने योग्य माल।

(i) अगर जनता में खुदरा बिक्री के लिए निर्धारित की कोई दूकान हो, तो वह यथासम्भव फैक्टरी के परिसर से दूर होनी चाहिये, और कम से कम फैक्टरी के परिसर से व्यवहारिक रूप से अलग की गयी होनी चाहिये। और लाइसेंस प्राप्त परिसर के अंदर से दूकान में आने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिये।

(ii) यदि निर्धारित केवल फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारियों में खुदरा बिक्री करने के लिए या मानार्थ भेंट के रूप में भेजने के लिए ही दत्त शुल्क माल जमा करना चाहना हो तो उसे सामान्य तौर पर लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर ही ऐसा माल स्टोर करने की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि किसी निर्धारित के पास दत्त शुल्क माल स्टोर करने के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर स्टोर करने का कोई अतिरिक्त स्थान नहीं है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन फैक्टरी परिसर में ही स्थित किसी अलग कमरे/स्थान में माल जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(क) जिस अलग कमरे/स्थान में दत्त शुल्क माल स्टोर किया जाना है, वहां माल स्टोर करने से पहले ही उसे संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त और अनुमोदित किया जायेगा।

(ख) उस कमरे या स्थान की ओर जाने वाले सभी प्रवेश मार्गों को अच्छी तरह बंद करके उसे लाइसेंस प्राप्त परिसर से अलग कर दिया जाएगा और केवल एक ही ऐसा रास्ता खुला रखा जाएगा, जो मुख्य फैक्टरी के बाहर खुले स्थान को जाता होगा। इसके अतिरिक्त स्टोर करने का यह स्थान ऐसा होना चाहिये, जिसे अच्छे प्रकार से ताला लगाकर रखा जा सके।

(ग) ऐसे अनुमोदित भंडारकक्ष/स्थान के अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त परिसर के और किसी भी स्थान पर इस उद्देश्य से को भी दत्त शुल्क माल नहीं रखा जाएगा।

(घ) रिटेल स्टोर के लिए सभी निकासियां शुल्क की भुगतान करने के बाद निकासी की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिये।

(ङ) डिलीवरी के समय दत्त शुल्क माल की हर रूप के लिए नियम 52 के अधीन अलग गेट के पास अवश्य जारी किये जाने चाहिए। एक गेटपास एक सिर्फ इसी काम के लिए प्रयोग में लायी जानी चाहिए। ऐसे गेटपासों के ऊपर प्रमुखता से "रिटेल स्टोर से दत्त शुल्क माल का निर्गम" लिखा रहना चाहिए।

(च) निम्नीकृति को अपने खुदरा भंडार में माल की प्राप्ति, निर्गम और बाकी माल के संबंध में एक ब्योरा नीचे दिये गये प्रणाल में रखना चाहिए।

| प्राप्तियाँ | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------|---------------------------|--------|-----|
| तारीख | माल का ब्योरा | माल जमा | गेटपास की संख्या और तारीख | मात्रा | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| निर्गम | | | | | |
| गेटपासों की संख्या और तारीख | मात्रा | माल बाकी | लाइसेंस के हस्ताक्षर | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

(छ) इस प्रकार रखे गये ब्योरे की किसी भी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी द्वारा हर समय जांच की जा सकती है।

फैक्टरी परिसरों में उत्पादशुल्कों योग्य दत्त शुल्क माल प्राप्त करने/रख लेने के संबंध में घोषणा

सेवा में,

केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी

..... रेज
मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उत्पादशुल्क योग्य माल की निम्नलिखित छेप अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में तारीख को वज कर .. मिनट पर के प्रयोजन से रख ली है/प्राप्त की है।

यदि प्राप्त करने जिस गेट पास के माल का ब्योरा प्राप्त फैक्टरी की बाकी फैक्टरी में अधीन शुल्क का और किन्में संख्या और उन माल नहीं बताया भुगतान किया पर अंकित पह-जाता, तो माल गया है उसकी चान का चिन्ह भेजने वाली फैक्टरी संख्या और का नाम और पता तारीख

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------|---|
| गेट पास में प्राप्त मात्रा | टैरिफ की मद | दिये गये | अभ्युक्ति | |
| विखलाई गई | संख्या | जिसके | शुल्क की | |
| मात्रा | अधीन | शुल्क | राशि | |
| | दिया गया था | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि गेट पास में दिये गये ब्योरे के साथ, प्राप्त किये गये माल के ब्योरे सतोषजनक ढंग से मिलते हैं। माल प्राप्त होने के अवधि के अंदर माल का पुनः प्रसस्करण/उपयोग आदि कर लिया जाएगा।

मैंने/हमने इस उद्देश्य से विहित अपने स्टॉक रजिस्टर केन्द्रीय उत्पादशुल्क खाते में खेपों के ब्योरे दर्ज कर लिये हैं।

लाइसेंसो या उस के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर

[स० के० उ० नि० 5/70]

दे. नं० लाल, समाजवादी केन्द्रीय उत्पादशुल्क, पुना

Poona, the 14th April, 1973

CENTRAL EXCISES

S.O. 1616.—In exercise of the powers conferred on me under rule 173 H of the Central Excise Rules, 1944, I hereby prescribe, in supersession of this Collectorate Notification No. CER. 4/68, dated the 12-9-1968, the procedures as mentioned in Annexure 'A' appended, which shall be followed by every assessee working under the Self Removal Procedure as laid down in Chapter VII A of the Central Excise Rules, 1944 as replaced by Govt. of India Notification No. 182/69-CE, dated the 14th July, 1968 for retaining in, or bringing into his factory or warehouse, the goods on which duty has been paid, for the purposes mentioned below:—

- Goods received/retained for use in the manufacture of other goods in the factory; or
- Goods returned to the factory for being re-made, refined, reconditioned, repaired or subjected to any other similar process in the factory; or
- After payment of duty the goods cannot be transported due to circumstances beyond the assessee's control such as suspension of booking on railways, non-availability of railway wagon or the break-down of carriers; or
- Goods are required for test or for studying designs or method of construction; or
- Goods are required to be stored in the factory premises for retail sale or for issue as complimentary gift or for repacking into packages so as to suit the requirements of individual customers.

ANNEXURE 'A'

(A) Goods received/retained for use in the manufacture of other goods in the factory:—

(1) The assessee shall inform within twentyfour hours from the time of receipt of the duty paid goods/retained in the factory to the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over the factory in writing in form enclosed with a copy to the Assistant Collector concerned.

(2) The goods with relevant duty paying documents should be presented for inspection/examination by the Central Excise officer if deputed for the purpose.

(3) The assessee shall maintain a record in the following proforma showing details of the goods retained/received, disposed of, etc.

(4) The goods should be stored separately from the non-duty paid goods and such storage place should be distinct from the Bonded Store-room for non-duty paid goods.

FORM

Account of duty paid goods received/retained in the factory premises for use in the factory

Name of the factory.....
Address
Licence No.
Description of goods.....

| Date | Open- ing balance | Receipts | | | |
|------|-------------------------|--|------------------------------------|------|-------|
| | | Name of the factory from which the goods are received | No. & date of docu- ment (s) | Qty. | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Signature of the manu- facturer | Issues | | Closing balance | Signature of the manu- facturer | Remarks |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|--|---------|
| | No. & date of docu- ment(s) | Quan- tity | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

NOTE :—Separate opening should be kept for accounting each type of goods.

(5) The stocks and accounts shall be open to inspection by any Central Excise officer at all times.

(B) Goods returned to the factory for being remade, refined, reconditioned, repaired or subjected to any other similar process in the factory:—

I. When duty paid goods except Electric fans, Electric Batteries, Electric Bulbs, Tyres and Tubes, I.C. Engines, Electric Motors, W.R. Sets, Refrigerating and Airconditioning appliances, Cement, Woollen Fabrics, Sugar, are returned for being remade, refined, reconditioned or subjected to any similar process in the factory.

- (i) The Assessee shall inform the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over his factory in writing in form enclosed within twenty-four hours of the receipt of the goods into the factory, with a copy to the Assistant Collector Central Excise, concerned.
- (ii) The goods shall be stored separately away from the Bonded Store-room pending their being remade, refined, reconditioned, or repaired.
- (iii) The goods along with the relevant duty paying documents shall be presented for inspection/examination by the Central Excise Officer if deputed for the purpose.
- (iv) The goods should be reprocessed, remade, refined, reconditioned, repaired or subjected to similar process isolately from the manufacture of fresh goods and in any circumstances such goods should not be mixed up with the manufacture of fresh goods.
- (v) If any excisable components are required for reprocessing, remade, repairs etc. of such goods duty should be paid on such components as usual before these are taken for repairs, remaking etc. of the goods.
- (vi) The goods so reprocessed, remade, etc. should be stored separately from the non-duty paid goods in the bonded store room.
- (vii) Gate passes covering re-issue of duty paid repaired, reconditioned goods shall carry on the top a prominent endorsement — "RE-ISSUE OF REPAIRED/ REPROCESSED GOODS".
- (viii) A detailed account of such goods received, the processes to which they are subjected to after their return to the factory and the quantity obtained after reprocessing, remarking etc. shall be kept by the assessee, in the subjoined form.

Account of duty paid goods received for reprocessing, remaking repairs etc. under Rule 173 H of the CE Rules, 1944

Name and address of the factory.....
Licence No.

Receipts

| Date of receipt into factory | From whom received | Description of goods | Brand name with identifying marks or No. if any | Qty. recd. | Signature of assessee or his agent |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Details of reprocessing/repairs

| Details of re-processing/re-making/repairs etc. to which such goods are subjected to | Quantity recovered after reprocessing | Description of excisable components used, if any | Amount of duty paid on the components with No. & date of gate pass |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 7 | 8 | 9 | 10 |

Issues

| Date | No. & date of gate pass | Quantity | Remarks | Signature of the assessee or his agent |
|------|-------------------------|----------|---------|--|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Refund granted, if any, of the duty

Remarks

16

17

NOTE :—(1) The account should be maintained consignmentwise.

(2) In case of damaged sugar/cement if the procedure of duty free clearance on quantity to quantity basis is followed, col. 8 should be amended to read 'permissible quantity for delivery free of duty as intimated by the Central Excise Officer'.

(ix) The record so maintained as well as relevant documents shall be open to inspection by any Central Excise Officer at all times.

(x) The manufacturers should follow the above procedure when they desire to reprocess, remake, etc. duty paid goods received into the factory isolately and to clear such goods after reprocessing, remaking etc. without payment of duty. However if the manufacturer cannot follow the above procedure, he may reprocess, remake etc. such goods under claim for refund by following the procedure laid down under Rule 173 I or 100 of the Central Excise, Rules, 1944.

II. Damaged sugar/cement brought back to the factory for refining, processing etc.

- (1) The assessee shall inform the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over his factory in writing in form enclosed within twentyfour hours of the receipt of the goods into the factory with a copy to the Assistant Collector Central Excise, concerned.
- (2) The consignment shall be stored separately till it is inspected by the Central Excise Officer.
- (3) The Central Excise Officer deputed for the purpose will weigh the consignment so received into the factory, draw representative sample, prepare the usual test memo, forward the sample to the Chemical Examiner for ascertaining the recoverable sugar/cement.
- (4) The Assistant Collector on receipt of the test report from the Chemical Examiner will intimate to the Supt. of Central Excise concerned, the quantity of goods permitted to be delivered free of duty from the factory against the damaged goods brought into the factory.
- (5) The Supdt. of Central Excise concerned on receipt of orders from the Asstt. Collector will apprise the assessee of the result of the chemical analysis and will permit clearance of a quantity equivalent to the recoverable quantity as determined by the Chemical Examiner without payment of duty.
- (6) The reprocessed quantity should be accounted for in the Central Excise accounts.
- (7) Gate pass covering such duty free clearance of sugar/cement shall carry on the top a prominent endorsement "DUTY FREE CLEARANCE AS PER SUPERINTENDENT'S ORDER NO.....DATE....."
- (8) The assessee shall maintain a detailed account of the damaged sugar/cement received and the process to which the same is subjected to in the factory in the form mentioned at (B) (I) (viii) above, which shall be open to inspection by any Central Excise Officer at all times. This account shall be in addition to the Central Excise Accounts.

III. Electric batteries, fans, electric bulbs, tyres and tubes, I.C. Engines, electric motors, W.R. Sets, Refrigerating and airconditioning appliances, brought into the factory for repairs, reconditioning, etc.

- (1) The assessee shall inform the Supdt. Central Excise having jurisdiction over his factory in writing in form enclosed, within twenty-four hours of the receipt of the goods into the factory with a copy to the Asstt. Collector Central Excise, concerned.
- (2) The goods so received shall be stored in a separate place specified for the purpose and repairing, reconditioning, etc. shall as far as possible be undertaken in a separate section as distinct from the manufacturing

section. When it is done in the manufacturing section itself, prior intimation should be given to the Supdt. of Central Excise concerned

- (3) The assessee shall pay duty on excisable parts used for repairing, reconditioning, etc. in the usual manner at the time of removal of the excisable parts before utilising them for repairs.
- (4) All removals of repaired/reconditioned goods shall take place under cover of separate gate pass as maintained for this purpose and shall carry on the top a prominent order about "REISSUE OF REPAIRED/RECONDITIONED DUTY PAID GOODS".
- (5) A detailed account of the returned goods shall be kept by the assessee in the form at (B) (I) (viii) above.
- (6) The manufacturer shall remove the goods after repairs/reconditioning within one month of the date of receipt thereof into the factory. However this time limit shall be extended by the Supdt. of C. Ex. to three months subject to the condition that the number of such batteries, fans so brought into the factory for repairs/reconditioning does not exceed at any one time 1% of the annual production of the assessee. This limit shall be relaxed to 5% in case of electric motors, electric batteries, and electric fans. In case of refrigerating and airconditioning appliances, electric motors, I.C. Engines, electric fans & electric batteries, the normal period for removal will be three months instead of 1 month. In deserving cases extension upto 9 months will be granted by the Supdt. and beyond that period by the Collector.

IV. Goods returned to the factory for being remade, refined, reconditioned, etc. under the provisions of Rules 173 L and 173 M and 100.

- (1) The assessee should follow the procedure laid down in the respective rules and as prescribed from time to time and he should maintain an account of the goods so received, the process to which subjected, and removed, in the form mentioned at (B)(I)(viii) above in addition to the accounts already prescribed under the procedure laid down under the respective rules. In the case of cement and sugar the procedure as laid down under B(II) above should be followed in addition to the procedure laid down under the respective rules. In the case of woollen fabrics the preprocessing of duty paid fabrics shall not be permitted under the provisions of rule 173 H. However, reprocessing of such fabrics shall be permitted under the provisions of rule 173 L of the Central Excise Rules, 1944.
- (C) (I) After payment of duty the goods cannot immediately be transported due to circumstances beyond the assessee's control such as non-availability of railway wagons or the breakdown of the carriers.
- (1) The place in the factory where such duty paid goods shall be stored shall be duly declared and approved by the officer competent to issue or renew the manufacturing licence.
- (2) The storage place should be separate and distinct from all parts of the premises forming the manufactory and approved store rooms for non-duty paid goods.
- (3) The assessee should intimate to the Supdt. Central Excise having jurisdiction over the factory in writing in form enclosed, the reasons for not removing the duty paid goods from the factory within twentyfour hours from the time and date shown in the gate pass with a copy to Assistant Collector Central Excise concerned.
- (4) The goods with the relevant duty paying documents should be presented for inspection/examination by the Central Excise Officer if deputed for that purpose.
- (5) The manufacturer shall keep an account of all goods retained, issued and balance of duty paid goods in the following form.

| Date | Description of goods | Opening balance | Receipt | | Total |
|------|----------------------|-----------------|----------------------|------|-------|
| | | | Gate pass No. & date | Qty. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Signature of licensee | Issues | | Closing balance | Signature of licensee |
|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| | No. & date of the gate pass | Quantity | | |

- | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|---|----|----|
| (6) | The stocks and accounts shall be open to inspection by any Central Excise Officer at all reasonable times. | | | |
| (7) | All copies of gate passes under which the goods are intended to be cleared should be suitably endorsed and when the goods are cleared again a suitable entry should be made on these gate passes. | | | |
| (II) | When goods cleared on payment of duty are brought back into the factory due to sudden suspension of booking on railways. | | | |
| (1) | The manufacturer shall inform the Supdt. of Central Excise concerned in writing in form enclosed about the re-entry of each consignment of excisable goods in his factory within twentyfour hours of receipt with a copy to the Assistant Collector Central Excise concerned. | | | |
| (2) | The goods with the relevant duty paying documents should be presented for inspection/examination by the Central Excise Officer if deputed for the purpose. | | | |
| (3) | The goods shall be stored separately in a place distinct from the main premises forming the manufactory and approved store-room for non-duty paid goods, a stock card superscribed "REENTERED GOODS" showing (i) date of receipt (ii) quantity received (iii) No. and date of clearance documents; (iv) date of reissue; and (v) quantity issued should be maintained to distinguish them from the other goods if any. | | | |
| (4) | All copies of gate passes under which the goods were first cleared should be endorsed when the goods are received back in the factory giving time and date. When the goods are cleared again, suitable entry should be made on these gate passes. | | | |
| (5) | The manufacturer should maintain an account in form prescribed under C(I) above. | | | |
| (D) | Goods brought into the factory for test or for studying designs or method of construction etc. | | | |
| (1) | The assessee shall notify to the Supdt. of Central Excise concerned in writing in form enclosed within twentyfour hours of receipt of samples of duty paid excisable goods into the factory with a copy to the Assistant Collector Central Excise concerned. | | | |
| (2) | The goods shall be presented for inspection, if necessary, for sampling by the Central Excise Officer. | | | |
| (3) | The assessee shall keep a simple account of the receipt and disposal of such goods. This account shall be open for inspection by any Central Excise Officer at all times. | | | |
| (E) | Goods required to be stored in the factory premises for retail sale or issue as complimentary gifts or repacking into packages so as to suit the requirement of the individual customers. | | | |
| (1) | Where the assessee has a retail shop open to the public it should as far as possible be located away from the factory premises and in any case physically segregated from the factory premises, there being no entrance to the retail shop from inside the licensed premises. | | | |
| (2) | Where the assessee wants to store duty paid goods for retail sale to factory employees only or issue as complimentary gifts, he should normally arrange for storage of such goods outside licensed premises. However any assessee having no additional storing place outside the licensed premises for storing duty paid goods, he will be permitted to store the goods in a separate room/place situated within the factory premises subject to the following conditions:— | | | |

- (a) The separate room/place where duty paid goods are to be stored shall be duly declared and approved by the licensing authority concerned, prior to storage therein.

- (b) The room or place shall be segregated from the rest of the licensed premises by effectively closing all entrances into it except one communicating only with the open space outside the main factory building and this storage place should be capable of being securely locked.
- (c) No duty paid goods shall be stored for this purpose elsewhere in the licensed premises except in such approved store room/place.
- (d) All issues for the retail store must be in accordance with the usual procedure for clearance on payment of duty.
- (e) Separate gate passes under rule 52A must be issued for each lot of duty paid goods at the time of delivery. One gate pass book should be exclusively used for this purpose. Such gate passes should carry on the top a prominent endorsement "ISSUE OF DUTY PAID GOODS FROM THE RETAIL STORE".
- (f) The assessee should maintain an account of receipt, issues and balance in the retail store, in the form given below:—

| Date | Description of goods | Opening balance | Receipts | | Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|-------|
| | | | G.P. No. & date | Qty. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <hr/> | | | | | |
| Issues | | Closing balance | Signature of licensee | Remarks | |
| No. & date of gate passes | Qty. | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

- (g) The account so maintained will be open for inspection by any Central Excise Officer at all times.

DECLARATION OF RECEIPT OF/RETAIN IN, OF DUTY PAID EXCISABLE GOODS IN THE FACTORY PREMISES To

The Superintendent of Central Excise.....
i/c Range.

I/We hereby declare that the undermentioned consignment of excisable goods has been retained/received by me/us at our licensed premises on 19..... at hrs for purpose of

| Name and address of the factory where the goods are not manufactured in the factory of receipt | No. and date of gate pass under which duty has been paid | Description and variety of goods | No. of packages & identifying marks on the packages received | |
|--|--|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | |
| Quantity as shown in the gate pass | Quantity received | Tariff item No. under which duty was paid | Amount of duty paid | Remarks |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

I/We declare that the goods received are identifiable with the description given in the gate pass to my/our entire satisfaction. The goods will be reprocessed/used etc. within..... period of receipts

I/We have entered the particulars of the consignments in my/our stock register as well as in C. Ex. accounts prescribed for the purpose.

Signature of the licensee or his authorised agent

Attested

Sd./ (Illesible)

[No. CER No. 5/70]
D. N. LAI., Collector.

Dy. Collector (Tech.),
Central Excise, Poona.

नई दिल्ली, 9 जून, 1973

सीमा-शुल्क

क्र. आ. 1617.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड गुजरात राज्य में नाडियाद के भाण्डागारण केंद्र घोषित करता है।

[सं. 95/73-सीमा-शुल्क/फ. सं. 473/35/72-सी. शु. 7]

के शंकररामन, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 1973

CUSTOMS

S.O. 1617.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Nadiad in the State of Gujarat to be a warehousing station.

[No. 95/73-Customs/F. No. 473/35/73-Cus. VII]

K. SANKARARAMAN, Under Secy.

बाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मई, 1973

क्र. आ. 1618.—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वस्त्र समिति द्वारा इस निमित्त उसे किए गए सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. क्र आ. 2200, तारीख 28 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) परन्तुक में,—

(क) खंड (1) में, "(1)" क्रोष्ठकों और अंक, तथा अन्त में आने वाले शब्द "या" का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (2) का लोप किया जाएगा;

(2) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्विष्ट अधिकारी बिना किसी ऐसे प्रमाणपत्र के ही किसी ऐसी सामग्री का निर्यात करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसकी राय हो कि वस्त्र समिति, उन कारणों के लिए जो ऐसे अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, उस तारीख से जिसकी सामग्री निरीक्षण के लिए ली गई थी, एक सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे निरीक्षण की व्यवस्था करने और उसे पूरा करने में असमर्थ रही है।"

[फ. सं. 25011/1/73-वस्त्र (ए):

टी. खन्ना, उप-सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 28th May, 1973

S.O. 1618.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), and on the recommendation made to it in this behalf by the Textiles Committee, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2200, dated 28th May, 1971, namely:—

In the said notification,—

(i) in the proviso,—

(a) in clause (i), the brackets and figure "(i)", and the word "or", occurring at the end, shall be omitted;

(b) clause (ii) shall be omitted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the officer referred to in the preceding proviso may permit any such material to be exported without any such certificate, if he is of the opinion that the Textiles Committee is unable, for reasons to be recorded by such officer in writing, to arrange for and complete such inspection, within a period of one week from the date of which the material is offered for inspection."

[File No. 25011/1/73-Text(A)]
T. KHANNA, Dy Secy.

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1973

का. आ. 1619.—स्पिरिट संबंधी विनिर्मातियों (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग से संबंधित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1779, तारीख 5 अगस्त, 1959 को विरुद्धित करती है।

[फा. सं. 4(2)-आई. टी./72]

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 31st May, 1973

S.O. 1619.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 1779 dated the 5th August, 1959 relating to the delegation of powers of the Central Government to the State of Andhra Pradesh to frame rules under section 3 of the said Act.

[F. No. 4(2)-I.T./72]

का. आ. 1620.—स्पिरिट संबंधी विनिर्मातियों (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1778, तारीख 5 अगस्त 1959 को विरुद्धित करती है।

[फा. सं. 4(2)-आई. टी./72]

य. एस. राणा, संयुक्त निदेशक

S.O. 1620.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 2 of the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955), the Central Government hereby rescinds the notification of the

Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry, No. S.O. 1778 dated the 5th August 1959.

[F. No. 4(2)-I.T./72]

U. S. RANA, Jt. Director.

नई दिल्ली, 9 जून, 1973

का. आ. 1621.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कच्ची की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम कच्ची की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. कच्ची की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1966 में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7 निरीक्षण फीस.—इन नियमों के अधीन लेबल लगाने और निरीक्षण के लिए, बीबी बिट्स (बी बी) श्रेणी के छोड़ कर कच्ची की गिरियों की सभी श्रेणियों के प्रति 11.34 कि. ग्रा. (25 पाउंड) या उसके भाग के लिए तथा बीबी बिट्स (बी बी) श्रेणी के प्रति 12.70 कि. ग्रा. (28 पाउंड) या उसके भाग के लिए तरह पैसे की फीस, और सभी श्रेणियों की कच्ची की गिरियों के प्रति 5 कि. ग्रा. (11.02 पाउंड) या उसके भाग के लिए पांच पैसे की फीस ली जाएगी।"

[सं. 60(4)/67-नि. नि. तथा नि. सं.]

New Delhi, the 9th June, 1973

S.O. 1621.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1966 namely:—

1. These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1966, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. **Inspection Fee.**—A fee of thirteen paise for every 11.34 kg. (25 lbs.), or fraction thereof, of all grades of cashew kernels excluding the grade "Baby Bits (BB)" and for every 12.70 kg. (28 lbs.), or fraction thereof, of the grade "Baby Bits (BB)", and a fee of five paise for every 5 kg. (11.02 lbs.), or fraction thereof, of all grades of cashew kernels shall be charged for labelling and inspection under these rules."

[No. 60(4)/67-EI&EP]

का. आ. 1622.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम समक-दार इस्पात छड़ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 है।

(2) ये नियम 9 जुलाई, 1973 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधीनियम” से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) “अभिकरण” से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई भी अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “परिषद्” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) “चमकदार इस्पात छड़” से साधारण इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए शीतल कर्षण, शीतल बेलन, वर्तन घर्षण से बनाई गई इस्पात की छड़ें और ढंड अभिप्रेत हैं।

3. निरीक्षण का आधार:—निर्यात के लिए चमकदार इस्पात छड़ों का निरीक्षण परेषण के तैयार हो जाने पर यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) चमकदार इस्पात छड़ों का निर्यात करने का आशय रखने वाला निर्यातकर्ता, निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी को भी, ऐसा करने के अपने आशय की लिखित प्रज्ञापना भेज देगा और किसी प्रज्ञापना के साथ-साथ उन विनिर्देशों की जो निर्यात संविदा में अनुबंध हैं, घोषणा भी सभी तकनीकी विशेषताओं का ब्याँस देते हुए, प्रस्तुत करेगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो सके। साथ ही वह ऐसी प्रज्ञापना की एक प्रतीति निरीक्षण के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् या तो “वर्ल्ड ट्रेड सेंटर” 7वीं मंजिल, 14/बी, इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1 या “अमन चैम्बर”, 113, महावि कर्वे रोड, बम्बई-4 या मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम कोचीन-11 या 13/37, आर्य समाज रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेसवेन एरिया, नई दिल्ली-6 स्थित कार्यालय को भेज देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक प्रज्ञापना और घोषणा अभिकरण और परिषद् के कार्यालय में पोत लदान की अनुबंध तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व पहुँच जानी चाहिए।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रज्ञापना और घोषणा प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अभिकरण चमकदार इस्पात छड़ों का निरीक्षण नियम 3 और इस बारे में परिषद् जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार करेगा।

(4) निरीक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् अभिकरण परेषण के पैकेजों को इस प्रकार से सील कर देगा ताकि सील किए गए माल में कोई गड़बड़ी न की जा सके। परेषण के अस्वीकृत हो जाने की दशा में यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे, तो परेषण अभिकरण द्वारा सील नहीं किया जा सकता है। तथापि, ऐसी दशा में निर्यातकर्ता अस्वीकृत के विरुद्ध अपील नहीं कर सकेगा।

(5) जब अभिकरण का समाधान हो जाए कि चमकदार इस्पात छड़ों का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है। तब वह निर्यातकर्ता को निरीक्षण पूरा होने के 3 दिनों के भीतर परेषण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा।

परन्तु जहाँ अभिकरण का प्रकार समाधान नहीं हो पाता है, वहाँ वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण दंड हो उसकी संसूचना निर्यातकर्ता को देगा।

5. निरीक्षण का स्थान:—इन नियमों के प्रयोजनार्थ चमकदार छड़ों का निरीक्षण:—

(क) विनिर्माता के परिसर में किया जाएगा, या

(ख) उस परिसर में किया जायेगा जहाँ निर्यातकर्ता द्वारा चमकदार छड़ों की प्रस्थापना की जाती है;

परन्तु यह तब जबकि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

6. निरीक्षण फीस:—इन नियमों के अधीन निर्यातकर्ता प्रति टन 4 रुपये की दर की फीस 50 न्यूनतम के अधीन रहते हुए, अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में देगा।

7. अपील:—(1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यक्ति कोई व्यक्ति उसी इंकारी का संसूचना प्राप्त होने के दो दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें कम से कम तीन व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल का अधिवेशन करने के लिए उरुकी गणपूर्ति उसके तीन विशेषज्ञों की होगी।

(3) ऐसी अपील पर, उक्त पैनल का विनिश्चय अंतिम होगा।

[सं. 6(1)/71-नि. नि. और नि. सं.]

S.O. 1622.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely—

1. **Short title and commencement:**—(1) These rules may be called the Export of Bright Steel Bars (Quality Control and Inspection) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on 9th July, 1973.

2. **Definitions:**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) “Agency” means any one of the Export Inspection Agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay or Delhi under section 7 of the Act;

(c) “Council” means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) “Bright Steel Bar” means steel bars and shaftings produced by cold drawing, cold rolling, turning or grinding for general engineering purposes.

3. **Basis of inspection:**—Inspection of Bright Steel Bars for export shall be carried out when the consignment is ready with a view to seeing that the same conforms to the standard specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. **Procedure of inspection:**—(1) Any exporter intending to export Bright Steel Bars shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specification stipulated in the export contract giving details of the technical characteristics to any of the Export Inspection Agencies to enable it to carry out inspection in accordance with rule 3. They shall at the time endorse a copy of such intimation for inspection to the office of the Export Inspection Council, either at “World Trade Centre”, 7th Floor, 14/1-B, Ezra Street, Calcutta-1, or “Aman Chamber”, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4 or at Manohar Building, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-11 or at 13/37, Arya Samaj Road, Western Extn. Area, New Delhi-5.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the Agency and the Council not less than ten days before the stipulated date of shipment.

(3) The Agency shall carry out the inspection of Bright Steel Bars in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard within 7 days of receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2).

(4) After completion of inspection, the Agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection of a consignment if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(5) When the Agency is satisfied that the consignment of Bright Steel Bars complies with the requirement of rule 3, it shall issue within 3 days of completion of inspection, a certificate to the exporter declaring that the consignment is export-worthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons therefor.

5. Place of inspection:—Inspection of Bright Steel Bars for the purposes of these rules shall be carried out—

(a) at the premises of the manufacturer; or

(b) at the premises at which, the Bright Steel Bars are offered by the exporter, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection fee:—A fee at the rate of Rs. 4 per tonne subject to a minimum of Rs. 50 shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee under these rules.

7. Appeal:—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than 3 persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The quorum to constitute a meeting of the panel of experts shall be of its three experts.

(3) The decision of the said panel on such appeal shall be final.

[No. 6(1)71-EI & EP]

आदेश

का. आ. 1623.—यतः भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए चमकदार इस्पात छड़ों को निर्यात से पूर्व अनिवार्य पूर्व पोत सदान निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कृतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 2 के उपनियम (2) द्वारा तथा अपेक्षित भारत सरकार के तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2307, तारीख 19 जून, 1971 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 19 जून, 1971 में पृष्ठ 2283-2291 पर प्रकाशित किए गए थे;

और यतः एतद्वारा संभावित प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से 18 जुलाई, 1971 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता के 19 जून, 1971 के उपलब्ध करा दी गई थी;

और यतः उक्त प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

2. अतः, अब निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार अपनी यह राय देने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है—

(1) यह अधिसूचित करती है कि चमकदार इस्पात छड़ें निर्यात पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी,

(2) चमकदार इस्पात छड़ें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती हैं जो निर्यात पूर्व चमकदार इस्पात छड़ों को लागू होंगे,

(3) इस आदेश के उपाबन्ध में उपवीणित विनिर्देश के न्यूनतम के अधीन रहते हुए उस विनिर्देश को, जिसके बारे में निर्यातकर्ता द्वारा यह घोषित किया गया है कि वह चमकदार इस्पात छड़ों के लिए निर्यात-सिद्धि की सहमति-प्राप्त विनिर्देश हैं, चमकदार इस्पात छड़ों के लिए मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देती है;

(4) चमकदार इस्पात छड़ों के अंतराष्ट्रीय व्यापार के दौरान निर्यात का तब तक प्रतिबंध करती है जब तक उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अधिकरणों में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि चमकदार इस्पात छड़ों का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है और निर्यात-योग्य है।

3. परिभाषा:—इस आदेश में “चमकदार इस्पात छड़ों” से साधारण इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए कर्षण शीतल, शीतल बलन बर्तन या धर्षण से बनाई गई इस्पात की छड़ें और दण्ड अभिप्रेत हैं।

4. इस आदेश की कोई भी बात उन चमकदार इस्पात छड़ों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका भारी क्रेताओं के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 125 रुपये (एक सौ पच्चीस रुपये) से अधिक नहीं है।

5. यह आदेश 9 जुलाई, 1973 को प्रवृत्त होगा।

उपाबन्ध

(पैरा 2 का उपपैरा (3) देखिए)

(चमकदार इस्पात छड़ों के लिए मानक विनिर्देश)

1. साधारण—चमकदार इस्पात छड़ें स्क्रैप का पुनः दोलन करके बनाए गए इस्पात या धटिया किस्म की धातु से नहीं बनाई जाएगी।

2. रासायनिक संरचना—गंधक और फास्फोरस की अन्तर्वस्तुएं प्रत्येक 0.070 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

टिप्पणी—क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से कटे जाने पर 0.070 प्रतिशत से अधिक की उच्चतर गंधक अन्तर्वस्तु ग्रहण की जा सकेगी।

3. लंबाई सामर्थ्य—32 कि०ग्रा०/मिमी से कम नहीं होगी।

4. दोष मुक्तता—चमकदार इस्पात छड़ें पृष्ठा उपलब्ध में की गई ग्रीक दृश्य सतहों दोषों से मुक्त होंगी। वे चमकदार ग्रीक साफ होंगी। मित्र उचित रूप में वर्गीकृत ग्रीक साफ होंगी।

5. आकार में सहमति—क्रेता द्वारा का विनिर्दिष्ट सहायता कि जान का दशा में चमकदार छड़ें निम्नलिखित मापदंडों में अर्पित रहें

हुए किसी भी आकार (गोल, षट्कोणीय, बर्गिकार, आयताकार, आदि) में प्रदाय की जाएगी।

| आकार | सहायता | आकार | सहायता |
|---|--------|---|--------------|
| मि०मी० | मि०मी० | इंचों में | मि०मी० (इंच) |
| 6 से कम | 0.05 | 1/4 से कम | 0.002 |
| 6 से 24 तक | | | |
| जिसके अन्तर्गत | 0.08 | 1/4 से 7/8 जिसके अन्तर्गत | 0.03 |
| 24 भी है। | | 7/8 भी है | |
| 24 से ऊपर और 50 को सम्मिलित करने हुए 50 तक | 0.10 | 7/8 से ऊपर और 2 को सम्मिलित करने हुए 2 तक | 0.004 |
| 50 से ऊपर और 100 को सम्मिलित करते हुए 100 तक | 0.13 | 2 से ऊपर और 4 को सम्मिलित करने हुए 4 तक | 0.005 |
| 100 से ऊपर और 125 को सम्मिलित करते हुए 125 तक | 0.15 | 4 से ऊपर और 5 को सम्मिलित करने हुए 5 तक | 0.006 |
| 125 से ऊपर सभी + (धन) | 0.18 | 5 से ऊपर सभी + (धन) | 0.007 |
| सहायताएं | 0.00 | सहायताएं | 0.000 |

6. पैकिंग :-

भ्रमकदार इस्पात छड़ों को संभारण से सम्बन्धित रूप से संरक्षित किया जायेगा। छड़े बड़लों में पैक की जाएंगी और पालिथीन के अस्तर वाले बिजुलीन लगे टाट में लपेटे जाएंगी। प्रत्येक बड़ल पर निम्नलिखित सूचना साफ साफ अंकित की जाएगी :-

- (क) विनिर्माता का नाम
- (ख) व्यापार चिन्ह
- (ग) आकार और लम्बाई
- (घ) विनिर्देश
- (ङ) उत्पादन का देश

7. नमूना लेना :-

प्रत्येक परेवण का नमूना लेने और निरीक्षण का कार्य नीचे की विहित मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा। परेवण को मानक की अपेक्षाओं के अनुसार तभी समझा जाएगा जब उक्त मारणी से दी गई शर्तें पूरी कर दी गई हों।

सारणी

| क्रम सं० | खंड का संदर्भ | लक्षण | लाट का आकार | एक लाट में से परख हेतु लिए जाने वाले नमूनों की संख्या | टिप्पणी |
|----------|---------------|--|----------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | गंधक तथा फॉस्फोरस अन्तर्वस्तुएं और आकार के इस्पात के 40 टन या उसका भाग | एक ही प्रोफाइल | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------|---|--|--|---|
| 2. | तनन सामर्थ्य | एक ही प्रोफाइल और आकार के इस्पात खंडों के 40 टन या उसका भाग | 2 | यदि दोनों नमूने परख में पास हो जाते हैं तो लाट को पास समझा जायेगा। यदि दोनों निष्फल रहते हैं तो लाट एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा किसी एक के निष्फल होने की वशा में 2 और नमूने परख हेतु लिए जाएंगे। यदि आगे और कोई निष्फलता होती है तो लाट अस्वीकृत कर दिया जायेगा। | |
| 3. | 4 | दोष मुक्तता | एक ही प्रोफाइल और आकार के इस्पात खंडों की 100 - लम्बाइया या उसका भाग | 5 | — |
| 4. | 5 | विमाण | —यथोक्त— | 2 | — |

[सं० 6(1)/71-नि० नि० और नि० सं०]

ORDER

S.O. 1623.—Whereas for the development of export trade of India, certain proposals for subjecting Bright Steel Bars to compulsory pre-shipment inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 at pages 2283—2291 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 19th June, 1971, under the notification of Government of India in the then Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2307, dated the 19th June, 1971;

And whereas, objections and suggestions were invited till the 18th July, 1971, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 19th June, 1971;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India, hereby—

- (1) notifies that Bright Steel Bars shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (2) specifies the type of inspection in accordance with the Export of Bright Steel Bars (Quality Control and Inspection) Rules, 1973 as the type of inspection, which should be applied to Bright Steel Bars prior to export;
- (3) recognises the specification as declared by the exporter to be the agreed specification of the export contract of Bright Steel Bars, subject to the minimum of the specification set out in Annexure to this order as the standard specification for Bright Steel Bars;
- (4) prohibits the export, in the course of international trade of Bright Steel Bars unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of Bright Steel Bars satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export-worthy.

3. **Definition.**—In this order “Bright Steel Bars” means steel bars and shaftings produced by cold drawing, cold rolling, turning or grinding for general engineering purposes.

4. Nothing in this order shall apply to the export of Bright Steel Bars, the f.o.b. value of which does not exceed Rs. 125 (Rupees one hundred twenty-five) to prospective buyers.

5. This order shall come into force on 9th July, 1973.

ANNEXURE

[See sub-paragraph (3) of paragraph 2]

(Standard specification for Bright Steel Bars)

1. **General.**—Bright steel Bars shall not be made out of steel re-rolled from scrap or off-grade material.

2. **Chemical composition.**—Sulphur and phosphorus contents shall not exceed 0.070% each.

Note:—Higher sulphur content of more than 0.070% shall be permitted in case a buyer specifically asks for the same

3. **Tensile Strength.**—Tensile strength shall not be less than 32 kgf./mm².

4. **Freedom from defects.**—Bright steel bars shall be sound, reasonably straight and free from visible surface defects. They shall be bright and clean. Ends shall be reasonably square and clean.

5. **Tolerances on size.**—Bright steel bars shall be supplied in any shape (round, hexagonal, square, rectangular, etc.) subject to the following tolerances which shall be followed in the absence of any specific tolerance stipulated by a buyer.

| Size in mm | Tolerance Minus (mm) | Size in inches | Tolerance Minus (Inch) |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Below 6 | 0.05 | Below 1/4 | 0.002 |
| 6 upto and including 24 | 0.08 | 1/4 upto and including 7/8 | 0.003 |
| Over 24 upto and including 50 | 0.01 | Over 7/8 upto and including 2 | 0.004 |
| Over 50 upto and including 100 | 0.13 | Over 2 upto and including 4 | 0.005 |
| Over 100 upto and including 125 | 0.15 | Over 5 upto and including 5 | 0.006 |
| Over 125 | 0.18 | Over 5 | 0.007 |
| All Plus tolerances | 0.00 | All Plus tolerances | 0.000 |

6. **Packing.**—Bright steel bars shall be suitably protected against corrosion. Bars shall be packed in bundles and wrapped with polythene lined bituminised hessian. Each and every bundle shall be clearly marked with the following information :

- (a) Manufacturer's name
- (b) Trade mark.
- (c) Size and length.
- (d) Specification
- (e) Country of origin

7. **Sampling.**—Sampling and inspection of each consignment shall be done in accordance with the scale prescribed in the Table below. The consignment shall not be considered to be in conformity with the requirements of the standard if the conditions laid down in the said Table are not satisfied.

TABLE

| Sl. No. | Re-ence to Clause | Characteristics | Lot size | No. of samples to be tested in a lot | Remarks |
|---------|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2 | Sulphur & phosphorus contents | 40 tons or part thereof of steel profile of same and size | 1 | |
| 2. | 3 | Tensile strength | 40 tons or part thereof of steel sections same of profile and size | 2 | The lot shall be deemed to have passed, if both the samples pass the test. If both fail, the lot shall be rejected straight away. In case of any one failure, 2 more samples shall be tested. If any further failure occurs, the lot shall be rejected. |
| 3. | 4 | Freedom from defects | 100 lengths or part thereof of steel sections of the same profile and size. | 5 | .. |
| 4. | 5 | Dimensions | Do. | 2 | .. |

[No. 6 (1)/71—ET&EP.]

K. L. MATHUR, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

का० प्रा० 1624.—यत् केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए रबर के बारे में भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1004, तारीख 23 मार्च, 1967 में भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संपोधन करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त निम्नित प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उपनियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिए हैं।

अतः, अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को सभाप्यतः प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है।

2 यह सूचना दी जाती है कि जो व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे, वह उन्हें उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "बल्ड ट्रेड सेंटर" 14/1 बी, इबरा स्ट्रीट (गातकी मजिन), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1004 तारीख 23 मार्च 1967 में,—

(i) उपाबन्ध 1 में क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

- "14. अग्निशमन नम्पनाल।
15. सीमेंट मरार्थ के नम्पनाल।
16. गर्म पानी के नम्पनाल।",

(ii) उपाबन्ध 2 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबन्ध रखा जायेगा, अर्थात् —

उपाबन्ध 2

रबर के नम्पनालों के लिए मानक विनिर्देश

1. जल वितरण नम्पनाल के लिए विनिर्देश

भा० प्रा० :- 144-1968 . बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले रबर के पानी के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

भा० प्रा० :- 913-1968 . गोलाई में बुने हुए कपड़े के प्रबलन और रबर के पानी के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

2. जलसूषण नम्पनाल के लिए विनिर्देश

भा० प्रा० 2482-1963 हल्के कामों के लिए रबर के जलसूषण नम्पनाल के लिये भारतीय मानक विनिर्देश।

भा० प्रा० 3548-1965

भारी कामों के लिए जलसूषण तथा जलनिकास नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

3. वायु नम्पनाल के लिए विनिर्देश

भा० प्रा० 446-1968

बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले रबर के वायु नम्पनाल के लिये भारतीय मानक विनिर्देश।

भा० प्रा० 911-1968

गोलाई में बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले रबर के वायु नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

4. तेल-रोधी नम्पनाल के लिए विनिर्देश

भा० प्रा० 635-1968

बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले तेल तथा विलायक रोधी रबर के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

भा० प्रा० 2396-1968

गोलाई में बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले पेट्रोल तथा डीजल ईंधनों के लिए रबर के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

भा० प्रा० 3418-1968

गोलाई में बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले तेल तथा विलायक रोधी रबर के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

5. वैल्विंग के नम्पनाल के लिए विनिर्देश

भा० प्रा० 447-1968

बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले वैल्विंग के रबर के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

भा० प्रा० 3572-1968

गोलाई में बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले वैल्विंग के रबर के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

6. छिड़काव नम्पनाल के लिए विनिर्देश

भा० प्रा० 1677-1968

गोलाई में बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले कृषि छिड़काव के रबर के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

7. रेडियेटर के नम्पनाल के विनिर्देश

भा० प्रा० 2765-1968

रेडियेटर के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

8. अग्नि शमन नम्पनाल के लिए विनिर्देश

- भा० मा० 2410-1963 अग्नि शमन सेवाओं के लिए रबर के चूषण नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।
- भा० मा० 5132-1969 अग्नि शमन के लिए नम्पनाल रील द्यूविंग के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।
- भा० मा० 884-1969 स्थिर रूप से लगाने के लिए प्राथमिक उपचार नम्पनाल रील के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।
- भा० मा० 636-1962 रबर के अन्तर वाले बुने हुए जाकेट के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

9. सीमेंट भराई के नम्पनाल के लिए विनिर्देश

- भा० मा० 5137-1969 बुने हुए कपड़े के प्रबलन के सीमेंट भराई के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।
- भा० मा० 5166-1969 गोलाई के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

10. गर्म पानी के नम्पनाल के लिए विनिर्देश

- भा० मा० 5937-1970 गोलाई के बुने कपड़े के प्रबलन वाले रबर के गर्म पानी के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।
- भा० मा० 5821-1970 बुने हुए कपड़े के प्रबलन वाले रबर के गर्म पानी के नम्पनाल के लिए भारतीय मानक विनिर्देश।

टिप्पणः—यदि ऊपर विनिर्दिष्ट किसी भी नम्पनाल के बारे में भारतीय मानक संख्या द्वारा सुसंगत विनिर्देशों के संबंध में बाद में कोई विवरण दिया गया हो तो ऐसे नम्पनाल को सबसे बाद विनिर्देश ही लागू होंगे, ऊपर यथावर्तिन तत्संबंधी प्रकृष्टि में वर्णित विनिर्देश नहीं।”

[सं० 6(36)/72-नि०नि० और नि० सं०]

ORDER

S.O. 1624.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S.O. 1004, dated the 23rd March, 1967 regarding rubber houses in the manner specified below, for the development of export trade of India;

And whereas the Central Government has forwarded the proposals in that behalf to the Export Inspection Council, 28 G of I/73—5

as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality control and Inspection) Rules, 1964 :

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions in respect of the said proposals may forward the same within thirty days from the date of publication of this Order in the official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

In the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S.O. 1004, dated the 23rd March, 1967.

(i) in Annexure I, after serial No. 13 and the entry relating thereto, the following serial Numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“14. Fire Fighting Hose.

15. Cement Grouting Hose.

16. Hot Water Hose.”

(ii) for Annexure II, the following Annexure shall be substituted, namely:-

Annexure II

Standards Specifications for Rubber Hoses

1. Specifications for Water delivery hose:

IS: 444-1968 : Indian Standard Specification for Water hose of rubber with woven textile reinforcement.

IS: 913-1968 : Indian Standard Specifications for Water hose of rubber with braided textile reinforcement.

2. Specification for Water suction hose:

IS: 2482-1963 : Indian Standard Specification for water suction hose of rubber, light duty.

IS: 3549-1965: Indian Standard Specification for Water Suction and discharge hose of rubber, heavy duty.

3. Specifications for air hose:

IS : 446-1968 : Indian Standard Specification for Air hose of rubber with woven textile reinforcement.

IS: 911-1968 : Indian Standard Specification for Air hose of rubber with braided textile reinforcement.

4. Specification for Oil resistant hose:

IS: 635-1968 : Indian Standard Specification for oil and solvent resistant hose of rubber with woven textile reinforcement.

IS: 2396-1968 : Indian Specification for Rubber hose for petrol and diesel fuels with braided textile reinforcement.

IS: 3418-1968 : Indian Standard Specification for oil and solvent resistant hose of rubber with braided textile reinforcement.

5. Specification for welding hose:

IS: 447-1968 : Indian Standard Specification for Welding hose of rubber with woven textile reinforcement.

IS: 3572-1968 : Indian Standard Specification for Welding hose of rubber with braided textile reinforcement.

6. Specification for spray hose:

IS: 1677-1968: Indian Standard Specification for Agricultural spray hose of rubber with braided textile reinforcement.

7. Specification for radiator hose:

IS: 2765-1964: Indian Standard Specification for radiator hose.

8. Specification for Fire Fighting hose:

IS: 2410-1963: Indian Standard Specification for suction hose of rubber for fire services.

IS: 5132-1969: Indian Standard Specification for Hose reel tubing for fire fighting.

IS: 884-1969: Indian Standard Specification for First aid hose reel for fixed installation.

IS: 636-1962: Indian Standard Specification for Rubber lined woven jacked.

9. Specification for Cement Grouting hose:

IS: 5137-1969: Indian Standard Specification for Cement Grouting Hose of rubber with woven textile reinforcement.

IS: 5166-1969: Indian Standard Specification for Cement Grouting Hose of rubber with braided textile reinforcement.

10. Specification for Hot Water hose:

IS: 5937-1970: Indian Standard Specification for Hot water hose of rubber with braided textile reinforcement.

IS: 5821-1970: Indian Standard Specification for Hot water hose of rubber with woven textile reinforcement.

Note:—If in respect of any Hose specified above, there are any later versions to the relevant specifications by the Indian Standards Institution, the specifications applicable to such Hose shall be the latest of such versions and not the specifications mentioned in the corresponding entry as shown above.

[No. 6(36)/72-EI&EB]

का. आ. 1625.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मछली और मछली उत्पाद का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम मछली और मछली उत्पाद का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. मछली और मछली उत्पाद का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 4 में,—

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अभिकर्ण मछली और मछली उत्पाद के परेक्षण का निरीक्षण इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह उपर्युक्त नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। निर्यातकर्ता अभिकर्ण को

ऐसी सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके।”

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकर्ण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाली मछली या मछली उत्पादों का परेक्षण नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तो अभिकर्ण परेक्षण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र—

(1) प्रशोधित भिंगा मछली (श्रिम्प) की दशा में सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर देगा, और

(2) लवण जल में डिब्बा बंद या सूखे पैक की हुई भिंगा मछली (श्रिम्प) की दशा में सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के अंदर देगा :

परन्तु जहां अभिकर्ण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है वहां वह भिंगा मछली (श्रिम्प) की दशा में उक्त सात दिनों की अवधि के भीतर और लवण जल में डिब्बा बंद या सूखे पैक की हुई भिंगा मछली (श्रिम्प) की दशा में दस दिनों के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण देते हुए उसकी संसूचना निर्यातकर्ता को देगा।”

[सं. 6(26)/72-नि. नि. और नि. सं.]

S.O. 1625.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fish & Fish Products (Inspection) Rules, 1964, namely:—

1. These rules may be called the Export of Fish & Fish Products (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Fish & Fish Products (Inspection) Rules, 1964—(a) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:

“(3) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Fish & Fish Products as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.”

(b) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted namely:

“(4) If after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Fish and Fish Products to be exported complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3, the Agency shall issue a certificate declaring the consignment as export-worthy.”

(i) Within seven days of the receipt of intimation in case of frozen prawns (Shrimps), and

(ii) Within ten days of the receipt of intimation in case of prawns (shrimps) canned in brine or dry packed:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days in the case of frozen prawns (shrimps) and of ten days in the case of prawns (shrimps) canned in brine or dry packed refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.”

[No. 6(26)/72-EI & EP.]

का. आ. 1626.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम भिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. भिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971 के नियम 4 में—

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण भिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग के परेण का निरीक्षण, इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अपना यह समाधान करने के लिए करेगा कि परेण उपर्युक्त नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसी सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके।

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले भिंगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग का परेण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर परेण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है, वहां वह उक्त सात दिनों की अवधि के अंदर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण देते हुए उसकी सूचना निर्यातकर्ता को देगा।

[सं. 6 (26)/72-नि. नि. और नि. सं.]

S.O. 1626.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Rules, 1971.

1. These rules may be called the Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Rules, 1971—(a) for sub-rule (3) the following shall be substituted namely :—

“(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of frozen lobster tails as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf, from time to time, with a view to satisfying itself that the consignment complies with the requirements of the recognised specifications referred to in 3 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.”

(b) For sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely :

“(4) If after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of frozen lobster tails to be exported, complies with the requirements of the specifications

referred to in rule 3, it shall, within 7 days of the date of receipt of intimation, issue a certificate declaring the consignment as export-worthy :

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of 7 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.”

[No. 6(26)/72-EI & EP]

का. आ. 1627.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार सुखाए हुए शार्क पंख और सुखाए हुए मछली वाताशय का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम सुखाए हुए शार्क पंख और सुखाए हुए मछली वाताशय का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन, नियम, 1973 है।

2. सुखाए हुए शार्क पंख और सुखाए हुए मछली वाताशय का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 के नियम 4 में—

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण सुखाए हुए शार्क पंख और सुखाए हुए मछली वाताशय के परेण का निरीक्षण इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह उपर्युक्त नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसी सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके।”

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाला सुखाए हुए शार्क पंख और सुखाए हुए मछली वाताशय का परेण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह सूचना प्राप्त होने के पांच दिनों के अंदर परेण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है, वहां वह उक्त पांच दिनों की अवधि के अंदर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण देते हुए उसकी सूचना निर्यातकर्ता को देगा।”

[सं. 6 (26)/72-नि. नि. और नि. सं.]

S.O. 1627.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Dried Shark Fins & Dried Fishmaws (Inspection) Rules, 1969 namely :—

1. These rules may be called the Export of Dried Shark Fins & Dried Fishmaws (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Dried Shark Fins & Dried Fishmaws (Inspection) Rules, 1969—(a) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :

“On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of dried shark fins & dried fishmaws as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to seeing that the same complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspections.”

(b) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted namely :

“If after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of dried shark fins & dried fishmaws to be exported, complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within five days of the date of receipt of intimation, issue a certificate declaring the consignment as export-worthy :

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of five days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.”

[No. 6(26)/72-EI & EP]

का. आ. 1628.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार काजू की गिरी का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम काजू की गिरी का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है ।

2. काजू की गिरी का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968 के नियम 5 में :—

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर अभिकरण काजू की गिरियों के परेण का निरीक्षण इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अपना यह समाधान करने के लिए करेगा कि परेण उपयुक्त नियम 3 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार श्रेणीकृत, लेबल लगाया और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसी सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके ।

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाला काजू की गिरियों का परेण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर परेणों को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है, वहां वह उक्त सात दिनों की अवधि के अंदर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकार के कारण होते हुए उसकी संसूचना निर्यातकर्ता को देगा ।”

[सं. 6 (26)/72-नि. नि. और नि सं.]

S.O. 1628.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Cashew Kernels (Inspection) rules, 1966, namely :

1. These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 5 of the Export of Cashew Kernels (Inspection) Rules, 1966—(a) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :

“(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of cashew kernels as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfying itself that the consignment has been graded, labelled and packed in accordance with the rules referred to in rule 3 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such Inspection.”

(b) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely :

“(4) If after inspection the Agency is satisfied that the consignment of cashew kernels to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of intimation, issue a certificate declaring the consignment as export-worthy :

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.”

[No. 6(26)/72-EI & EP]

का. आ. 1629.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार मोंडक की टंगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम मोंडक की टंगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है ।

2. मोंडक की टंगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 में :—

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण मोंडक की टंगों के परेण का निरीक्षण इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह उपयुक्त नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसी सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके ।”

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाला मोंडक की टंगों का परेण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह सूचना प्राप्त होने की तारीख के 7 दिनों के अंदर परेण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है वहाँ वह उक्त सात दिनों की अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण दत्ते हुए उसकी संसूचना नियतिकर्ता को देगा।"

[सं. 6 (26)/72-नि. नि. और नि. सं.]

S.O. 1629.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965, namely:

1. (i) These rules may be called the Export of Frog Legs (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of Export of Frog legs (Inspection) Rules, (a) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(3) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of frog legs as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time with a view to seeing that the same complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection."

(b) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(4) If after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of frog legs to be exported, complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the date of receipt of intimation issue a certificate declaring the consignment as export-worthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor."

[No. 6(26)/72-EI & EP]

का. आ. 1630.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्तार (गम कराया) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम कर्तार (गम कराया) का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. कर्तार (गम कराया) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 में (क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, अभिकरण, कर्तार (गम कराया) के परेषण का निरीक्षण, इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह उपर्युक्त नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है। निर्यातिकर्ता अभिकरण को ऐसी सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके।"

"(5) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किया जाने वाला कर्तार (गम कराया) का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह परेषण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए प्रमाणपत्र—

- (1) बम्बई के अभिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने की वृत्ता में सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर देगा; और
- (2) दिल्ली के अभिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने की वृत्ता में सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर देगा:

परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है, वहाँ वह मुम्बई के अभिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने की वृत्ता में उक्त तीन दिनों की अवधि के अंदर और दिल्ली के अभिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने की वृत्ता में सात दिनों की अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण दत्ते हुए उसकी संसूचना नियतिकर्ता को देगा।"

[सं. 6 (26)/72-नि. नि. और नि. सं.]

S.O. 1630.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1965, namely:

1. These rules may be called the Export of Gum Karaya (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In rule 4 of the Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1965—(a) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Gum Karaya as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time with a view to seeing that the same complies with the requirements of rule 3 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection."

(b) for sub-rule (5) the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(5) If after inspection the Agency is satisfied that the consignment of gum karaya to be exported complies with the requirements of rule 3, it shall, issue a certificate declaring the consignment-wise as export-worthy.

(i) Within three days of the receipt of intimation in case of inspection conducted by the Agency at Bombay, and

(ii) Within seven days of the receipt of intimation in case of inspection conducted by the Agency at Delhi:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days in the case of inspection conducted by the Agency at Bombay and of seven days in the case of inspection conducted by the Agency at Delhi refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor."

[No. 6(26)/72-EI & EP]

का. आ. 1631.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल निष्कासित चावल की भूसी का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम तेल निष्कासित चावल की भूसी का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. तेल निष्कासित चावल की भूसी का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 3 के उपनियम (2) और नियम 4 ब

उपनियम (4) के स्थान पर क्रमशः निम्नीलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) निर्यात की जाने वाली तेल निष्कासित चावल की भूसी का निरीक्षण, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के लिए किया जाएगा कि तेल निष्कासित चावल की भूसी उससे लागू मानकों के अनुरूप हैं। निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसी सभी आवश्यक सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके।”

(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् घुमन अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात की जाने वाली तेल निष्कासित चावल की भूसी का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, तो वह परेषण को निर्यात-यांग्य घोषित करते हुए आठ दिन के अंदर एक प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं है पाया है वह उस आठ दिनों की अवधि के अंदर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण देते हुए उसकी संसूचना निर्यातकर्ता को देगा।”

[सं. 6 (26)/72-नि. नि. और नि. सं.]

S.O. 1631.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Rules, 1966, namely :

1. These rules may be called the Export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In the export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Rules, 1966., the sub-rule (2) of rule 3 and the sub-rule (4) of rule 4 shall be substituted respectively, with the following, namely :

“3(2) The inspection of de-oiled rice bran intended to be exported shall be carried out as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time with a view to seeing that the de-oiled rice bran complies with the standards applicable to it. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.”

“4(4) If after the inspection the fumigation Agency is satisfied that the consignment of de-oiled rice bran to be exported complies with the requirements of rule 3, it shall within 8 days issue a certificate declaring the consignment as export worthy.

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of 8 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.”

[No. 6(26)/72-EI & EP]

आदेश

का. आ. 1632.—यत्तः केंद्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि पटसन से बनी वस्तुएं निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी,

और यत्तः केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3395, तारीख 14 अक्टूबर, 1970 में किए गए प्रस्तावों को अधिस्तृत करते हुए उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केंद्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को तत्काल संभाव्यतः प्रभावित होने वाले लोगों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है।

2. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 14/बी, एजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि पटसन से बनी वस्तुएं निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी,

(2) पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 के अनुसार उपाबन्ध में दिए गए क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना, जो कि ऐसी पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात से पूर्व लागू होगा,

(3) (क) (1) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा ऐसे गणकों की परीक्षा एवं अनुमोदन के प्रयोजनार्थ नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों को,

(2) भारतीय मानक संस्थान द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों को, यदि कोई हो,

परन्तु यह तब जब कि वे संविदात्मक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(ख) ऐसे मानक विनिर्देशों के अभाव में, जैसे कि ऊपर के 3 (क) में दिए गए हैं, निर्यात संविदा में दिए गए विनिर्देशों या किसी अन्य विनिर्देश को, जैसा कि परिषद् समीक्षित समझे, मान्यता देना।

टिप्पण—ऐसे किसी मामले में, जिसमें मिस/निर्यातकर्ता का यह विचार है कि (3) के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देश ऐसे हैं कि वे किसी माल के विशिष्ट बाजार में बाधा डालते हैं तथा अतः, विहित विनिर्देशों से भिन्न विनिर्देशों का माल स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, वह ऐसी परिषद् को प्रीनवेदन भेज सकेगा जो कि प्रस्ताव की ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह यांग्य समझती है तथा, यदि आवश्यक हो, तो उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल से परामर्श करने के पश्चात्, ऐसे उपांतरित विनिर्देशों के अनुसार, जिनका कि वह अनुमोदन करती है, ऐसे देश को निर्यात को अनुज्ञात कर सकेगी।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में पटसन से बनी ऐसी वस्तुओं के निर्यात का तब तक प्रतिबंध करनी है जब तक कि उस पर भा. मा. सं. प्रमाणीकरण विन्ध न लगा हो या उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में

से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि पटसन से बनी वस्तुओं का परीक्षण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की शर्तों को पूरा करता है तथा मानक विनिर्देशों के अनुरूप है एवं निर्यात के प्रयोजनार्थ स्वीकार्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात स्थल-मार्ग, जल-मार्ग या वायु-मार्ग द्वारा पटसन से बनी वस्तुओं के नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब कि भावी श्रेता के लिए परीक्षण का पो. प. नि. मूल्य एक सौ रुपये से अधिक न हो।

3. परिभाषा :—इस आदेश में पटसन से बनी वस्तुओं से टाट तथा बोरों, कालीन के अस्तर का कपड़ा, थैले बनाने का कपड़ा तथा ऐसे बोरों जिनमें ऊन की गठियाँ (पैक) तथा रूई की गाँठों को लपेटने के लिए पटसन का टाट भी सम्मिलित हैं, सभी किस्मों अभिप्रेत हैं।

उपाधन

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973 है।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है।

(ख) “अभिकरण” से अधिनियम, की धारा 2 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई और विल्ली में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) “परिषद्” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है।

(घ) “पटसन से बनी वस्तुओं” से टाट तथा बोरों, के कालीन के अस्तर का कपड़ा थैले बनाने का कपड़ा तथा ऐसे बोरों की जिनमें ऊन की गठियाँ (पैक) तथा रूई की गाँठों को लपेटने के लिए पटसन का टाट भी सम्मिलित है सभी किस्मों अभिप्रेत है।

3. प्रक्रिया में क्वालिटी नियंत्रण :—निर्यात के लिए आशीर्षित पटसन से बनी वस्तुओं की क्वालिटी यथा नीचे दिए गए नियंत्रणों के स्तरों के साथ-साथ विनिर्माण की विविध अवस्थाओं पर निम्नलिखित नियंत्रण को लागू करके विनिर्माता मिल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी :

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिर्मित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, एक प्रयोगशाला तथा निरीक्षण विभाग बनाए रखे जाएंगे जो परिषद् द्वारा सूचित बार-बारता के अनुसार परख तथा निरीक्षण को क्रियान्वित करने के लिए उपकरणों द्वारा समुचित रूप से सज्जित रखे जाएंगे तथा उस कार्य के लिए कर्मचारीयों को रखा जाएगा।

(2) परखों एवं निरीक्षण के सभी अभिलेख परिषद् द्वारा विहित रीति से रखे जाएंगे और परिषद् अभिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) (1) इन नियमों से संलग्न परिशिष्टों एवं सारिणियों में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों पर परखें तथा निरीक्षण, मिल के सभी उत्पादन पर किए जाएंगे तथा समुचित अभिलेख तथा चार्ट नियमित एवं प्रायिक रूप से रखे जाएंगे।

(2) इन नियमों के अधीन निरीक्षण के प्रयोजन के लिए फिनिशिंग विभाग की एक पारी में समान धशाओं के अधीन विनिर्मित एक ही प्रकार तथा क्वालिटी के सभी टाट तथा बोरों बनाने का कपड़ा। टाट तथा सैंकिंग के बोरों/कालीन के अस्तर का कपड़ा एक नियंत्रण यूनिट बनेगा।

(3) माल पर उचित पहचान चिन्ह लगा रहेगा ताकि जब कभी आवश्यक हो, सुधार संबंधी कार्रवाई करने के लिए उनको बनाने वाली विशिष्ट मशीन का पता लगाया जाए।

(4) परखों :—(क) टाट तथा बोरों बनाने का (सैंकिंग) कपड़ा जैसा कि परिशिष्ट “क” में दिया गया है।

(ख) पटसन के बूल-यैक जैसा कि परिशिष्ट “ख” में दिया गया है।

(ग) रूई की गाँठों को लपेटने के लिए पटसन का थैले का कपड़ा (बैगिंग) जैसा कि परिशिष्ट “ग” में दिया गया है।

(घ) टाट के बोरों। सैंकिंग के बोरों जैसा कि परिशिष्ट “घ” में दिया गया है।

(ङ) कालीन के अस्तर का कपड़ा जैसा कि परिशिष्ट “ङ” में दिया गया है।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद समुचित विनिर्देशों की विभिन्न अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, कारखाना, उत्पादन के प्रत्येक प्रक्रम पर समुचित नियंत्रण तथा जांच करता रहेगा।

(5) ऐसे नियंत्रण यूनिटों, जो विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं की अस्वीकृत से संबंधित जानकारी ऐसे हुए अलग अभिलेख रखा जाएगा।

(6) यदि किसी समय उत्पाद की विनिर्देशों से अनुरूपता बनाए रखने में कोई कठिनाई होती है, या परख-यंत्र बिगाड़ जाता है, या किसी कारण ऐसा करने के लिए यदि अभिकरण से निदेश प्राप्त होता है, तो निर्यात के लिए पटसन की वस्तुओं का विनिर्माण अभिकरण एवं परिषद् को सूचना देते हुए स्थगित कर दिया जाएगा। वस्तुएं विनिर्देश की अनुरूपता के अनुसार पास होने पर या साधन के ठीक किए जाने पर या अभिकरण के ऐसे निदेश देते ही निर्यात के लिए उत्पादन पुनरारंभ किया जाएगा। निर्यात के लिए उत्पादन के पुनरारंभ सम्बन्धी जानकारी अभिकरण तथा परिषद् को भी भेजी जाएगी।

4. सैंकिंग से पूर्व निरीक्षण :—मिलों द्वारा की गई परखों के अतिरिक्त निर्यात के लिये विनिर्मित प्रत्येक नियंत्रण यूनिट का अभिकरण द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

(1) यदि अभिकरण द्वारा की गई परखों द्वारा मानक विनिर्देशों की एक या अधिक अपेक्षाओं में अभाव दिखाई देता है, तो माल रद्द (अस्वीकृत) कर दिया जाएगा।

(2) यदि लिए गए नमूने मानक विनिर्देशों की अपेक्षाओं की अनुरूपता इंगित करते हैं, तो माल निर्यात के लिए सैंकिंग करने हेतु, पास कर दिया जाएगा।

5. सैंकिंग और चिह्नन :—नियम 4 के अनुसार पास किए जाने पर माल की मानक विनिर्देशों में दी गई अपेक्षाओं, यदि कोई हों, के अनुसार सैंकिंग की जाएगी और (उस पर) निम्नलिखित जानकारी चिह्नित की जाएगी :

- (क) विनिर्माता का नाम तथा या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, यदि कोई हो।
- (ख) गांठ/रोल संख्या
- (ग) कुल भार
- (घ) शुद्ध भार
- (ङ) माल का नाम
- (च) मात्रा
- (छ) भारत और आयात करने वाले देश में प्रवृत्त विधि द्वारा अपीक्षित कोई अन्य जानकारी।

6. स्टाम्प लगाया :—नियम 4 के अनुसार निरीक्षित माल की प्रत्येक गांठ/रोल पर इस प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित स्टाम्प अभिकरण द्वारा लगाया जाएगा।

7. निर्यात से पूर्व निरीक्षण :—(1) अभिकरण निर्यात के लिए पटसन से बनी वस्तुओं के परीक्षण का निरीक्षण, अनुदेशों के अनुसार तथा ऐसी बारंबारता पर निर्यात के पूर्व करेगा, जो इस निमित्त प्रत्येक मिल के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) निरीक्षण का आधार :—पटसन की वस्तुओं का निरीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि वे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मानक विनिर्देश कहा गया है) के अनुरूप हैं।

(3) निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) पटसन से बनी वस्तुओं को निर्यात करने की वांछा करने वाला निर्यातकर्ता/मिल ऐसा करने की अपने आशय की लिखित सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ, ऐसे निर्यात से संबंधित सविज्ञा में दिए गए विनिर्देशों की घोषणा किसी निकटतम अभिकरण के कार्यालय को देगा, जिससे कि वह नियम 7 के अनुसार निरीक्षण कर सके। वे ऐसी सूचना के साथ यह घोषणा भी देंगे कि पटसन से बनी वस्तुओं के परीक्षण का विनिर्माण नियम 3 के अधीन निर्दिष्ट नियंत्रण के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग करते हुए किया गया है, और परीक्षण इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(2) निर्यातकर्ता/मिल परीक्षण की प्रत्येक गांठ/रोल पर लगाए गए पहचान चिह्न को भी अभिकरण के निकटतम कार्यालय को देगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा विनिर्माता के परिसर से परीक्षण के भेजे जाने के कम से कम तीन दिन पहले अभिकरण के निकटतम कार्यालय में पहुंच जाएगी।

(4) उप-नियम (3) (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण नियम 7 तथा इसके लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार पटसन से बनी वस्तुओं का निरीक्षण करेगा।

(5) यदि पटसन से बनी वस्तुएं अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती, तो अभिकरण मिल/निर्यातकर्ता को उप-नियम 3 (1) के अधीन आयंदा की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर तदनुसार सूचना देगा।

8. निरीक्षण का प्रमाण-पत्र :—अपना स्वयं यह समाधान करने के पश्चात् कि पटसन से बनी वस्तुएं नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुसार विनिर्मित की गई हैं तथा निरीक्षण करने पर माल अधिनियम की धारा 6 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं, अभिकरण सूचना तथा घोषणापत्र प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर उप-नियम 3 (1) अधीन परीक्षण को निर्यात-योग्य करते हुए प्रमाण-पत्र दे देगा :

परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया है, वह वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए इसे इंकार की सूचना उसके कारण सीहत निर्यातकर्ता को दे देगा।

9. परख के लिए सुविधाएं :—स्कीम के अनुसार मिल नमूना लेने तथा परखने के लिए सभी सुविधाएं देगा।

10. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए पटसन से बनी वस्तुओं का निरीक्षण मिलों के परिसर में किया जाएगा।

11. निरीक्षण फीस :—निरीक्षण के लिए सूचना के साथ पटसन से बनी वस्तुओं के निरीक्षण के लिए निम्नीलिखित दर पर निरीक्षण फीस के रूप में फीस दी जाएगी।

(क) कालीन के अस्तर का कपड़ा 5.25 रु. प्रति मीट्रिक टन

(ख) टाट/बोर 3.00 रु. प्रति मीट्रिक टन

(ग) थैले बनाने का कपड़ा (सैकिंग)/थैले। अन्य 1.50 रु. प्रति मीट्रिक टन

12. परीक्षण के अनुसार निरीक्षण :—यदि किसी समय किसी कारण उक्त 3 से 7 तक नियमों में दिए गए उपबंधों के अनुसार प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण उपायों को लागू करने में कोई कठिनाई हो, तो पोत-लदान पूर्व निरीक्षण परीक्षण के अनुक्रम में निम्नीलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :

(1) मिल/निर्यातकर्ता परिषद् को लिखित रूप में वे परिस्थितियां सूचित करेगा जिनके अधीन 3 से 7 तक नियमों का पालन नहीं हो सकता और

(2) परिषद् ऐसी परीक्षा एवं सत्यापन के पश्चात्, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, प्रत्येक निर्यात सविज्ञा के लिए प्रत्येक लाट के आधार पर पटसन से बनी वस्तुओं के निरीक्षण की अनुमति दे सकेगी।

(3) ऐसे निरीक्षणों के लिए नियम 11 में विनिर्दिष्ट दृग्गती दरों पर निरीक्षण फीस प्रभारित की जाएगी।

13. अपील :—(1) नियम 8 के अधीन अभिकरण के प्रमाण-पत्र जारी करने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए न्यूनतम तीन व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(3) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट 'क'

गारणी—टाट/बैले बनाने के कचड़े (सैकिंग) के लिए नियंत्रण के स्तर

| क्रम सं० | अपेक्षा | नमूने की संख्या | |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | चाक्षुष निरीक्षण | सभी टुकड़े | |
| 2 | चौड़ाई | प्रत्येक दो घंटे के उत्पादन में से पांच टुकड़े | प्रति नियंत्रण यूनिट के न्यूनतम 20 टुकड़ा तक |
| 3 | ताने/डे०मी० | | |
| 4 | बाने/डे०मी० | | |
| 5 | भार—ग्रा/मी ² में | | |
| 6 | आर्द्रता पुनः ग्राह्यता | | |
| 7 | फटन भार | प्रत्येक दो घंटे के उत्पादन में से दो टुकड़े | प्रति नियंत्रण यूनिट के न्यूनतम 8 टुकड़ी तक |
| 8 | तेल की अन्तर्वस्तु | प्रत्येक चार घंटे के उत्पादन में से एक टुकड़ा | प्रति नियंत्रण यूनिट के न्यूनतम 2 टुकड़ी तक |

गारणी—टाट के रोलों के लिए नियंत्रण के स्तर

| क्रम सं० | अपेक्षा | नमूनों की संख्या | |
|----------|-------------------------------|---|---|
| 1 | चाक्षुष निरीक्षण | गारे रोल | |
| 2 | चौड़ाई | | |
| 3 | ताने/डे०मी० | प्रत्येक दो घंटे के उत्पादन में से दो रोल | प्रति नियंत्रण यूनिट के न्यूनतम 8 रोलों तक |
| 4 | बाने/डे०मी० | | |
| 5 | भार—ग्रा/मी० ² में | | |
| 6 | आर्द्रता पुनः ग्राह्यता | | |
| 7 | फटन भार | प्रत्येक दो घंटे के उत्पादन में से एक रोल | प्रति नियंत्रण यूनिट के न्यूनतम 1 रोलों तक (प्रत्येक रोल में से 1 मीटर के दस अलग-अलग टुकड़े लेना) |
| 8 | तेल की अन्तर्वस्तु | प्रत्येक 4 घंटे के उत्पादन में से एक रोल | प्रति नियंत्रण यूनिट के न्यूनतम दो रोलों तक |

परिशिष्ट 'ख'

पटमन का मूल पैक

| क्रम सं० | अपेक्षा | नमूनों की संख्या | |
|----------|--|-------------------------------|---|
| 1 | चाक्षुष निरीक्षण | सभी पैक | प्रति नियंत्रण यूनिट |
| 2 | पैक की विमाण (ऊचाई, लम्बाई चौड़ाई डील टार की विमाण नई मिली हुई फ्लैप की विमाण) | 15 पैक | —यथावत— |
| 3 | प्रति पैक भार | 15 बण्डल (प्रत्येक में 5 पैक) | प्रत्येक नियंत्रण यूनिट के उत्पादन की अवधि का सम्भावित करने के लिए पैक की अपेक्षित सं० को जानी चाहिए। |
| 4 | प्रति डे०मी० ताने तथा बाने | 15 पैक | |
| 5 | आर्द्रता पुनः ग्राह्यता | | |
| 6 | सफाई, लाल पट्टी तथा लेबल की स्थिति | 50 पैक | |
| 7 | कपड़े को फाड़ने का भार | 3 पैक | |
| 8 | सीजन का फाटन भार | | |
| 9 | तेल की अन्तर्वस्तु | 2 पैक | |

परिशिष्ट 'ग'

रई की गाटा का लपटन के लिए पटसन के थैलो का कपडा

| क्र०स० | अपेक्षा | तमना की सख्या |
|--------|---|-------------------------|
| 1 | सामान्य अपेक्षा | |
| 2 | तान तथा बाने | |
| 3 | लम्बाई और चौड़ाई | |
| 4 | प्रति मीटर भार | प्रति नियंत्रण यूनिट 20 |
| 5 | ताने तथा बाने का तत्तु-बिन्द्याम बट व (ग्रिड) | |

परिशिष्ट 'घ'

टाट/सैकिंग के बोरे

| क्र०स० | अपेक्षा | तमना की स० |
|--------|--------------------------------|---|
| 1 | बोरे की बाह्य लम्बाई और चौड़ाई | प्रति नियंत्रण यूनिट के 20 बोरे |
| 2 | प्रति बोरा भार | प्रत्येक दो घटे के उत्पादन से से 5 बोरे |
| 3 | सीवन की मजबूती | प्रति नियंत्रण यूनिट के 6 बोरे |
| | | एक नियंत्रण यूनिट के लिए गए पहेले तथा अन्तिम तमूनों से से प्रत्येक से तीन-तीन । |

हम स्कीम से अन्तर्दिष्ट बोरे को बनाने के लिए टाट/थैले बनाने वा (सैकिंग) कपडा परिशिष्ट 'क' के अनुसार परखा और पास किया जाएगा ।

परिशिष्ट 'ङ'

तापन के अस्तर का कपडा

| क्र० स० | अपेक्षा | तमना की सख्या |
|---------|---|---|
| 1 | सामान्य अपेक्षा | |
| 2 | ताने तथा बाने | |
| 3 | चौड़ाई | |
| 4 | श्री, बिम, थ्री तथा बिम मिश्रित ताने का अलग हो जाना | प्रत्येक नियंत्रण यूनिट से से प्रति क्वालिटी का एक-एक रोल |
| 5 | प्रति वर्ग मीटर भार | (रोलिंग मशीन के एक घांरी का उत्पादन) |
| 6 | प्रति रोल लम्बाई | |
| 7 | तेल की अन्तर्वस्तु | प्रत्येक नियंत्रण यूनिट से से |
| 8 | फटन भार | प्रति क्वालिटी तीन रोल । |

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

S.O. 1632.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), jute products should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose in supersession of the proposals contained in the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 33959 dated the 14th October, 1970, and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by Sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, World Trade Centre, 14/1-B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

- (1) To notify that jute products shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1973 as set out in the Annexure as the type of quality control and inspection which would be applied to such jute products prior to export;
- (3) To recognise—
 - (a) (i) the specifications approved by a panel of experts appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such standards;
 - (ii) specifications, if any, issued by the Indian Standards Institution, provided these meet the contractual requirements.
 as the standard specifications;
- (b) In the absence of such standard specifications as per 3(a) above, specifications stipulated in the export contract or any other specification, as the Council may deem appropriate.

Note : In any case in which the mill/exporter is of the view that the specifications recognised under (3) are such as inhibit export to a particular market and the buyers are willing to accept goods of specifications different from the one prescribed, it may make a representation to the Council which after such examination of the proposal as it may deem fit and if necessary after consulting the panel of experts appointed by it, may permit export to such country in accordance with such modified specifications as it may approve of.

- (4) Prohibits the export, in the course of international trade, of such jute products unless the same bears ISI certification mark or accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignment of jute products satisfies the conditions relating to quality control and inspection and conform to the standard specifications and are accepted for purposes of export.

2 Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of jute products to prospective buyers, provided the F.O.B. value of the consignment does not exceed rupees one hundred.

3. Definition:—In this order 'jute products' shall mean all varieties of Hessian Cloth and bags, Carpet Backing Cloth, Sacking Cloth and bags including wool packs and jute bagging for wrapping cotton bales.

ANNEXURE

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1973.

2. Definition:—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.
- (b) 'Agency' means the Export Inspection Agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act.
- (c) 'Council' means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act.
- (d) 'Jute products' mean all varieties of Hessian Cloth and bags, Carpet Backing Cloth, Sacking Cloth and bags including wool packs and jute bagging for wrapping cotton bales.

3 In-process Quality Control.—The quality of jute products intended for export shall be ensured by the manufacturing mill effecting the following control, at different stages of manufacture, together with the levels of control, as given below :

- (1) A laboratory and inspection department shall be maintained which shall be suitably equipped and staffed to carry out tests and inspection in accordance with the frequency advised by the Council to ensure that the products manufactured conform to the specifications.
- (2) All records of tests and inspection shall be maintained in the manner prescribed by the Council and shall be made available to the Council/Agency.
- (3) (i) The tests and inspection, as specified in the Appendices and the Tables appended to these rules and at the levels of control specified therein, shall be carried out on all the production of the mill and appropriate records and charts shall be regularly and systematically maintained.
- (ii) For the purpose of inspection under these rules all hessian and Sacking Cloth/hessian and sacking bags/carpet backing cloth of one type and quality manufactured under similar conditions in one single shift of the finishing department shall constitute a control unit.
- (iii) The material shall have suitable mark of identification so that they could be traced back to the particular machine manufacturing them for taking corrective action whenever necessary.
- (iv) Tests—
 - (a) Hessian and Sacking cloth as in Appendix 'A'
 - (b) Jute Woolpack as in Appendix 'B'.
 - (c) Jute Bagging for Wrapping Cotton Bales as in Appendix 'C'.
 - (d) Hessian Bags/sacking bags as in Appendix 'D'.
 - (e) Carpet Backing cloth as in Appendix 'E'.
- (4) At all stages of manufacture, the factory shall maintain appropriate control and checks to ensure that the product conforms to the various requirements of the appropriate specifications.
- (5) A separate record shall be maintained giving information relating to the rejection of control units, which do not conform to the specification.
- (6) If, at any time, there is any difficulty in maintaining the conformity of the product to the specification, or the testing equipment goes out of order, or if directed to do so by the Agency for any reason, the manufacture of jute products for export shall be suspended under intimation to the Agency and to the Council. The production for export may be resumed as soon as the articles are passed in con-

formity with the specification or the equipment is restored or the Agency so directs. The information regarding resumption of production for export shall also be sent to the Agency and to the Council.

4 Inspection prior to packing.—In addition to tests by mills each control unit manufactured for export shall be inspected by the Agency.

- (1) If the tests done by the Agency indicate failure in any one or more requirement of the standard specification, the material shall be rejected.
- (2) If the samples drawn indicate conformity to the requirements of the standard specifications the material would be passed for packing for export.

5 Packing and marking.—The material passed in accordance with the rule 4 shall be packed as per the requirements, if any laid down in the standard specification and marked with the following information :

- (a) Name of manufacturer and/or registered trade mark, if any
- (b) Bale/roll number
- (c) Gross weight
- (d) Net weight
- (e) Name of the material
- (f) Quantity
- (g) Any other information required by the law in force in India and the importing country.

6 Affixation of Stamp.—Every bale/roll of the material inspected in accordance with rule 4 shall be stamped by the Agency with the Stamps approved for the purpose by the Council.

7. Inspection Prior to Export.—(1) The Agency shall carry out inspection of consignments of jute products prior to export in accordance with the instructions and at such frequencies as may be decided in this behalf by the Council from time to time for each mill.

(2) Basis of Inspection.—

view to seeing that the same conform to the specifications of jute products shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act (herein referred to as the standard specifications).

(3) Procedure of Inspection.—

- (i) The exporter/mill intending to export jute products shall give intimation in writing of his intention to do, and submit along with such intimation a declaration of the specifications stipulated in the Contract relating to such export to the nearest office of the Agency to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 7. They shall also submit along with such intimation a declaration that the consignment of jute products has been manufactured but exercising quality control measure as per Control referred to under rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose.
- (ii) The exporter/mill shall also furnish to the nearest office of the Agency the identification marks applied on each bale/roll of the consignment.
- (iii) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the nearest office of the Agency not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(iv) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3) (1), the Agency shall carry out the inspection of jute products in accordance with the rule 7 and the instruction in this behalf issued by the Council from time to time.

(v) If the jute products do not comply with the requirements, the Agency shall intimate the mill/exporter accordingly within 3 days of the receipts of application under sub-rule 3(i).

8. Certificate of Inspection.—After satisfying itself that the jute products have been manufactured as per the requirements of rule 3 and the materials on inspection conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, the Agency shall within three days of the receipt of intimation and declaration issue a certificate declaring the consignment as export-worthy under sub-rule 3(1).

Provided that where the agencies is not so satisfied it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with reason therefor.

9. Facilities for test.—The mill shall provide all facilities required for sampling and testing in accordance with the scheme.

10. Place of Inspection.—Inspection jute products for the purpose of these rules, shall be carried out at the premises of the mills.

11. Inspection Fee.—Fees at the following rates shall be paid as inspection fees for inspection of jute products along with the notice for inspection;

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| (a) Carpet Backing | — Rs. 5.25 per metric ton |
| (b) Hessian cloth/bags | — 3.00 per metric ton |
| (c) Sacking cloth/bags/others | — Rs. 1.50 per metric ton |

12. Consignmentwise Inspection.—If at any time, there is any difficulty in implementing in-process quality control and inspection measures in accordance with the provisions of rules 3 to 7 above due to any reason, pre-shipment inspection would be carried out on a consignment-wise basis in accordance with the following procedure :

- (1) The Mill/Exporter shall intimate in writing to the Council the circumstances under which the provisions of rules 3 to 7 can not be adhered to; and
- (2) The Council after such examination and verification as may be deemed necessary, may permit inspection of jute goods on a lot by lot basis against individual export contracts.
- (3) The inspection fee for such inspections would be charged at double the rates specified under rule 11.

13. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under rule 8, may within ten days of the receipt of the communications of such refusal, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons, as may be constituted for the purpose by the Central Government.

(2) The quorum of the panel shall be three.

(3) The decision of the panel on such appeal shall be final.

APPENDIX 'A'

TABLE - Levels of Control for Hessian/Sacking Cloth

| Sl. No. | Requirement | No. of samples | |
|---------|----------------------------|---|---|
| 1. | Visual inspection | All cuts | |
| 2. | Width | Five cuts from every two hours of production. | Subject to a minimum of 20 cuts per control unit. |
| 3. | Ends/dm | | |
| 4. | Picks/dm | | |
| 5. | Weight in g/m ² | | |
| 6. | Moisture regain | | |
| 7. | Breaking load | Two cuts from every 2 hours of production | Subject to a minimum of 8 cuts per control unit. |
| 8. | Oil content | One cut from every 4 hours of production. | Subject to a minimum of 2 cuts per control unit. |

TABLE—Levels of Control for Hessian Rolls

| Sl. No. | Requirement | No. of Samples | |
|---------|----------------------------|--|--|
| 1. | Visual Inspection | All Rolls | |
| 2. | Width | | |
| 3. | Ends/dm | Two Rolls from every two hours production. | Subject to a minimum of 8 rolls per control unit. |
| 4. | Picks/dm | | |
| 5. | Weight in g/m ² | | |
| 6. | Moisture regain | | |
| 7. | Breaking load | 1 roll from every 2 hrs. production | Subject to a minimum of 4 rolls (taking 2 separate pieces of 1 metre each from each roll per control unit. |
| 8. | Oil content | 1 roll from every 4 hrs. production. | Subject to a minimum of two rolls control unit. |

APPENDIX 'B'

JUTE WOOLPACK

| Sl. No. | Requirement | No. of samples | |
|---------|--|-----------------------------|--|
| 1. | Visual inspection | All packs per control unit. | |
| 2. | Dimension of pack (height, length, width loose top dimensions unsewn flap dimensions). | 15 packs per control unit. | |
| 3. | Weight per pack | 15 bundles (5 packs each) | Required number of packs should be drawn to cover the period of production every control unit. |
| 4. | Ends and picks per dm | 15 packs | |
| 5. | Moisture regain | | |
| 6. | Cleanliness, position of red stripe and label | 50 packs | |
| 7. | Breaking load of fabric | 3 packs | |
| 8. | Breaking load of seam | | |
| 9. | Oil content | 2 packs. | |

APPENDIX 'C'

JUTE BAGGING FOR WRAPPING COTTON BALES

| Sl No | Requirement | No. of sample |
|-------|------------------------------|----------------------|
| 1. | General requirement | 20 Per control unit. |
| 2. | Ends & Picks | |
| 3. | Length and width | |
| 4. | Weight per metre | |
| 5. | Tex (grist) of warp and weft | |

APPENDIX 'D'

HESSIAN/SACKING BAGS

| Sl. No. | Requirement | No. of samples |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| 1. Outside length and width of bag | 20 bags per control unit | Five bags from every two hours of production. |
| 2. Weight per bag | | |
| 3. Seam strength | 6 bags per control unit | Three each from the first and the last samples drawn from a control unit. |

The hessian/sacking cloth used in the manufacture of bags covered under the scheme shall be tested and passed as per Appendix 'A'

APPENDIX 'E'

CARPET BACKING CLOTH

| Sl. No. | Requirement | No. of samples |
|--|-------------|----------------|
| 1. General requirement | | |
| 2. Ends and Picks | | |
| 3. Width | | |
| 4. Bow, bias, combined bow and bias, weft fall-off | | |
| 5. Weight per square metre | | |
| 6. Length per roll | | |
| 7. Oil content | | |
| 8. Breaking load | | |

one roll per each quality from every control unit (single shift production of rolling machine).

3 rolls per each quality from every control unit.

[No. 6(18)/72-EI & EPI

K. I. MAJHUR, Under Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

(पेट्रोलियम विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 1973

क्र. आ. 1633.—लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं. क्र. आ. 870, तारीख 3 मार्च, 1972 और क्र. आ. 4146, तारीख 4 दिसम्बर, 1972 में निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में क्रम सं. 9 के सामने स्तंभ 1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी के स्थान पर, निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“महाप्रबन्धक, सिन्ध्री यूनिट,
भारत का उर्वरक निगम, सिन्ध्री”।

[क्र० सं० 26 (5)/73-खाप, 1]

ए. ए. वासुदेवन, अवर सचिव.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1633.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, in the Ministry of Works and Housing Nos. S.O. 870, dated 3rd March, 1972 and S.O. 4146 dated 4th December, 1972, namely:—

In the table below the said notification against Serial No. 9, for the entry in Column 1, the following entry shall be substituted, namely:—

“General Manager, Sindri Unit, Fertilizer Corporation of India, Sindri”.

A. A. VASUDEVAN, Under Secy
[F. No. 26(5)/73-Fert. I]

क्र. आ. 1634.—पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 28 अक्टूबर, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग-2 खण्ड 3(2) के पृष्ठों 4964-4965 पर प्रकाशित अधिसूचना क्र. आ. संख्या 3468 में पुलिस स्टेशन, हरीपाल, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल के लिए भूमि की अधिसूचना में:—

(1) मौजा बामनजोल (जे. एल. 93) पृष्ठ 4964 पर लाइन 34 में दूसरे कालम (प्लॉट संख्या) में ‘385’ के स्थान पर ‘386’ पढ़िये और उसी कालम में लाइन 35 में ‘399’ के स्थान पर ‘389’ पढ़िये।

(2) मौजा किसिमपुर (जे. एल. 112) पृष्ठ 4965 पर दूसरे कालम (प्लॉट संख्या) में ‘1236’ के स्थान पर ‘1296’ पढ़िये। और आखिरी लाइन के दूसरे, तीसरे तथा चौथे कालम की प्रविष्टियां निकाल दीजिए।

[सं. 11/2/72 एल एड एन]

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 29th May, 1973

ERRATUM

S.O. 1634.—In Notification No. S.O. 3468 under sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published at pages 1964-4965 of the Gazette of India, October 28, 1972, Part II Section 3(ii), for Police Station Haripal, District Hooghly, West Bengal, in the schedule of land for:—

(1) Mouza Bamanjol (J. I. 93) at Page 4964 in the second column (plot No.) in line 34 read ‘386’ in place

of '385' and in the same column in line 35 read '389' in place of '399'.

(2) Mouza Kasimerpur (J. L. 112) at page 4965 in the second column (plot no.) read '1296' in place of '1236' and omit the entries in the second, third and fourth columns of the last line.

[No. 11 2/72 L&I]

नई दिल्ली, 30 मई, 1973

शुद्धि-पत्र

का. आ. 1635.—पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग-2 खण्ड 3(2) के पृष्ठों 6027-6034 पर प्रकाशित अधिसूचना का. आ. 5372 के पुलिस स्टेशन डोमजोर, जिला हानड़ा, पश्चिमी बंगाल, के लिए भूमि की अनुसूची में :—

- (1) गांव राघवपुर (ज. ए. संख्या 35) पृष्ठ 6028 पर तीसरे कालम (सीमा क्षेत्र) में प्लॉट संख्या 850 के सामने 'दसवीं सार्जन' में '6.06' के स्थान पर '0.06' पढ़िये।
- (2) गांव भालुअरबर (ज. ए. 48) पृष्ठ 6031 पर दूसरे कालम (सर्वेक्षण संख्या) लाइन 53 में, '890' के स्थान पर '990' पढ़िये।

[सं. 11/4/71 लेबर एंड लेजिस]

New Delhi, the 30th May, 1973

ERRATUM

S.O. 1635.—In Notification No. S.O. 5372 under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published at pages 6027-6034 of the Gazette of India, December 30, 1972 Part (ii) Section 3(ii), for Police Station Bomjor, District Howrah, West Bengal, in the schedule of land, for :—

- (i) village Raghobpur (J. L. No. 35) at page 6028 in the third column (Extent-area) against plot No. 850 read "0.06" in place of "6.06" in line 10 (ten).
- (ii) village Jhaluarber (J. L. No. 48) at page 6031 in the second column (survey no's) read "990" in place of "890" in line 53.

[No. 11/4/71-L&I]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 1636.—पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग-2 खण्ड 3(2) के पृष्ठों 6012-6019 पर प्रकाशित अधिसूचना का. आ. 5371 में पुलिस स्टेशन चन्दीतल जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल, के लिए भूमि की अनुसूची में :—

- (1) गांव थरो (ज. ए. 52) पृष्ठ 6012 पर दूसरे कालम (सर्वेक्षण संख्या एवं भूमि का विवरण) में '1536' के स्थान पर '1436' पढ़िये और तीसरे कालम (सीमा क्षेत्र) में प्लॉट संख्या 1452 के सामने '0.05' के स्थान पर '0.005' पढ़िये।
- (2) गांव बामनडंगा (ज. ए. 53) पृष्ठ 6013 पर तीसरे कालम (सीमा क्षेत्र) प्लॉट संख्या 1333 के सामने '0.05' के स्थान पर '0.005' पढ़िये।

(3) गांव कालाचारा (ज. ए. 54) पृष्ठ संख्या 6013 पर तीसरे कालम में (सीमा क्षेत्र) प्लॉट संख्या 85 के सामने '5.57' के स्थान पर '5.67' पढ़िये।

(4) गांव जनार्द (ज. ए. 57) पृष्ठ 6014 पर तीसरे कालम में (सीमा क्षेत्र) प्लॉट संख्या 1238 के सामने '0.30' के स्थान पर '0.03' पढ़िये।

(5) गांव मोनीरामपुर (ज. ए. 64) पृष्ठ संख्या 6017 पर तीसरे कालम में (सीमा क्षेत्र) प्लॉट संख्या 2328 के सामने '0.40' के स्थान पर '0.04' पढ़िये।

(6) गांव माधवपुर (ज. ए. 74) पृष्ठ संख्या 6017 पर तीसरे कालम में (सीमा क्षेत्र) प्लॉट संख्या 328 के सामने '4.63' के स्थान पर '3.64' पढ़िये।

(7) गांव बक्स (ज. ए. 77) पृष्ठ संख्या 6018 पर तीसरे कालम (सीमा क्षेत्र) प्लॉट संख्या 1411 के सामने '3.45' के स्थान पर '4.45' पढ़िये।

(8) गांव खानपुर (ज. ए. 88) पृष्ठ संख्या 6019 पर तीसरे कालम (सीमा क्षेत्र) प्लॉट 165 के सामने '2.64' के स्थान पर '3.64' पढ़िये।

[सं. 11/4/71 एल एंड एल]

ERRATUM

S.O. 1636.—In Notification No. S.O. 5371 under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published at pages 6012—6019 of the Gazette of India, December 30, 1972, Part II/section 3(ii), for Police Station Chanditala, District Hooghly, West Bengal, in the schedule of land, for :—

(i) village Thero (J. L. No. 52) at page 6012 in the second column (Survey No's and description of land), read "1436" in place of "1536" and in the third column (Extent-area) against plot No. 1452, read "0.005" in place of "0.05".

(ii) village Bamandanga (J. L. No. 53) at page 6013 in the third column (Extent-area) against plot No. 1333, read "0.005" in place of "0.05".

(iii) village Kalachara (J. L. No. 54) at page 6013 in the third column (Extent-area) against plot No. 85 read "5.67" in place of "5.57".

(iv) village Janai (J. L. No. 57) at page 6014 in the third column (Extent-area) against plot No. 1238, read "0.03" in place of "0.30".

(v) village Monirampur (J. L. No. 64) at page 6017 in the third column (Extent-area) against plot No. 2328, read "0.04" in place of "0.40".

(vi) village Madhabpur (J. L. No. 74) at page 6017 in the third column (Extent-area) against plot No. 328, read "3.64" in place of "4.63".

(vii) village Baksa (J. L. No. 77) at page 6018 in the third column (Extent-area) against plot No. 1411, read "4.45" in place of "3.45".

(viii) village Khanpur (J. L. No. 88) at page 6019 in the third column (Extent-area) against plot No. 165, read "3.64" in place of "2.64".

[F. No. 11/4/71-L&I]

शुद्धि-पत्र

ERRATUM

का. आ. 1637.—पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 14 अक्टूबर, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग-2 खण्ड 3(2) के पृष्ठ 4154-4155 पर प्रकाशित अधिसूचना का. आ संख्या 2796 में एन्सकूरा पुलिस स्टेशन, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल, के लिए मौजा सारदाबासन (ज. एल. 305) के लिए भूमि की अनुसूची में दूसरे कालम (प्लॉट संख्या) में लाइन 8 में '3' के स्थान पर '31' पढ़िये और लाइन 9 में '3' के स्थान पर '32' पढ़िये।

[सं. 11/4/71 एल एण्ड एल]

बी. आर. भल्ला, अवर सचिव

[No. 11/4/71-L&U]

B. R. BHALLA, Under Secy.

श्रीधोगिक, विकास, विज्ञान तथा प्रादयोगिकी मन्त्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

का० आ० 1638—समय समय पर मण्डित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955, के विनियम 11 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिमूर्चित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल-3035 जिसका व्योम नोच दिया गया है 2 जनवरी, 1973 से मगहन के प्रबन्धको में परिवर्तन किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है

अनुसूची

| लाइसेंस संख्या और तिथि | लाइसेंसधारी का नाम और पता | रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी भारतीय मानक |
|-----------------------------|---|--|
| सी एम एल-30 35 30-3-1972 | मेनमें इंडस्ट्रियल प्लास्टिक (इंडिया) पी-47, हाइडरोड ऐक्सटेंशन, कलकत्ता-27 (कार्यालय 15 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16 में है) | केवल मध्यम साइज के औद्योगिक बचाव टोप (I.S. 2925-1964) |

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT,

SCIENCE AND TECHNOLOGY

सी. म. जी.

55 3035

(Indian Standards Institution)

New Delhi the 25th May 1973

S. O. 1638.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L 3035 particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 2 January, 1973 due to change in the management of the organisation:

SCHEDULE

| Licence No. and Date | Name and address of the Licensee | Article/process Covered by the Licence Cancelled & the Relevant Indian Standard |
|----------------------|---|---|
| CM/L-3035 30-3-72 | M/s Industrial Plastics (India), P-48, Hide Road Extension, Calcutta-27 having their office at 15, Park Street, Calcutta-16. | Industrial safety helmets of medium size only (IS:2925-1964) |

[No. CMD/55-3035]

नई दिल्ली, 28 मई, 1973

का० आ० 1639.—नोच जिन प्रमाणन मुहर लाइसेंसों के व्योम अनुसूची में दिए गए हैं या तो वे रद्द हो गए हैं अथवा उनका नवीकरण स्थगित कर दिया गया है।

अनुसूची

| क्रम संख्या | लाइसेंस संख्या तथा जारी करने की तिथि | लाइसेंसधारी का नाम और पता | वस्तु/प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी पदनाम | एस० आ० संख्या तथा लाइसेंस स्वीकृति छपने वाले गजट की तिथि | विथरण |
|-------------|--------------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सी०एम०/एल०-945 28-11-1964 | गंगा मैन्यूफैक्चरिंग लि०, डाकघर बामबोरिया, हुगली, (कार्या- लय 11 खीन्द्र सरणी कलकत्ता-1) | भारतीय टाट- IS 2818-1964 टाट के बोरे- IS 3790-1966 | एस० आ० 79 दिनांक 2-1-1965 | 31-11-1972 के बाद रद्द |
| 2 | सी०एम०/एल०-1370 26-12-1966 | नाहन फाउंडरी लिमिटेड, नाहन, जिला सिरमूर (हि०प्र०) | क्षैतिज आपकेंद्रीय पम्प- IS 1520-1960 | एस० आ० 243 दिनांक 21-1-1967 | इस लाइसेंस का नवीकरण 31-12-1969 के बाद स्थ- गित कर दिया था अब उसी। तिथि से यह रद्द हो गया है |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|--|-----|
| 3. सी० एम०/एल-1387 4-1-1967 | साइकिल इंडस्ट्रीज, (म० प्र० लघु उद्योग निगम लि०) इन्दौर का एक उद्यम ए० बी० रोड, गुना (म० प्र०)। | साइकिल के अगले चिमटे— IS : 2061-1962 | एम०ओ० 624 दिनांक 25-2-1967 | इस लाइसेंस का नवीकरण 31-1-1969 के बाद स्थगित कर दिया गया था, अब उसी तिथि से यह रद्द हो गया है। | |
| 4. सी० एम०/एल०-1396 28-2-1967 | कृषि रसायन, रानीताल जिला बाणामोर (उड़ीसा)। | एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव IS : 1310-1958 | एम०ओ० 1038 दिनांक 1-4-1967 | 15-2-1973 के बाद रद्द। | |
| 5. सी० एम०/एल०-1534 4-10-1967 | एम० सी० इंजीनियर्स, विवेणी रोड, पटियाला (पंजाब)। | हाकी स्टिक— IS : 829-1965 | एम०ओ० 4258 दिनांक 9-12-1967 | इस लाइसेंस का नवीकरण 30-4-1971 के बाद स्थगित कर दिया गया था, अब उसी तिथि से यह रद्द हो गया है। | |
| 6. सी० एम०/एल०-1678 22-4-1968 | हमराज महाजन एण्ड सन जी० टी० रोड, जलधर शहर। | हाकी स्टिक— IS : 829-1965 | एम०ओ० 2127 दिनांक 15-6-1968 | 15-9-1972 के बाद रद्द। | |
| 7. सी० एम०/एल०-1725 18-6-1968 | प्रमृत बनस्पति कं० लि०, जी० टी० रोड, गाजियाबाद (उ० प्र०) | 18 सीटर समारई वाले बर्गकार-टिन— IS : 916-1966 | एम०ओ० 2577 दिनांक 20-7-1968 | 15-12-1972 के बाद रद्द। | |
| 8. सी० एम०/एल०-1725 18-6-1968 | हमराज महाजन एण्ड सन जी० टी० रोड, जलधर शहर। | क्रिकेट बल्ला— IS : 828-1966 | एम०ओ० 2577 दिनांक 20-7-1968 | 15-9-1972 के बाद रद्द। | |
| 9. सी० एम०/एल०-2160 4-12-1969 | इस्मा जमाल युप धातुविज्ञान विभाग, निकट इंडियन आयल इन्स्टीटयूशन स्वास्तिक तेल मिल से अगला बडाला-बम्बई-31 | 18-सीटर समारई वाले बर्गकार टिन— IS : 916-1966 | एम०ओ० 437 दिनांक 7-2-1970 | 30-11-1972 के बाद रद्द। | |
| 10. सी० एम०/एल०-2242 9-2-1970 | दि गंगा मैन्यू० कं० लि० डाक-घर बांसबेरिया, हुगली (कार्यालय: 11-रवीन्द्र सरणी कलकत्ता-1) | ऊन बांधन के पटसन के बोरे- IS : 1856-1968 | एम०ओ० 1235 दिनांक 4-4-1970 | 30-11-1972 के बाद रद्द। | |
| 11. सी० एम०/एल०-2314 29-4-1970 | यूनाइटेड, पुल्वराहजर्म, बोयला, आगरा-7 | बी० एच० सी० जलविमर्जनीय तेज-चूर्ण IS : 562-1962 | एम० ओ० 1911 दिनांक 30-5-1970 | इस लाइसेंस का नवीकरण 31-9-1972 के बाद स्थगित कर दिया गया था, अब उसी तिथि से रद्द हो गया है। | |
| 12. सी० एम०/एल-2357 1-7-1970 | नेशनल गैरटोयारइम, 5-डंड-स्ट्रियल स्ट्रेट, विदिशा (म० प्र०) | एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव— IS : 1310 1958 | एम० ओ० 2109 दिनांक 29-5-1971 | इस लाइसेंस का नवीकरण 31-12-72 के बाद स्थगित कर दिया गया था, अब उसी तिथि से यह रद्द हो गया है। | |
| 13. सी० एम०/एल-2517 25-1-1971 | मनना स्टील रि-रोलिंग फाउंड्री मिल, इंडस्ट्रियल इस्टेट, मनना (म० प्र०) | संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1969 | एम० ओ० 5028 दिनांक 6-11-1971 | 31-1-1973 के बाद रद्द। | |
| 14. सी० एम०/एल-2518 25-1-1971 | „ „ | संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977-1969 | एम० ओ० 5028 दिनांक 6-11-1971 | 31-1-1973 के बाद रद्द। | |
| 15. सी० एम०/एल-2533 4-2-1971 | बलवंत प्राण इंजिनियर्स कं० प्रा० लि० 25-अबूल दूसरी बाई लेन, हाबड़ा-3 (कार्यालय : 9 कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता -1) | बिश्ली कार्यों के लिए बानिश किया सूती कपड़ा और टेप (टाइप 1 और 2) सभी साइजों में। IS : 3352-1965 | एम० ओ० 5037 दिनांक 6-11-1971 | 15-2-1973 के बाद रद्द। | |
| 16. सी० एम०/एल-2535 5-2-1971 | इंडस्ट्रियल केमिकल्स मिनरल्स, बी-25, सोनी रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद (उ० प्र०) | द्रवित इमारत लकड़-2-4 टी IS : 1827-1961 | एम० ओ० 5037 दिनांक 6-11-1971 | इस लाइसेंस का नवीकरण 15-2-1972 के बाद स्थगित कर दिया गया था, और अब उसी तिथि से इसको रद्द कर दिया है। | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----|
| 17 सी एम/एल-2734 12-8-1971 | दिल्ली केबल कं० प्रा० लि०, 29-नजफगढ़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-15 | पी बी सी रोहित केबल बिना खोल वाले, हकहरी कोर, 250/440 बोस्ट वाले एल्यू- मिनियम चालक— IS : 694 (भाग 2)-1964 | एम ओ 5031 दिनांक 6-11-1971 | 15-2-1973 के बाद रद्द | |
| 18. सी एम/एल-2865 7-1-1972 | हिन्दुस्तान वायर लि०, बी० टी० रोड, सूखार 24-परगना (ए० बंगाल) (कार्यालय : 16/5 चौंगी रोड, कलकत्ता- 13 में है) | सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मृदु इस्पात के तार— IS : 280-1962 | एम ओ 2777 दिनांक 7-10-1972 | 15-1-1972 के बाद रद्द | |
| 19. सी एम/एल-2870 14-1-1972 | इम्पेक्स ट्रेडर्स, 2135 मस्जिद खजूर धर्मपुरा दिल्ली-6 | पिटवा एल्युमिनियम के जर्नल ग्रेड एम आई सी— IS : 21-1959 | एम ओ 2777 दिनांक 7-10-1972 | 15-1-1973 के बाद रद्द | |
| 20 सी एम/एल-2880 17-1-1972 | बगलोर पेस्टीमाइडम लि०, 10 वा मील पत्थर, टुमकूर रोड, बम्बई-22 (कार्यालय : 7/4 मास्के रोड, बगलोर-20) | क्लोरोडैन पायसनीय तेज द्रव— IS : 2682-1966 | एस ओ 2777 दिनांक 7-10-1972 | 15-1-1973 के बाद रद्द | |
| 21. सी एम/एल-2893 31-1-1972 | ईस्टर्न इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेडर्स, 13/16, वयाराम नरकर लेन, हावड़ा, (कार्यालय : 402 चिन्मय रोड, कलकत्ता-7 में है) | चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970 | एम ओ 2777 दिनांक 7-10-1972 | 31-1-1973 के बाद रद्द | |
| 22 सी एम/एल-2934 23-2-1972 | राजाराम ब्रदर्स, मट्टू-सीमिच रोड, सबसोर (म० प्र०) | बस्त्र उद्योग के लिए डेकमेटाइट— IS : 5448-1969 | एम ओ 2801 दिनांक 14-10-1972 | 28-2-1973 के बाद रद्द | |
| लाईसेंस स्थगित | | | | | |
| 23 सी एम/एल-66 7-2-1958 | बुड काप्ट (ग्राम) जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, का एक (विभाग डाकघर मरायणी) जिला सिबसागर (ग्राम) कार्यालय : लाल द्वारा बिल्डिंग न्यू लिंक रोड, मन्डेवाला एम- टेशन नई दिल्ली -55 में है) | चाय की पेटियों के लिए प्लास्टिक के तबके— IS : 10-1970 | एम ओ 136 दिनांक 1-3-1958 | 28-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 24 सी एम/एल-351 31-10-1961 | भारत बुड वर्क प्रा० लि०, पी एण्ड टी ओ डिब्रूगढ़, जिला लखीमपुर (ग्राम) (कार्यालय : 35 चिरजन एवेन्यू तीसरी मंजिल, कलकत्ता-12 में है) | चाय की पेटियों के लिए प्लास्टिक के तबके— IS : 10-1970 | एम ओ 2708 दिनांक 18-11-1961 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 25. सी एम/एल-1686 30-4-1968 | पालम इंडस्ट्रीज, मुलतानपुर रोड कपूरथला | डोर क्लोजर्स (इव नियंत्रित) IS : 3564-1970 | एम ओ 2127 दिनांक 15-6-1968 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 26 सी एम/एल-1909 31-1-1969 | मोम इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, 96 बी, कोम्पार्टेड इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोविन्द नगर, कानपुर (उ० प्र०) | एक फेरी छोटी एसी और यूनि- वर्सल बिजली मॉटर, 'ए' श्रेणी के इंस्टालेशन लगी 40 वाट IS : 996-1964 | एम ओ 720 दिनांक 22-2-1969 | 31-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 27. सी एम/एल-1911 5-2-1969 | कृष्णा माइनर्स एण्ड ट्रेडर्स, 12- इंडस्ट्रियल जयपुर पश्चिम (राजस्थान) | एल्यूमिनियम धूल पाउडर— IS : 1308-1958 | एम ओ 1256 दिनांक 5-4-1969 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| 28. सी एम/एन-2199 8-1-1970 | स्टील इन्फ्रामेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, 22 जी टी रोड (उत्तर) डाकघर बिलुआ जिला (हवड़ा) | सरचना इस्पात (मानक किस्म) — IS : 226-1969 | एस प्रो 771 दिनांक 28-2-1970 | 15-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 29. सी एम/एन 2200 8-1-1970 | ” ” | सरचना इस्पात (माधारण किस्म) IS : 1977-1969 | एस प्रो 771 दिनांक 28-2-1970 | 15-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 30. सी एम/एन-2217 22-1-1970 | बनिक सघ प्रा० लि०, 77, राजा विनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-6 (कार्यालय : 15 बलाइव रोड, कलकत्ता में है) | चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970 | एस प्रो 77 दिनांक 28-2-1970 | 31-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 31. सी एम/एन-2122 7-10-1970 | नेशनल पेस्ट्रीमाइड्स, 5-इंडस्ट्रियल इस्टेट, बिदिणा (म० प्र०) | डी डी टी धूलन पाउडर— IS : 564-1961 | एस प्रो 561 दिनांक 30-1-1972 | 31-1-1972 के बाद स्थगित | |
| 32. सी एम/एन-2519 25-1-1971 | जगजीत इंडस्ट्रीज लि०, जगजीत नगर, हमीरा, जिला कपूरथला | टिक्सियां IS : 4449-1967 | एस प्रो 5028 दिनांक 6-11-1971 | 31-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 33. सी एम/एन-2520 25-1-1971 | सुदर्शन इंडस्ट्रीज, उद्योग नगर, तिनमुखिया, (असम) | चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970 | एस प्रो 5028 दिनांक 6-11-1971 | 31-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 34. सी एम/एन-2531 3-2-1971 | कमिको सीमेंट वाटर पुविंग इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, 34-पणपति भट्टाचार्य जी रोड, कलकत्ता-41 | जल रोक कार्यों के लिए सीमेंट का समेकित भसाला— IS : 2645-1964 | एस प्रो 5037 दिनांक 6-11-1971 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 35. सी एम/एन-2729 4-8-1971 | भार पुन्नुस्वामी नायडु एण्ड सन, 422-एडवार स्ट्रीट, कोयम्बटूर-1 (तमिलनाडू) | चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970 | एस प्रो 5031 दिनांक 6-11-1971 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 36. सी एम/एन-2883 24-1-1972 | कना परिवर्ष आगरा जाम रोड, (गेन्डूर) (प्रा० प्र०) | इजकों से बनी फाउंटैन पेन की स्पाही— IS : 1221-1957 | एस प्रो 5031 दिनांक 6-11-1971 | 31-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 37. सी एम/एन-2889 31-1-1972 | बी-बीधरी एण्ड कम्पनी, 27 डा० सुन्दरी मोहन, ऐवेन्यू, कलकत्ता 14 (कार्यालय : 162 ए-बिबेकानन्द रोड, कलकत्ता में है) | चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग— IS : 10-1970 | एस प्रो 5031 दिनांक 6-11-1971 | 31-1-1973 के बाद स्थगित | |
| 38. सी एम/एन-2898 4-2-1972 | स्विज बेल्डेड मेश क० (प्रा०) लि०, ए-7, इंडस्ट्रियल इमपेट, अम्बाटूर, मद्रास-58 | सामान्य उपयोग के लिए बेलडकृत इस्पात के तार की बुनी जानी IS : 4918-1968 | एस प्रो 2807 दिनांक 14-10-1972 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 39. सी एम/एन-2901 14-2-1972 | रीजनल विंग ब्रीड स्टेशन-कम बेकन फैक्टरी, हरिगंठटा, हरिगंठटा फार्म, डाकघर मोहनपुर, जिला तारिया (प० बंगाल) | सुअर का मांस— IS : 1723-1960 | एस प्रो 2801 दिनांक 14-10-1972 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 40. सी एम/एन-2905 14-2-1972 | ” ” | सुअर का मांस (साजेज)— IS : 3061-1965 | एस प्रो 2801 दिनांक 14-10-1972 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 41. सी एम/एन-2911 16-2-1972 | गोपालराम जातराम, 864-इंडस्ट्रियल एरिया 'ए' लुधियाना (पंजाब) | रंग के लिए छेददार स्टेनलेस इस्पात के शफु— IS : 4893-1968 | एस प्रो 2801 दिनांक 14-10-1972 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |
| 42. सी एम/एन-2917 16-2-1972 | असम प्लाईवुड प्राइवेट्स, कोका-जन जयपुर डाकघर जिला लखिमपुर (असम) | चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड की पेटियाँ— IS : 10-1970 | एस प्रो 2801 दिनांक 14-10-1972 | 15-2-1973 के बाद स्थगित | |

[सं० सी० एम० डी०/1314]

एस० क० सेन, महानिदेशक

New Delhi, the 28th May, 1973

S. O. 1639.—Certification Marks Licences, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have lapsed or their renewals deferred :

SCHEDULE

| Sl. No. | Licence No. and date of Issue | Name and Address of the Licensee | Article/Process and the Relevant Is: Designation | S.O. Number and the Date of the Gazette Notifying Grant of Licence | Remarks |
|---------|-------------------------------|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | CM/L-945 28-11-1964 | Ganges Manufacturing Co. Ltd., P.O. Bansberia, Hooghly (Office : 11 Rabindra Sarani, Calcutta-1) | Indian hessian-IS:2818-1964 Hessian bags-IS:3790-1966 | S.O. 79 dated 2-1-1965 | Lapsed after 30-11-1972 |
| 2. | CM/L-1370 26-12-1966 | Nahan Foundry Limited, Nahan, Distt. Sirmur (H.P.) | Horizontal centrifugal pumps-IS: 1520-1960 | S.O. 243 dated 21-1-1967 | Renewal was deferred after 31-12-1969 ; the licence now stands lapsed after that date. |
| 3. | CM/L-1387 9-1-1967 | Cycle Industries, (An undertaking of M.P. Laghu Udyog Nigam Ltd., (Indore), A.B. Road, Guna (M.P.)) | Bicycle front forks-IS: 2061-1962 | S.O. 624 dated 25-2-67 | Renewal was deferred after 31-1-1969; the licence now stands lapsed after that date. |
| 4. | CM/L-1396 28-2-1967 | Krishi Rasayan, Ranital, Distt. Balasore, (Orissa) | Endrin emulsifiable concentrates-IS: 13-10-1958 | S.O. 1038 dated 1-4-1967 | Lapsed after 15-2-1973 |
| 5. | CM/L-1534 4-10-1967 | Emcee Engineers, Terbeni Road, Patiala (Punjab) | Water meters-IS:779-1968 | S.O. 4258 dated 9-12-1967 | Renewal was deferred after 30-4-1971; the licence now stands lapsed after that date. |
| 6. | CM/L-1678 22-4-1968 | Hans Raj Mahajan & Sons, G.T. Road, Jullundur City | Hockey sticks-IS:829-1965 | S.O. 2127 dated 15-6-1968 | Lapsed after 15-9-1972 |
| 7. | CM/L-1719 12-6-1968 | Amrit Vanaspati Co. Ltd., G.T. Road, Ghaziabad (U.P.) | 18-Litre square tins-IS: 916-1966 | S.O. 2577 dated 20-7-1968 | Lapsed after 15-12-1972. |
| 8. | CM/L-1725 18-6-1968 | Hans Raj Mahajan & Sons, G.T. Road, Jullunder City | Cricket bats-IS: 8-28-1966 | S.O. 2577 dated 20-7-1968 | Lapsed after 15-9-1972 |
| 9. | CM/L-2160 4-12-1969 | Issa Jamall Group, Metallurgical Division Near Indian Oil Installations. Next to Swastik Oil Mills, Wadala, Bombay-31 | 18-Litre square tins-IS: 916-1966 | S.O. 437 dated 7-2-1970 | Lapsed after 30-11-1972 |
| 10. | CM/L-2242 9-2-1970 | The Ganges Mfg. Co. Ltd., Bansberia, Distt. Hooghly, (W.Bengal) (Office : 11 Rabindra Sarani, Calcutta-1) | New Jute wool pack-IS: 4856-1968 | S.O. 1235 dated 4-4-1970 | Lapsed after 30-11-1972. |
| 11. | CM/L-2314, 29-4-1970 | United Pulverisers, Bodla, Agra-7 | BHC water dispersible powder concentrates-IS: 562-1962 | S.O. 1911 dated 30-5-1970 | Renewal was deferred after 31-9-1972 ; the licence now stands lapsed after that date. |
| 12. | CM/L-2357 1-7-1970 | National Pesticides, 5, Industrial Estate, Vidisha (M.P.) | Endrin emulsifiable concentrates-IS : 1310-1958 | S.O. 2109 dated 29-5-1971 | Renewal was deferred after 31-12-1972 ; the licence now stands lapsed after that date. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------------|--|--|----------------------------|--|-----|
| 13. CM/L-2517 25-1-1971 | Satna Steel Re-rolling & Foundry Mill, Industrial Estate, Satna (M.P.) | Structural steel (standard quality)-IS : 226-1969 | S.O. 5028 dated 1971 | 6-11- Lapsed after 31-1- | |
| 14. CM/L-2518 25-1-1971 | Do. | Structural steel (ordinary quality)-IS:1977-1969 | S.O. 5028 dated 1971 | 6-11- Lapsed after 31-1- | |
| 15. CM/L-2533 4-2-1971 | Basant Pran Electric Co. Pvt. Ltd., 25, Andul 2nd Bye Lane, Howrah-3 (Office : 9 Court House Street, Calcutta-1) | Varnished cotton cloth and tapes for electrical purposes (Type 1 & 2 all sizes)-IS:3352-1965 | S.O. 5037 dated 1971 | 6-11- Lapsed after 15-2- | |
| 16. CM/L-2535 5-2-1971 | Industrial Chemicals & Minerals, B-25, Loni Road, Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) | Liquidamine salts of 2, 4- d-IS : 1827-1961 | S.O. 5037 dated 1971 | 6-11- Renewal was deferred after 15-2-1972, the licence now stands lapsed after that date. | |
| 17. CM/L-2734 12-8-1971 | Delhi Cables Co., Pvt. Ltd., 29, Najafgarh Road, Industrial Area, New Delhi-15. | PVC insulated cables, unsheathed, single core, 250/440 volts, aluminium conductors-IS : 694 (Part II)-1964 | S.O. 5031 dated 1971 | 6-11- Lapsed after 15-2- | |
| 18. CM/L-2865 7-1-1972 | Hindustan Wires Ltd., B.T. Road, Suckchar, 24 Parganas (W. Bengal) Office : 16/5, Chowringhee Road, Calcutta-13 | Mild steel wire for general engineering purposes-IS : 280-1962 | S.O. 2777 dated 1972 | 7-10- Lapsed after 15-1-1973 | |
| 19. CM/L-2870 14-1-1972 | Impex Traders 2135, Masjid Khajoor, Dharampura, Delhi-6 | Wrought aluminium utensils, Grade SIC-IS : 21-1959 | S.O. 2777 dated 1972 | 7-10- Lapsed after 15-1-1973 | |
| 20. CM/L-2880 17-1-1972 | Bangalore Pesticides Ltd., 10th Milestone, Tumkur Road, Bangalore-22 (Office : 7/4, Sambey Road, Bangalore-20) | Chlordane emulsifiable concentrates-IS : 2682-1966 | S.O. 2777 dated 1972 | 7-10- Lapsed after 15-1-1973 | |
| 21. CM/L-2893 31-1-1972 | Eastern Industries & Trade Centre, 13/16, Dayaram Naskar Lane, Howrah (Office : 402, Chitpur Road, Calcutta-7) | Tea-chest metal fittings— IS : 10-1970 | S.O. 2777 dated 1972 | 7-10- Lapsed after 31-1-1973 | |
| 22. CM/L-2934 23-2-1972 | Raja Ram Bros., Mhow-Neemuch Road, Mandasaur (M.P.) | Dextrine for textile industries-IS : 5448-1969 | S.O. 2801 dated 14-10-1972 | Lapsed after 28-2-1973 | |

LICENCES DEFERRED

| | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|
| 23. CM/L-65 7-2-1958 | Woodrafts (Assam), A Division of Jayshree Tea & Industries Limited., P.O. Marani, Dist. Sibsagar (Assam), (Office : Lal Dwara Bldg., New Link Road, Jhandewalan Extension, New Delhi-55). | Tea-chest plywood panels-IS : 10-1970 | S.O. 136 dated 1-3-1958 | Deferred after 28-2-1973 |
| 24. CM/L-351 31-10-1961 | Bhatat Wood Works Pvt. Ltd., P. & T O Dibrugarh, Dist. Lakhimpur (Assam) (Office : 35 Chittaranjan Avenue, 3rd floor, Calcutta-12). | Tea-chest plywood panel-IS : 10 1970 | S.O. 2708 dated 18-11-1961 | Deferred after 15-2-1973 |
| 25. CM/L-1686 30-4-1968 | Palsons Industries, Sultanpur Road, Kapurthala. | Door closers (hydraulically regulated IS : 3564-1970) | S.O. 2127 dated 15-6-1968 | Deferred after 15-2-1973 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------------|--|---|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 26. CM/L-1909 31-1-1969 | Som Engineering Corporation, 96 B, Co-operative Industrial Estate, Govind Nagar Kanpur (U.P.) | Single phase small ac and universal electric motors with Class 'A' insulation upto 40 watts-IS:996-1964 | S.O. 720 dated 22-2-1969 | Deferred 1973 | after 31-1- |
| 27. CM/L-1911 5-2-1969 | Krishna Mine's & Traders, 12, Industrial Area, Jaipur West (Rajasthan) | Aldrin dusting powders IS: 1308-1958 | S.O. 1256 dated 5-4- 1969 | Deferred 1973 | after 15-2- |
| 28. CM/L-2199 8-1-1970 | Steel Equipment & Construc- tion Pvt. Ltd., 22 G.T. Road, (North) P.O. Liluah Distt. Howrah | Structural steel (Stand- ard quality)-IS :226- 1969. | S.O. 771 dated 28-2- 1970 | Deferred 1973 | after 15-1- |
| 29. CM/L-2200 8-1-1970 | Do. | Structural steel (ordinary quality)-IS :1977-1969 | S.O. 771 dated 28-2- 1970 | Deferred 1973 | after 15-1- |
| 30. CM/L-2217 22-1-1970 | Banik Sangha Pvt. Ltd., 77, Raja Dinendra Street, Calcutta-6 (Office : 15 Clive Row, Calcutta-1) | Tea-chest metal fittings IS: 10-1970 | S.O. 771 dated 28-2- 1970 | Deferred 1973 | after 31-1- |
| 31. CM/L-2422 7-10-1970 | National Pesticides, 5, Industrial Estate, Vidisha (M.P.) | DDT dusting powders- IS: 564-1961 | S.O. 561 dated 30-1- 1971 | Deferred 1972 | after 31-12- |
| 32. CM/L-2519 25-1-1971 | Jagatjit Industries Ltd., Jagatjitnagar, Hamira Distt. Kapurthala | Whiskies-IS : 4449-1967 | S.O. 5028 dated 6-11- 1971 | Deferred 1973 | after 31-1- |
| 33. CM/L-2520 25-1-1971 | Sudershan Industries, Udyog Nagar, Tinsukia (Assam) | Tea-chest metal fittings- IS: 10-1970 | S.O. 5028 dated 6-11- 1971 | Deferred 1973 | after 31-1-1973 |
| 34. CM/L-2531 3-2-1971 | Chemico Cement Waterproof- ing Industries Pvt. Ltd., 34, Pashupati Bhattachar- jee Road, Calcutta-41 | Integral cement water- proofing compound- IS:2645-1964 | S.O. 5037 dated 6-11- 1971 | Deferred 1973 | after 15-2- |
| 35. CM/L-2729 4-8-1971 | R. Ponnuswamy Naidu & sons, 422, Edayar Street, Coimbatore-1(Tamil Nadu) | Tea-chest metal fittings- IS: 10-1970 | S.O. 5031 dated 6-11- 1971 | Deferred 1973 | after 15-2- |
| 36. CM/L-2883 24-1-1972 | Kala Parishat, Agraharam Road, Guntur-4 (A.P.) | Dye-based fountain pen inks-IS : 1221-1957 | S.O. 5031 dated 6-11- 1971 | Deferred 1973 | after 31-1- |
| 37. CM/L-2889 31-1-1972 | B. Chaudhary & Company, 27, Dr. Sundari Mohan Avenue, Calcutta-14. (Office : 162 A, Viveka- nanda Road, Calcutta-6) | Tea-chest metal fittings- IS : 10-1970 | S.O. 5031 dated 6-11- 1971 | Deferred 1973 | after 31-1- |
| 38. CM/L-2898 4-2-1972 | Swiss Welded Mesh Co (P) Ltd., A-7, Industrial Estate, Ambatur, Madras-58 | Welded steel wire fabric for general use-IS : 4948-1968 | S.O. 2801 dated 14-10- 1972 | Deferred 1973 | after 15-2- |
| 39. CM/L-2904 14-2-1972 | Regional Pig Breed Station- cum-Bacon Factory, Hari- nghata, Haringhata Farm P.O. Mohanpur Distt. Nadia, (W.Bengal) | Pork-IS: 1723-1960 | S.O. 2801 dated 14-10- 1972 | Deferred 1973 | after 15-2- |
| 40. CM/L-2905 14-2-1972 | Do. | Pork sausages-IS : 3061- 1965 | S.O. 2801 dated 14-10- 1972 | Deferred 1973 | after 15-2-1973 |
| 41. CM/L-2911 16-2-1972 | Gopal das Jagat Ram, 864, Industrial Area 'A' Ludhiana (Punjab) | Perforated stainless steel cones for wet pro- cessing-IS : 4893-1968 | S.O. 2801 dated 14-10- 1972 | Deferred 1973 | after 15-2- |
| 42. CM/L-2917 16-2-1972 | Assam Plywood Products, Kakojan, Jeypore P. O., Distt. Lakhimpura (Assam) | Tea-chest plywood bat- tens-IS : 10-1970 | S.O. 2801 dated 14-10- 1972 | Deferred 1973 | after 15-2- |

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 मई, 1973

का. आ. 1640.—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1893 (1893 का 6) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 180-क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“180-क—(1) वह रकम, जिसके लिए एकल इण्डियन पोस्टल आर्डर जारी किया जा सकेगा, 50 पैसे, एक रुपया या 10 रुपये तक, जिसमें वह भी सम्मिलित है, एक रुपए का कोई गुणज होगी। ऐसे प्रत्येक इण्डियन पोस्टल आर्डर के जारी किए जाने पर 10 पैसे कमीशन प्रभारित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए 1.50 रु., 2.50 रु., 3.50 रु., 4.50 रु., 5.50 रु., 6.50 रु., 7.50 रु., 8.50 रु. और 9.50 रु. के मूल्य-वर्ग के इण्डियन पोस्टल आर्डर भी जारी किए जाएंगे और ऐसे प्रत्येक इण्डियन पोस्टल आर्डर के जारी किए जाने पर 10 पैसे कमीशन प्रभारित किया जाएगा।”

3. उक्त नियम के नियम 180 ख में “50 पैसे” अंकों और शब्द के स्थान पर, “एक रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 64/178/71-सी. आइ.]

श्रीमती जी. ई. बनर्जी, डाक निदेशक (तकनीकी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

Delhi, the 21st May, 1973

S.O. 1640.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Post Office (Third Amendment) Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 180-A, the following rule shall be substituted, namely:—

“180-A—(1) The amount for which a single Indian Postal Order may be issued shall be 50 paise, Rupee I or any multiple of a Rupee upto and including Rupees 10. A commission of 10 paise shall be charged on the issue of each such Indian Postal Order.

(2) Notwithstanding anything contained in Sub-rule (1), Indian Postal Orders in the denominations of Rs. 1.50, Rs. 2.50, Rs. 3.50, Rs. 4.50, Rs. 5.50, Rs. 6.50, Rs. 7.50,

Rs. 8.50 and 9.50 shall also be issued for a period of two years from the commencement of the Indian Post Office (Third Amendment) Rules, 1973, and a commission of 10 paise shall be charged on the issue of each such Indian Postal Order.”

(3) In rule 180.B of the said rules, for the figures and word “50 paise”, the words “one rupee” shall be substituted.

[No. 64/178/71-CI]

SMT. G. E. BANERJI, Director Postal (Technical).

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

का. आ. 1641.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने तिरुपाट्टूर टेलीफोन केंद्र में दिनांक 1-7-1973 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5/18/73-पी. एच. बी.]

ए. एस. वोहरा, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1641.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-7-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in TIRUPATTUR Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5/18/73-PHB]

A. S. VOHRA, Asstt. Director Gen. (P.H.B.)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

का. आ. 1642.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 44 की उपधारा (2) के खण्ड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार दिल्ली परिवहन निगम (सलाहकार परिषद्) नियम, 1973 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम (सलाहकार परिषद्) (संशोधन) नियम, 1973 होगा।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) नियम 16 का संशोधन:—दिल्ली परिवहन निगम (सलाहकार परिषद्) नियम 1973 (जिसे इसके बाद मुख्य नियम कहा गया है) के नियम 16 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि 15 दिन की सूचना की अवधि नियम 12 के उपनियम (3) के अधीन भेजी गई सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख पर निश्चित की गई बैठक में किये गये प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा।”

(3) नियम 19 का संशोधन:—मुख्य नियम के नियम 19 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:—

“परन्तु यह कि बैठक की स्थगित तारीख की सूचना उन सदस्यों को दी जायेगी जो बैठक में उपस्थित नहीं थे।”

[सं. 15-सी. ए. जी. (15)/723]

एन. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 22nd May, 1973

S.O. 1642.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 44 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following amendments in the Delhi Transport Corporation (Advisory Council) Rules, 1973, namely :—

(1) **Short Title & Commencement:**—(1) These Rules may be called the Delhi Transport Corporation (Advisory Council) (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 16:—To rule 16 of the Delhi Transport Corporation (Advisory Council) Rules, 1973 (hereinafter referred to as the principal rules), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that the period of 15 days notice shall not apply to a proposition to be moved at a meeting which is fixed at a date specified in the intimation sent under sub-rule (3) of rule 12.”

3. Amendment of Rule 19:—To sub-rule (1) of rule 19 of the principal rule, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that notice of the adjourned date of the meeting shall be given to the members who were not present at the meeting.

[No. 15-TAG(15)/72]

N. R. REDDY, Joint Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

क्रा. आ. 1643.—राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पीठित व्यापारी पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा वाइस एडमिरल बी. ए. कामथ, उपाध्यक्ष नौसेना, को वाइस एडमिरल जे. कर्सेतजी के स्थान पर राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती हैं और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) का अधिसूचना संख्या सा. आ. 600 दिनांक 24 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 12 के सामने की प्रविष्टि में “वाइस एडमिरल जे. कर्सेतजी” के स्थान पर “वाइस एडमिरल बी. ए. कामथ” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

[37-एम. डी. (6)/73]

बा. कृ. साही, अवर सचिव

New Delhi, the 25th May, 1973

S.O. 1643.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with sub-rule (2) of rule 4 of the National Shipping Board

Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Vice Admiral V. A. Kamath, Vice Chief of Naval Staff, as a Member of the National Shipping Board, in place of Vice Admiral J. Cursetji and makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 600, dated the 24th January 1972, namely :—

In the said notification in the entry against Serial No. 12, for the words “Vice Admiral J. Cursetji” the words “Vice Admiral V. A. Kamath” shall be substituted.

[37-MD(6)/73]

B. K. SAHI, Under Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

सुविध-पत्र

नई दिल्ली, 26 मई, 1973

क्रा. आ. 1644.—वस्त्र मशीनों के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूची उद्योगों की विकास परिषद् स्थापित करने के बारे में भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2) दिनांक 30 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. 4073 दिनांक 22-10-1971 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) उक्त आदेश में, क्रम सं. 22 के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,

अर्थात्

22. श्री पी. आर. दासगुप्ता,
उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

[सं. 2-2/71-एच. एम. (1)]

एस. कन्नन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th May, 1973

S.O. 1644.—In order of the Government of India, Ministry of Industrial Development No. 4073 dated 22-10-1971, establishing a Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Textile Machinery, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 30th October, 1971, the following amendments shall be made, namely :—

(1) In the said order, for the entry occurring against S. No. 22, the following entry shall be substituted, namely :—

22. Shri P. R. Dasgupta,
Deputy Secretary,
Ministry of Heavy Industry.
Udyog Bhavan,
New Delhi

[No. 2-2/71-HM(I)]

S. KANNAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1973

का. आ. 1646.—भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग 2 में एतद् द्वारा आगे और निम्नीलिखित संशोधन करती है:

उपर्युक्त भाग 2 में “एम. डी. (सैंण्ट लुइस यूनीवर्सिटी अमेरिका),” प्रविष्टि के बाद निम्नीलिखित प्रविष्टि रख ली जाए:

“एम डी (यूनीवर्सिटी ऑफ बसेल), स्विट्जरलैंड,
एम. डी (यूनीवर्सिटी ऑफ फिलीपाइन्स, मनीला).
एम डी (यूनीवर्सिटी ऑफ मोडेना). इटली”

[संख्या 19-40/71 एम. पी टी]

क, साथी बालाकृष्णा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th May, 1973

S.O. 1646—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendment in Part II of the Third Schedule to the said Act, namely:—

In the said Part II, after the entry “M.D. (St. Louis University, USA)”, the following entries shall be inserted, namely:—

“M.D. (University of Basel), Switzerland
M.D. (University of Philippines, Manila)
M.D. (University of Modena), Modena, Italy”

[No 19-40/71-MPT]

Km SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1973

का. आ. 1647—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 10 फरवरी 1973 के पृष्ठ 549 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश सं. का. आ. 380 तारीख 10 दिसम्बर 1972 की अनुसूची में “नारायण चन्द्र दत्त” के स्थान पर “नारायण चन्द्र भट्ट” पढ़ें।

[सं. एस् 16012/2/72(एल आर 3)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

(CORRIGENDUM)

New Delhi, the 4th April, 1973

S.O. 1647—In the Order of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 380, dated the 19th December, 1972 published in Part II Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India dated the 10th February, 1973 on page 549 in the Schedule for “Narayan Chandra Dutta” read “Narayan Chandra Bhatta”

[No L 16012/2/72/(LRH)]

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 1973

का० आ० 1648—यह व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा के प्रबंधक से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व पंजाब लोक निर्माण, विभाग मोटर चालक यूनियन, तलवाड़ा करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

28 G of 1/73—8

और यह उक्त नियोजको और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947) का (14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धा के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद का उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यमस्व के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यमस्व करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार का भेजी गई है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यमस्व करार का जो उस 14 मई, 1973 को मिला था, एतद्वारा प्रकाशित करती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अन्तर्गत के बीच पदाधारों के नाम

नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 श्री मरदारी लाल
कर्मकारी इजीनियर (कार्मिक)
व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री प्रोतम सिंह.
अध्यक्ष, पंजाब लोक निर्माण विभाग
मोटर चालक यूनियन, तलवाड़ा।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री टी०टी० तयाडे, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के माध्यमस्व के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है —

1 विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय क्या व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा में नियोजित चालक 130—
200 रुपये के वेतन मान को पाने के हकदार है? यदि हाँ, तो किस तारीख से?

2 विवाद के पक्षकारों का विवरण 1 महा प्रबन्धक,
जिसमें अन्तर्बालित स्थापन या व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा।
उपक्रम का नाम और पना भी 2 अध्यक्ष, पंजाब लोक निर्माण विभाग
सम्मिलित है। मोटर चालक यूनियन तलवाड़ा।

3 यदि कोई सच प्रश्नगत कर्मकारों पंजाब लोक निर्माण विभाग, मोटर
का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका चालक यूनियन तलवाड़ा।
नाम।

4 प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्म- 15,000
कारों की कुल संख्या।

5 विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्य 450
प्रभावित होने वाले कर्मकारों की
प्राक्कालित संख्या

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर
बाधक कर होगा।

मध्यस्थ अपना पचाह तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक विनिश्चय करार द्वारा बनाया जाय, देगा। यदि पूर्ण वर्णित कालावधि के भीतर पचाह नहीं दिया जाना तो माध्यमस्व के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नये माध्यमस्व के लिये बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पदाधारों के हस्ताक्षर

ह०/—मरदारी लाल

ह०/—प्रोतम सिंह

12/4/73

नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले
साक्षी

1 ह०/—कुलदीप सिंह

12/4/73

2 ह०/—अमृत लाल

[संख्या एल०-42013/3/73-(एल०आर० 1)]

ORDER

Delhi the, 24th May, 1973.

S. O. 1648.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to Beas Dam Project, Talwara, and its workmen represented by Punjab Public Works Department Motor Driver Union, Talwara;

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on 14th May, 1973.

AGREEMENT

Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947

BETWEEN

Name of the parties:

Representing employers : Shri Sardari Lal
Executive Engineer (Personnel)
Beas Dam Project, Talwara.

Representing Workmen : Shri Pritam Singh,
President, Punjab Public Works
Department Motor Drivers Union,
Talwara.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri T.T. Tayade, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

- (i) Specific matters in dispute "Whether the Drivers employed at the Beas Dam Project, Talwara are entitled to the scale of Rs. 130—200 ? If so, from what date ?"
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
- (iii) Name of the Union, if any representing the workmen in question.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.

1. General Manager, Beas Dam Project, Talwara.
2. President, Punjab Public Works Department Motor Driver Union, Talwara.

Punjab P.W.D. Motor Driver Union, Talwara.

16000

450

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us. The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties:

Sd/- Sardari Lal
Representing employers

Sd/- Pritam Singh
12/4/73
Representing workmen.

Witnesses:

1. Sd/- Kuldip Singh
12/4/73
2. Sd/- Amrit Lal.

[No. L. 42013/3/73/LR III]

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1973

का. आ. 1649.—यतः व्यास बांध प्रायोजना से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व कर्मकार यूनियन, व्यास प्रायोजना, तलवाड़ा कस्बा करती है, संयुक्त रूप से एक आवेदन उनके बीच उस बात की बाबत जो उक्त आवेदन में उपबर्णित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रत्युपादित है विद्यमान औद्योगिक विवाद को किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार को दिया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त कर्मकार यूनियन, व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा कस्बा कर्मचारों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 7-क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी. पी. आर. साहनी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त औद्योगिक विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निवेशित करती है।

अनुसूची

क्या व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा, जिला होशियारपुर में अग्निशमन सेवा में नियोजित कर्मचारी पहली जून, 1965 से 31 दिसम्बर, 1969 तक उन्हें वरों से बुलाया भत्ता के भुगतान के हकदार हैं, जिनसे उन्हें पहली जनवरी, 1970 से भुगतान किया जा रहा था ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल.-42012/22/73-एल. आर.-3]

ORDER

New Delhi, the 26th May, 1973

S.O. 1649.—Whereas the employers in relation to Beas Dam Project, Talwara and their workmen represented by Workers Union, Beas Dam Project, Talwara Township, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed; And, whereas the Central Government is satisfied that the said Workers Union, Beas Dam Project, Talwara Township represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the employees employed in the Fire Fighting Service at Beas Dam Project, Talwara, District Hoshiarpur are entitled to the payment of Call Allowance from 1st June, 1965 to 31st December, 1969 at same rates at which they are being paid with effect from 1st January, 1970? If not, to what relief are they entitled?

[No. L-42012/22/73-LR-III]

आवृत्ति

का. आ. 1650.—यतः व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व व्यास प्रायोजना कर्मकार यूनाइटेड फ्रण्ट, तलवाड़ा कर्मचारों की बहु-रूप से एक आवेदन उनके बीच उस बात की बाबत जो उक्त आवेदन में उप-वर्णित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रत्युत्पादित है, विद्यमान औद्योगिक विवाद को किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार को दिया है,

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त व्यास प्रायोजना कर्मकार यूनाइटेड फ्रण्ट, तलवाड़ा कर्मचारों की बहु-संख्या का प्रतिनिधित्व करता है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी. पी. आर. साहनी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त औद्योगिक विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

क्या व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा के कार्य-भारित कर्मचारी पहली जनवरी, 1970 के बड़े पहली फरवरी, 1968 से संशोधित ग्रैंड पाने के हकदार हैं ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष को पाने के हकदार हैं ?

[संख्या एल.-42012/10/73-एल. आर.-3]

ORDER

S.O. 1650—Whereas the employers in relation to Beas Dam Project, Talwara and their workmen represented by Beas Project Workers United Front, Talwara, have jointly applied to the Central Government for reference of an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Beas Project Workers United Front, Talwara represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the workcharged employees of Beas Dam Project, Talwara are entitled to the revised grades with effect from 1st February, 1968 instead of from 1st January, 1970? If not, to what relief are they entitled?

[No. L. 42012/10/73/LR III]

आवृत्ति

का. आ. 1651.—यतः व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व पंजाब लोक निर्माण विभाग मोटर चालक यूनियन, तलवाड़ा करती है, संयुक्त रूप से एक आवेदन उनके बीच उस बात की बाबत जो उक्त आवेदन में उप-वर्णित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रत्युत्पादित है, विद्यमान औद्योगिक विवाद को किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार को दिया है ,

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त पंजाब लोक निर्माण विभाग मोटर चालक यूनियन, तलवाड़ा कर्मचारियों की बहु-संख्या का प्रतिनिधित्व करती है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी. पी. आर. साहनी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

क्या व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा में नियोजित कार्य-भारित चालक और कण्डक्टर, जिन्होंने दस वर्ष या इससे अधिक की सतत सेवा कर ली है, अपनी सेवा के नियमितकरण के हकदार हैं? यदि हां, तो किस तारीख से?

[संख्या एल.-42012/8/73-एल. आर.-3]

ORDER

S.O. 1651.—Whereas the employers in relation to Beas Dam Project, Talwara and their workmen represented by Punjab Public Works Department Motor Drivers Union, Talwara, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Punjab Public Works Department Motor Drivers Union, Talwara represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the workcharged Drivers and Conductors employed at Beas Dam Project Talwara who have put in ten years or more of continuous service are entitled to the regularisation of their services? If so, from what date?

[No. L. 42012/8/73 LR III]

आवृत्ति

का. आ. 1652.—यतः व्यास बांध प्रायोजना से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व व्यास प्रायोजना कर्मकार यूनाइटेड फ्रण्ट, तलवाड़ा करता है, संयुक्त रूप से एक आवेदन उनके बीच इस बात की बाबत जो उक्त आवेदन में वर्णित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रत्युत्पादित है, विद्यमान औद्योगिक विवाद को किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार को दिया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त व्यास प्रायोजना कर्मकार यूनाइटेड फ्रण्ट, तलवाड़ा कर्मचारियों की बहु-संख्या का प्रतिनिधित्व करती है ,

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी. पी. आर. साहनी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

क्या व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा में नियोजित कार्य-भारित कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष या इससे अधिक की सतत सेवा कर ली है, अतनी सेवा के नियमितकरण के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस तारीख से?

[सं. एल-42012/11/73-एल. आर-3]

ORDER

S.O. 1652.—Whereas the employers in relation to Beas Dam Project, Talwara and their workmen represented by Beas Project Workers United Front, Talwara, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Beas Project Workers United Front, Talwara represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the workcharged employees employed at Beas Dam Project Talwara who have put in ten years or more of continuous service are entitled to the regularisation of their services? If so, from what date?

[No. L. 42012/11/73/LR III]

New Delhi, the 29th May, 1973

S.O. 1653.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Chirimiri Ponri Hill Colliery, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st May, 1973.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT**

Jabalpur, the 24th March, 1973

Present :

Mr. Justice S. N. Katju, Presiding Officer.

Case Ref. No. CGIT/LC(R)(16)/72

(Notification No. L-22011/4/72-LRIL dated 4-5-1972)

Parties :

Employers in relation to the management of New Chirimiri Ponri Hill Colliery, Post Office Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh) and their workmen represented through the M. P. Koyala Mazdoor Panchayat, P.O. Kurasia, District Surguja (M.P.)

Appearances :

For employers—Sri P. S. Nair, Advocate.

For workmen—Sri Hardeo Singh.

Industry : Coal Mine.

District : Surguja (M.P.).

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 (hereinafter called the Act).

The workmen of the New Chirimiri Ponri Hill Colliery, P.O. Chirimiri, District Surguja (hereinafter called the Colliery) have claimed wages at double the rate for working on Sundays. There was an agreement in Form 'II' dated

2-7-1965 between the management of the Colliery and the workmen who were represented by the Secretary and the President of the New Chirimiri Ponri Hill Colliery Branch of M.P.C.W. Federation and by the Vice President of the aforesaid Federation. Clause (4) of the terms of the aforesaid agreement was as follows :—

"Barring the personnel mentioned in item (2) and (2) above, the rest of the Sunday workers will be given 1-1/2 times their normal rate of wages and this enhanced Sunday rate for these personnel will commence with effect from 1-5-1965."

Thereafter there was another agreement between the parties dated 21-1-1968 which was followed by an award of this Tribunal dated 7-2-1968. The said award was quashed by the High Court of Madhya Pradesh on a writ petition moved by one Sital S/o Sukhi Ram. The case was remanded back to the Tribunal for adjudication. After the remand, the workmen of the Colliery including Sital were represented by the Federation and again the parties entered into an agreement dated 4-12-1968 and this Tribunal made an award in terms of the aforesaid settlement between the parties. The question of payment of wages for working on Sundays was covered by item 3 of the aforesaid terms of settlement between the parties. It said :—

"This matter is covered by the provisions of Certified Standing Orders which are being fully implemented. The demand is, therefore, not pressed."

The dispute which has given rise to the present reference before me was raised by the M. P. Koyala Mazdoor Panchayat. The question referred to this Tribunal is :—

"Keeping in view the provisions of the Standing Orders, whether the demand of the workmen of New Chirimiri Ponri Hill Colliery Post Office, Chirimiri, District Surguja for wages at double the rate for working on Sundays is justified? If so from which date?"

The management has contended that the aforesaid agreement of 4-12-1968 has not been terminated and it is still binding on the parties. Evidently, the question referred to in the schedule to the reference does not mention the aforesaid agreement of 4-12-1968 at all. It may be that since item No. 4 of the settlement of 1968 says that "matter is covered by the provisions of the Certified Standing Orders" the dispute could be said to relate to the interpretation of the Standing Orders of the Colliery. I need not go further into the matter and an proceeding on the assumption that the reference made to this Tribunal is maintainable.

Admittedly the workmen have not based their claim for working for more than six days in a week. It is not contended by them that they were working on Sundays in addition to working on the remaining six days in the week. Sri Hardeo Singh who represented the workmen admitted that the workmen did not work for more than six days in the week. He, however, contended that Sunday was the weekly rest day and work taken on Sundays, irrespective of the fact whether the workmen have only worked for 5 days in the week, would entitle the workmen to claim wages at double the rate. The dispute, therefore, is confined to the question whether irrespective of the fact that the workmen had worked for only six days in a week but while doing so if they had worked on a Sunday then in that case they were entitled to claim double the wages for working on that day. It was further contended on behalf of the workmen that weekly bazars were held in the neighbourhood of the Colliery on Sundays and if the workmen worked on Sundays they were not able to go to the bazar and purchase commodities at comparatively cheaper rates.

Clause 6(c) of the Standing Orders of the Colliery runs :—

"Overtime shall be worked by the workmen and wages therefor shall be paid to them in accordance with the provisions of the Mines Act (as amended) and Rules made thereunder or as may be admissible under an award, agreement, custom or usage, whichever is more favourable to the workmen".

Sri Hardeo Singh tried to argue that the expression "or as may be admissible under an award, agreement, custom or usage whichever is more favourable to the workmen" implied that the workmen were entitled to "more favourable" terms irrespective of an award or agreement between the parties.

There is no force in the contention of the representative of the workmen that working on Sundays irrespective of the fact whether the workmen had worked for only 5 days in a week in addition to working on Sundays would entitle them to claim wages at double the daily rate. He referred to the first paragraph of the recital of the case in the agreement dated 2-7-1965. It says :—

"The approved Standing Order at the New Chitmiri Ponri Hill Colliery was modified by the Union with their representation to the Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur and the main changes effected were to give uniform leave with pay for all monthly rated workers and to give better monetary consideration for Sunday works, which was the general rest day of the Colliery. Over this amended Standing Orders the employer felt aggrieved and they have gone in appeal, the result of which is still awaited.

With the cooperation and goodwill prevailing it is mutually agreed that both the parties to this agreement should approach the Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur to get the Standing Orders amended as per the terms of this Agreement and approach the concerned authority jointly with a request that the appeal pending on this issue should be withdrawn. This agreement will be binding on both the parties with the Standing Order also accordingly amended and will continue in force till such time that any fresh statutory provisions or Wage Board findings require a modification thereon."

He laid stress on the words "for Sunday works which was the general rest day of the Colliery". It may be that Sunday was "the general rest day" in the colliery, but it does not mean that Sunday had been declared a holiday in the sense of a Gazetted holiday which the workmen get. The provisions of the Mines Act make it clear that one day in a week is a weekly day of rest irrespective of the fact whether it is a Sunday or any other day. Section 28 of the Act lays down that a workman has to work for six days in a week and he is entitled to extra wages if he is made to work on a seventh day. Further-more, the total working hours of a workman during a week are not to exceed the limit of 48 hours. Therefore even if a workman works on a Sunday and gets a day of rest on any other day in the week he would not be entitled to any extra wages merely because he had worked on a Sunday. There is nothing to prevent the management from making any day in a week as a weekly day of rest. In this connection reference may be made to a letter issued by the Ministry of Mines and Fuel, Government of India dated 11-7-1972 (Ex. E/7) to "all the Collieries in the outlying coalfields". It said :—

"With the sharp rise in the demand of rail transport for movement of coal under the third Five Year Plan the necessity for utilisation of the available rail transport capacity has assumed great importance. The railways are operating on all days of the week and they have finally intimated that if the transport capacity for one day is lost it will be impossible for them to meet the entire demand of coal transport. Under the circumstances the Government of India would like to make it obligatory for the Collieries to load uniformly on all days of the week.

In order to achieve the above objective it may be necessary to stagger the rest days for the labour over the week".

It was stated on behalf of the Colliery :—

"Rest day or Sunday works are vital in a Colliery. Even when coal production is kept stopped for a day in the week, machines have to be repaired, water and electricity have to be supplied, hospital has to run and Mine has to be inspected for gases, fire, safety, etc. and above all Ministry of Mines has controlled wagon loading to be essentially done on Sundays and Rest days on an equal par. The employers are hardly engaging 375 workmen for works on Sundays giving them alternate Rest day and this is in the total labour force of over 2000."

Taking the aforesaid circumstances into consideration it cannot be said that the management of the Colliery was not justified in changing the rest day of some of their workmen from Sunday to some other day in a week. The workmen were amply compensated by paying them 1-1/2 days wages for doing work on Sundays which by itself could not be said

to be payment for taking work for more than 48 hours in a week or for more than six days in a week.

The representative of the workmen while trying to place reliance on the words in the aforesaid recital of the case that Sunday was "the general rest day of the Colliery" overlooked the terms of the agreement which followed the recital of the case in the settlement dated 2-7-1965. It was specifically mentioned in clause (4) that the workers will be given 1-1/2 times of their normal rate of wages. The payment of 1-1/2 time of wages for working on a Sunday and not working for more than six days or 48 hours in a week was mutually agreed upon between the parties and there is no reason why the workmen should resile from the aforesaid terms of the settlement. Shri G. Srinivasan, E.W. 1, the former Chief Mining Engineer of the Colliery, stated that working on Sundays for which the claim of extra wages has been made by the workmen was for working for six days and not for 7 days in a week. He proved the agreements and the awards of this Tribunal which according to him were still in operation. Ram Nath (W.W. 1) and Din Dayal (W.W. 2) gave evidence on behalf of the workmen. Ram Nath in his cross-examination has admitted that he had no evidence with him in support of his case that double payments were made for working on Sundays. His evidence is not convincing and does not support the workmen's case. Din Dayal stated in his cross-examination :—

"If the rest day is any other day besides Sunday then we were paid 1-1/2 wage and if Sunday was a rest day and work was done on that day double payment was made."

From the aforesaid statement it would appear that Sunday was not a rest day for all the workmen and only when Sunday was a rest day and a workman had worked on Sunday also after working for the remaining six days in the week then in that case only he was given double wage. That will be fully in accordance with the provisions of the Mines Act.

There is no force in the contention that when a workman worked on a Sunday then in that case he was denied the opportunity to go to the weekly bazars to purchase goods at comparatively low prices. In any case that could not be a ground for claiming double wages for working on a Sunday if it was not the seventh day of work in a week. Mr. Srinivasan (F.W. 1) has stated that bazars were held in the vicinity of the Colliery on Thursday, Friday and Saturday. The Saturday's bazar was held at a distance of 2 Kms. from the colliery area while the Sunday bazar was held at a distance of 3 Kms. away from the colliery. He further stated that there was a Consumer Cooperative Stores in the colliery area where consumer's goods were available. He also stated that if any workman wanted leave on Sunday he could get it. Mr. Srinivasan further stated that in the neighbouring collieries the workmen were getting only a day's wages when they worked on a Sunday which was not the seventh day of work in a week.

Considering the circumstances of the case I am satisfied that the demand of the workmen of the Colliery for wages at double the rate for working on Sundays is not justified. I make my award accordingly. I make no order for costs.

[No. L/22011/4/72/LR II]

S. N. KATJU, Presiding Officer.

आपरा

नई दिल्ली, 29 मई, 1973

का. आ. 1654—यतः व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा से संबंधित नियोजक और उनके कर्मकारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व कर्मकार यूनियन, व्यास बांध प्रायोजना, तलवाड़ा करती है, संयुक्त रूप से एक आवेदन उनके बीच उस बात की बाबत जो उक्त आवेदन में उपस्थित है और इससे उपायबद्ध अनुसूची में प्रत्युत्पादित है विद्यमान औद्योगिक विवाद को किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार को विधा है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त कर्मकार यूनियन, व्यास बांध प्रायोजना तलवाड़ा कर्माचारियों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी. पी. आर. साहनी होंगे, जिनका मुख्यालय खंडीगढ़ होगा और उक्त विवाद का उक्त अधिकरण का न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

क्या न्याय बांध प्रायोजना, तलवाड़ा में नियोजित अग्नि शमन व्यक्ति 110-200 रुपये के नतनमान के हकदार हैं? यदि हां, तो किस तारीख से?

[सं. एल. 42012/23/73/एल. आर. 3]

कमल सिंह, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th May, 1973

S.O. 1654.—Whereas the employer in relation to Beas Dam Project, Talwara and then workmen represented by Workers Union, Beas Dam Project, Talwara Township, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Workers Union Beas Dam Project, Talwara Township represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the Fire Fighting men employed at Beas Dam Project, Talwara are entitled to the Scale of Rs. 110—200? If so, from what date?

[No. L. 42012/23/73/LR III]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

आवेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1973

का. आ. 1655.—यतः राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, डाकघर अणुशक्ति, बरास्ता कांटा के प्रबंधन से सम्बद्ध चिन्ताओं और उनके कर्मचारियों, जिनका प्रतिनिधित्व राजस्थान अणुशक्ति प्रायोजना कर्मचारी संघ, डाकघर रावथभाटा, बरास्ता कांटा करता है, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपबर्णित और इससे सम्बद्ध अनुसूची में उद्धृत विषयों के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करे।

और, यतः केन्द्रीय सरकार का समधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद के उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

क्या राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, डाकघर अणुशक्ति, बरास्ता कांटा के प्रबंधन की, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9क के अधीन, जहाँ तक स्टाफ कार चालकों का अतिकाल भत्ते के भुगतान का सम्बन्ध है तारीख 20 मार्च, 1973 के परिवर्तन नोटिस देने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वे किस अनुपात के हकदार हैं?

[सं. एल.-29011/28/72-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 19th April, 1973

S.O. 1655.—WHEREAS the employer in relation to the management of Rajasthan Atomic Power Project, Post Office Anushakti, Via-Kota and their workmen represented by Rajasthan Anushakti Pariyojna Karamchhari Sangh, Post Office Rawathbhatta, Via-Kota have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) for reference of an Industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

AND, WHEREAS the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Rajasthan Atomic Power Project, Post Office Anushakti, Via Kota in giving a notice of charge dated 20th March, 1973 under section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947, in so far as payment of overtime allowance to Staff Car Drivers is concerned, is justified? If not, to what relief are they entitled?

[No. L-29011/28/73-LR. IV]

आवेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973

का. आ. 1656.—यतः राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, डाकघर अणुशक्ति में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बनारसीदास भनाोट एन्ड कम्पनी, मैसर्स रायपुर माइनिंग एण्ड बिल्डिंग क., मैसर्स अनुपचन्द जैन एन्ड कम्पनी, और मैसर्स और माइनिंग कम्पनी, ठाकंदार, बंताडिला आयरन और प्रोजेक्ट, डाकघर किरनबुल के प्रबंधन से सम्बद्ध चिन्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

“क्या मैसर्स बनारसीदास भनाोट एन्ड कम्पनी, मैसर्स रायपुर माइनिंग एण्ड बिल्डिंग कम्पनी, मैसर्स अनुपचन्द जैन एण्ड कम्पनी और मैसर्स और माइनिंग कम्पनी, डाकघर किरनबुल, ठाकंदार, बंताडिला आयरन और प्रोजेक्ट के कर्मचारियों की लॉह अयस्क उद्योग मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को, जैसी कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, कार्यान्वित करने की मांगें न्यायोचित हैं? यदि हां तो वे किस अनुपात के और किस तारीख से हकदार हैं?”

[सं. एल.-29011/1/73-एल. आर.-4]

एस. एस. सक्सेनामान, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th April, 1973

S.O. 1656.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Banarsi Das Bhanot and Company, Messrs Raipur Mining and Building Company, Messrs Anup Chand Jain and Company and Messrs Ore Mining Company, Contractors, Bailadila Iron Ore Project,

Post Office Kirandul, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demands of the workers of Messrs. Banarasi-das Bhanot and Company, Messrs Raipur Mining and Building Company, Messrs Annupchand Jain and Company and Messrs Ore Mining Company, Post Office Kirandul, Contractors, Bailadila Iron Ore Project, for implementation of the recommendations of the Wage Board for Iron Ore Industry, as accepted by the Government of India, are justified? If so, to what relief are they entitled and from what date?

[No. L-26011/1/73-LR. IV]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1973

का. आ. 1657.—लॉह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 3 के साथ पीठल लॉह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना सं. का. आ. 3399, तारीख 18 सितम्बर, 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और 7 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

श्री बी. ए. गवस, महासचिव, राष्ट्रीय माइन मजदूर संघ, क्यूपोम, गोवा।

श्री एम. एस. राना, सचिव, राष्ट्रीय माइन मजदूर संघ द्वारा मैसेर्स न्यू इण्डिया माइनिंग कारपोरेशन (प्रा.) लिमिटेड, रोही जिला, रत्नागिरी जिला, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

लॉह अयस्क खान
कर्मचारियों
के प्रतिनिधि

[फा. सं. यू. 19012/3/71-एम-4]

बी. के. सक्सेना, अवर सचिव

Delhi the, 28th May, 1973

S. O. 1657.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961), read with rule 3 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963; the Central Government hereby makes the following amendment in the notification No. S.O. 3399, dated the 18th September, 1972 namely :—

In the said notification against serial numbers 6 and 7, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

Shri V.S. Gawas,
General Secretary,
Rashtriya Mine Mazdoor Sangh,
Qupom, Goa.
Shri M.S. Rane,
Secretary,
Rashtriya Mine Mazdoor Sangh,
C/o M/s. New India, Mining
Corporation (P) Ltd.,
Radi, District Ratnagiri (Maharashtra)

Representatives of
Iron Ore Mines
Workers.

[F. No. U/19012/3/71-M. IV]

B. K. SAKSENA, Under Secy.

का. आ. 1658.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या ए-32013/1/73-एम.-1 दिनांक 25 अप्रैल, 1973 का अतिक्रमण करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एच. बी. घोष को उस सभी राज्य क्षेत्र के लिए जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार है, पहली मई, 1973 को और से मुख्य खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[ए-32013/1/73-एम. आई.]

पी. आर. नैयर, अवर सचिव

S.O. 1658.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. A. 32013/1/73-MI, dated the 25th April, 1973, the Central Government hereby appoints Shri H. B. Ghose, with effect from 1st May, 1973, to be the Chief Inspector of Mines for all the territories to which the said Act extends.

[A.32013/1/73-MI]

P. R. NAYAR, Under Secy.

Delhi the, 26th May, 1973

S. O. 1659.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following interim consent award of Shri F.C.R. Machado, Arbitrator, Vasco-da-Gama (Goa), in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri S.R. Navelkar, Vasco-da-Gama, Shri D.S. Kamat, Vasco-da-Gama, Shri D.B. Naik, Vasco-da-Gama, Shri Cactano Rodrigues, Vasco-da-Gama, Shri R. Kharapurkar, Vasco-da-Gama, Shri D.S. Naik, Vasco-da-Gama, Shri C.S.D. Souza, Vasco-da-Gama, Shri R.V. Phadte, Vasco-da-Gama, Shri Damodar B. Naik, Vasco-da-Gama, and Shri Gabriel D'Souza, Vasco-da-Gama, and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st May, 1973.

IN THE MATTER OF ARBITRATION IN THE DISPUTE BETWEEN 14 LAUNCH OWNERS AT MORMUGAO HARBOUR (GOA) AND THE GOA DOCK LABOUR UNION, (INTUC), VASCO-DA-GAMA (GOA).

1. Present : Shri F.C.R. Machadeo, (Arbitrator), President of Mormugao Stevedores' Association, Vasco-da-Gama, Goa.
2. Representing Employers :
 1. Shri S.R. Navelkar
 2. Shri D.S. Kamat
 3. Shri B.D. Naik
 4. Shri Cactano Rodrigues
 5. Shri R. Kharapurkar
 6. Shri D.S. Naik
 7. Shri C.S. D'Souza
 8. Shri R.V. Phadte
 9. Shri Damodar B. Naik
 10. Shri Gabriel D'Souza
3. Representing Workmen : Shri Mohan Nair, General Secretary, Goa Dock Labour Union, Vasco-da-Gama, Goa. and others

AWARD

The following Launch Owners (hereinafter mentioned as Employers) on the one hand and Goa Dock Labour Union (hereinafter mentioned as employees) on the other, entered into a Settlement on 21.11.72 agreeing to refer the following dispute for my arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

Names of Employers

1. Shri Rajaram Kharapurkar, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
2. Shri Vasudeo Kerker, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
3. Shri D.S. Kamat, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
4. Shri Cactano Rodrigues, Launch Owner, Vasco-da-Gama.

5. M/s. Elesbao Pereira & Sons, Launch Owners, Vasco-da-Gama.
6. M/s. D.B. Naik & F.X. Braganza, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
7. Shri Vasant R. Sakhalakar, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
8. Shri Hari Krishna Naik, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
9. Shri Raghuvir Fotto, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
10. Smt. Veronica D'Souza, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
11. Shri S.R. Navelkar, Launch Owner, Vasco-da-Gama.
12. M/s. Hiralal & Co. Launch Owners, Vasco-da-Gama.
13. Shri Madhav Rao Sawant, Launch Owner, Mormugao Harbour.
14. Shri Gabriel D'Souza, Launch Owner, Vasco-da-Gama.

The specific matters in the dispute referred to my arbitration are as under :—

1. Whether the Charter of Demands dated 1st January 1972, served on the Launch Owners/Launch Employers by the Goa Dock Labour Union, Vasco-da-Gama, in respect of the Launch Crew are justified or not ?
2. If so, what relief the workmen (Launch Crew) are entitled to ?

The Central Government, vide Notification No. L-36011/6/72-P&D (i) dated 30th December, 1972, of the Ministry of Labour and Rehabilitation, (Dept. of Labour & Employment), New Delhi, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, issued a notification under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947, referring the said dispute for my arbitration.

During the pendency of my hearing in the above dispute, the Employers viz.

1. Shri S.R. Navelkar, Vasco-da-Gama.
2. Shri D.S. Kamat, Vasco-da-Gama.
3. Shri D.B. Naik, Vasco-da-Gama.
4. Shri Caetano Rodrigues, Vasco-da-Gama.
5. Shri R. Kharapurkar, Vasco-da-Gama.
6. Shri D.S. Naik, Vasco-da-Gama.
7. Shri C.S. D'Souza, Vasco-da-Gama.
8. Shri R.V. Phadte, Vasco-da-Gama.
9. Shri Damodar B. Naik, Vasco-da-Gama.
10. Shri Gabriel D'Souza, Vasco-da-Gama.

entered into a mutual Settlement with the Goa Dock Labour Union, representing the employees, under which it was agreed between the parties that an ad hoc amount of Rs. 100 per Khalasi and Rs. 150 per Tandel or per Driver (who are in the employment of the respective employers as on 16-4-73) will be paid on or before 21st April, 1973, and that such ad hoc amount will be adjusted/recovered as the case may be in accordance with the Award to be given by me and that in case of recovery, the amount will be recovered in three instalments.

The parties have filed the said mutual Settlement before me for passing the same as Interim Consent Award. After going through the said mutual settlement I am satisfied that the same is fair and reasonable and accordingly I pass the same as Interim Award pending my Final Award in the above dispute.

Sd/-

F.C.R. MACHADO
Arbitrator

Dated: 14th May, 1973 President, Mormugao stevedores' Association, Vasco-da-Gama.

BEFORE THE ARBITRATOR SHRI FROILANO C.R. MACHADO

BETWEEN

The 14 Launch Owners at Mormugao Harbour
AND

Their Workmen Represented by Goa Dock Labour Union

VASCO-DA-GAMA, GOA

May it please you

We are enclosing herewith a copy of an interim settlement signed between 10 Launch Owners' representatives out of the 14 Launch Owners and their workmen represented by Goa Dock Labour Union, Vasco-da-Gama on 16th April, 1973 in the matter incidental to and connected with the dispute which has been referred to your arbitration under section 10A of the I.D. Act, 1947 vide notification No. L-36011/6/72-P&B (i) dated 30th December, 1972 of Govt. of India, Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour & Employment) New Delhi.

We therefore, pray you to be kind enough to pass an interim consent award in the light of the above interim settlement.

Dated this day 30th of April 1973.

(MOHAN NAIR)

General Secretary

Goa Dock Labour Union

Representing the Workmen

Parties Representing the Employers :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Shri S.R. Navelkar | sd/- S.R. Navedkar |
| 2. Shri D.S. Kamat | sd/- D.S. Kamat |
| 3. Shri D.B. Naik | sd/- D.B. Naik |
| 4. Shri Caetano Rodrigues | sd/- Caetano Rodrigues |
| 5. Shri R. Kharapurkar | sd/- R. Kharapurkar |
| 6. Shri D.S. Naik | sd/- D.S. Naik |
| 7. Shri C.S. D'Souza | sd/- C.S. D'Souza |
| 8. Shri R.V. Phadte | sd/- R.V. Phadte |
| 9. Shri Damodar B. Naik | sd/- Damodar B. Naik |
| 10. Shri Gabriel D'Souza | sd/- Garbriel D'Souza |

MINUTLS OF INTERIM SETTLEMENT FOR AN INTERIM CONSENT AWARD OF THE ARBITRATOR

Dated 16th April, 1973

The following Launch Owners are herein present :—

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Shri S.R. Navelkar | sd/- S.R. Navelkar |
| 2. Shri D.S. Kamat | sd/- D.S. Kamat |
| 3. Shri D.B. Naik | sd/- D.B. Naik |
| 4. Shri Caetano Rodrigues | sd/- C. Rodrigues |
| 5. Shri R. Kharapurkar | sd/- R. Kharapurkar |
| 6. Shri D.S. Naik | sd/- D.S. Naik |
| 7. Shri C.S. D'Souza | sd/- C.S. D'Souza |
| 8. Shri R.V. Phadte | sd/- (in Hindi) |
| 9. Shri Damodar B. Naik | sd/- D.B. Naik |
| 10. Shri Gabriel D'Souza | sd/- G. D'Souza |

Representing the workmen, Mr. Mohan Nair and Mr. Vasudev Vishnu Gurgaokar and Mr. Harischandra Ramchandra Usgaokar & others were present.

It has been agreed between the parties that an amount of Rs. 100 per Khalasi and Rs. 150 per Tandel and per Driver (who are in the employment of the respective employers as on 16th April, 1973) will be paid on or before 21st April, 1973.

The above said amount is purely on ad hoc basis and it is specifically agreed between the parties that the above said amount of Rs. 100 and Rs. 150 to Sailors and Tandels & Drivers respectively shall be adjusted/recovered as the case may be in accordance with the Award to be given by the Hon. Arbitrator within a month.

If the recovery is to be effected, it is agreed between the parties that the recovery shall be effected in three instalment.

It is agreed between the Launch Owners and the workmen that they shall implement the Award, and if necessary, after implementation they shall prefer an appeal.

sd/- F.K. Mohan Nair 16/4.

sd/- V.V. Gurgaokar

sd/- Harischandra Ramchandra Usgaokar.

New Delhi, the 29th May, 1973

S.O. 1660.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Eastern Supply Services, Calcutta, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th May, 1973.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
AT CALCUTTA

Reference No. 53 of 1972

Parties :

Employers in relation to the management of Messrs
Eastern Supply Services, Calcutta.

AND

Their Workmen.

Present :

Sri S. N. Bagchi—Presiding Officer.

Appearances :

On behalf of Employers—Sri S. Sarkar, Advocate

On behalf of Workmen—Sri N. Ghosh of Dock Shramik Association.

State : West Bengal

Industry : Dock

AWARD

By Order No. L-32011/16/71-P & D, dated 2nd September 1972 the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following disputes existing between the employees in relation to the management of Messrs Eastern Supply Services, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely :

“Taking into account the terms of settlement dated the 20th February, 1970, whether the denial of employment to the following 12 workmen by the management of Messrs Eastern Supply Service is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?”

1. Rahim Bux
2. Kedar Nath Gupta
3. Chand Meah
4. Noor Bux
5. Imdad Ali
6. Abdul Mabood
7. Sk. Chand
8. Fakhera Alam
9. Md. Sayeed
10. Md. Massim
11. Nar Hossain, and
12. Ali Hossain-II.”

2. Mr. Sarkar, appearing for the management raised a preliminary objection as to the legality of the reference, the jurisdiction of this tribunal to entertain the reference and to adjudicate upon it the reference as constituted is patently illegal for the reasons I am detailing below. The employer admittedly is an unregistered dock employer and the employee workmen numbering 12 are admittedly unregistered dock workers.

3. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 applies to Calcutta Dock area within the Port of Calcutta. Section 3 of the Act speaks of a Scheme which is, according to the Supreme Court Decision in Visakhapatnam Dock Labour Board and Stevedores' Association, Visakhapatnam and Ors, reported in 1970 1 LLJ p.46, a statutory Scheme. Clause (d) or Sub-section (2) of Section 3 of the Act says, “For regulating the employment of the dock workers whether registered or not and the terms and conditions of employment including rates of remuneration, hours of work condition as to holidays and pay in respect thereof” a Scheme may be provided. The Central Government in exercise of its powers conferred by Sub-section (1) of Sec. 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948

made and published the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970. I need not go into the details of the Scheme which is a statutory scheme. Clause 62 of the Scheme has repealed the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 and the Calcutta Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 and has brought into force since 1st June, 1970 the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 which is in force at present. There is the clause 42 of the Scheme of 1970 which is quoted below :

“42 **Restriction on Employment** :—(1) No person other than a registered employer shall employ any worker on dock work nor shall a registered employer engage, subject to the relaxation given in sub-clause (5) of Clause 20, for employment or employ a worker on dock work unless that worker is a registered dock worker.

(2) Notwithstanding the foregoing provisions of this clause—

(a) where the Administrative Body is satisfied that :—

- (i) dock work is emergently required to be done; and
- (ii) it is not reasonably practicable to obtain a registered dock worker for that work;

the Administrative Body may, subject to any limitations imposed by the Board, allocate to a registered employer a person who is not a registered dock worker. In selecting such workers the local Employment Exchange organisation shall, as far as possible, be consulted :

Provided that whenever unregistered workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible, the prior approval of the Chairman to the employment of such workers and where this is not possible, shall report to the Chairman within 24 hours the full circumstances under which such workers were employed and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at its next meeting;

(b) in the case referred to in item (a), the person so employed as aforesaid by a registered employer shall, for the purposes of sub-clauses (4), (5) and (6) of Clause 41 and Clauses 44 and 45 be treated in respect of that dock worker as if he were a daily worker.

(3) A registered worker in the reserve pool may, provided he fulfils fully his obligations under Clause 40, take up occasional employment under employers other than those registered under the Scheme on those days on which he is not allocated for work by the Administrative Body.”

No person other than a registered employer shall employ any worker on dock work nor shall a registered employer engage subject to the relaxation given in sub-clause (5) of Clause 20 or employ a worker on dock work unless the dock worker is a registered dock worker. This is the sub-clause (1) of clause 42. Then there is the non-obstante clause in sub-clause (2). The Administrative authority if satisfied that the dock work is emergently required to be done and it is not reasonably practicable to obtain registered dock worker for that work, the administrative body may, subject to limitations imposed by the Board, allocate to a registered employer a person who is not a registered dock worker. The rest of the clause 42 need not now be discussed. So, a registered dock worker is the only person that can be employed in any dock work only by registered dock employers but none else. There is a system of allocation by the administrative body as laid down in the scheme of 1970 of allocating registered dock workers for any dock work only to registered dock employer. So, the administrative body under the scheme is the only authority on whose allotment and allocation of a registered dock worker, be it in the reserve pool or not can only be employed by

the allottee registered dock employer. So, in between registered dock employer and registered dock employee there is no freedom of contract of employment. The freedom of contract of employment in a dock work has been taken away by the Scheme and the employment in any dock work of any registered or a non registered dock worker only by registered dock employer is controlled, conditioned and administered by the administrative body set up under the Scheme of 1970. An unregistered dock worker, however, can be employed only by the registered dock employer and that only under special circumstances. An unregistered dock worker may be allotted and allocated to perform any specified dock work by the administrative body under the provisions laid down in clause 42 sub-clause (2) of the Scheme, 1970 and that on being employed only by registered dock employer. The employees now before me are unregistered dock workers as they admitted before me. It appears that a business is being carried on by the unregistered dock employer in this case by gathering unregistered dock workers styled as watchmen. The registered shipping Companies or Stevedores send requisitions to unregistered dock employer i.e. the present management for supplying watchmen. This unregistered dock employer i.e. the management collects unregistered dock workers and refer their names to registered employers i.e. Stevedores or Shipping Companies or Agents and they employ the unregistered dock workers as in this case for dock work. I have never found such a blatant violation of law in carrying on such an unauthorised, unwarranted and illegal business. If any unregistered dock worker is to be employed for any dock work, he is to be allotted for such work for employment only by a registered dock employer and by none else and that only when the administrative body, under certain terms and conditions, specifically laid down in mandatory languages as appearing in clause 42 of the Scheme of 1970, allocates such unregistered dock worker for a dock work for employment by a particular registered dock employer. The unregistered dock employer has no right to comply with the requisition of any registered dock employer for supplying any unregistered dock workers for being employed by such registered dock employer for any dock work. The administrative body by such illegal arrangement goes away from the field in clear and unmistakable violation of the restrictions of employment in any dock work as laid down in clause 42 sub-clause (1) and (2) of the Scheme of 1970. I wonder how dock permit could be given to the unregistered dock workers who claim to have been working as watchmen in many ships berthed at the dock during the years 1969, 1970, 1971 and even up to the time when the alleged dispute was raised when they were not referred to by the unregistered dock employer i.e. the present management to the registered dock employer for engagement as watchman on their requisition. It is an indisputable fact that the administrative body never allocated any of these unregistered dock worker who are involved in this reference for employment at any time by any registered dock employer. I have already observed that it is only the administrative body as clause 42 sub-clause (2) of 1970 Scheme lays down that can only, under special circumstances as laid down in the scheme, refer to a registered employer for employment in any dock work any unregistered dock worker, and that none else can refer any unregistered dock worker for any dock work to be employed by anyone other than a registered dock employer.

Registered dock employers requisitions through unregistered dock employer i.e. the present management of the Company, of unregistered dock workers for being employed as watchmen of ships are thoroughly illegal. The unregistered dock employer i.e. the present company selects a batch of unregistered dock workers in compliance with the requisition of the registered dock employers, refer them to such requisitioning registered dock employer. The registered dock employer then engages these selected and referred to unregistered dock workers in a dock work. Can they do it? There is the clause 42 prohibiting such employment. If the administrative body is satisfied that a particular dock work is urgently required to be performed and there is no registered dock workers available at the time, it is only the administrative body that can refer to only a registered dock employer such number of unregistered dock workers for employment in the particular dock work by the registered dock employer and such dock workers if so employed by registered dock employer, would be considered in view of the provisions in sub-clause 2(b) of clause 42 of the Scheme of 1970, as if they were a daily workers. Industrial Tribunal cannot, by any award, legislate contrary to the provisions of clause 42 of the Scheme of 1970. If the tribunal directs that the so called employer in the present case, i.e. the company, which is an unregistered dock employer, should refer the name of the 12 unregistered dock workers involved in this case to any registered dock employer on its requisition for performance of any dock work, it would be in direct violation of sub-clause (2) of clause 42 of 1970 Scheme. I have already quoted the specific provisions of the scheme and I need only point out that it is only the administrative body, but none else, that shall have the absolute authority to refer for doing any particular dock work, any unregistered worker for employment to such work only by a registered dock employer under specific circumstances as enumerated in the sub-clause (2) of clause 42 of 1970 Scheme. The Industrial Tribunal cannot direct the unregistered dock employer the company to select these 12 workmen who are unregistered dock worker and to refer their names on the requisition of any registered dock employer for employment in any dock work because it is administrative body that alone has the power under the statutory scheme to allot and allocate any unregistered dock worker for employment in any dock work and that only by a registered dock employer. In the case of General Secretary, Madras Harbour Workers Union vs. Industrial Tribunal, Madras and others, reported in 1973 LIC, p. 186, two issues were referred to for adjudication, viz., whether the regular promotion to the category of Tindals should be limited to Winchmen as at present or thrown open also to Mazdoors who have been acting in casual vacancies over long periods as per Clause 30 of the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, if the Mazdoors are to be so promoted, on what qualifying terms and (b) Whether the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, should be amended to remove the existing anomalies in regard to promotion to the category of Tindals in casual vacancies and on a regular basis and if so, whether the same conditions must be prescribed for both types of promotions or any distinction should be drawn between the two". In rejecting the reference his Lordships Mr. Justice Palaniswami at page 190 of the report observes; "The jurisdiction of the Industrial Tribunal is no doubt wide in dealing with terms of contract between the employer and the work-

men as pointed out by the Supreme Court in the case cited above. It can even substitute a new contract if it is indeed essential for industrial peace. But it would be arrogating too much power if the Tribunal were to make an award out of its own power. The scheme framed under the Act is by virtue of the power of delegation conferred on them by the said Act. The scheme has all the characteristics of a subordinate legislation. Instead of the legislature itself making the scheme, it laid down the principles and conferred upon the Central Government the power to embody those principles and make a scheme in conformity with the conditions of labour obtaining in the respective Port." His Lordships however had not referred to the Vishakapatnam Port case quoted above where the Supreme Court at page 48 of the report observed, "The Port is a autonomous body competent to determine and prescribe wages, allowances and other conditions of service of the dock workers. The purport of the scheme is hold to be that the entire body of workers by the administrative body and the administrative body supplies wherever necessary the labour force to Stevedores, registered employers from the reserve pool. The workmen who are allotted to the registered employer are to do the work under the control and supervision of the registered employer and to act under their directions. The registered employer pay the wages due to the workers to the administrative body of the Dock Labour Board and the latter in turn an agent of the registered employers pay them over to the concerned workmen." Their Lordships observed that a scheme framed under the Act such as the present Scheme of 1970 is a statutory scheme and has the force of law. Therefore, this tribunal has no jurisdiction by making an award to direct an unregistered dock employer to supply directly on the requisition of a registered dock employer unregistered dock workers for employment by registered dock employer in any dock work in violation of clause 42 sub-clause (2) of 1970 Scheme. Such an award would be one legislating against the law of the land. In *Sarat Chandra & Co., Private Limited and Ors. vs Central Government Industrial Tribunal and Ors.* reported in 1963 1 L.J. p. 76, at page 81 their Lordships of the Patna High Court observed, "It is thus clear that the Board is an autonomous body competent to determine and prescribe wages and allowances and other conditions of service of dock workers. Dock Labour Board deal with almost all matters of importance connected with the employment and services of dock workers. The Scheme is self-contained one. The whole purport of the scheme seems to be that the entire body of dock workers should be under the control and supervision of the Board". Their Lordships held that the scheme that means the Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 made and published under the Dock Workers Regulation of Employment Act, 1948 relating to Calcutta Dock is a statutory scheme. At page 83 of the report their Lordships observed, "As I have said above the matter concerning the conditions of service, wages and remunerations can be raised on behalf of the dock workers before the Board and it is competent to decide it. If that be so, the Industrial Tribunal will not be competent to force on the employer or the workmen its decision against that body or in modification of it". If this tribunal directs the unregistered dock employer, like the present company, that you the company must enlist these 12 unregistered dock workers, must refer to the registered dock employers for employment in any dock work on their requisition, the tribunal will, by such an award,

trench upon the statutory provisions in clause 42 sub-clause (2) of the 1970 Scheme for the reasons I have already stated.

4. Even in case of registered dock workers, as the learned Judges of the Patna High Court had been pleased to observe, matters relating to employment i.e. condition of service, wages allowance, etc., governed by statutory scheme cannot form the subject matter of an industrial dispute. Clause 42(2) of 1970 scheme governs unregistered dock workers to be employed in any dock work. If the registered dock workers are dissatisfied with the terms and conditions of employment under registered dock employers, they can refer as observed by their Lordships of Patna High Court in *Sarat Chatterjee's case*, their grievances not before any industrial tribunal but before the Board, that means the Dock Labour Board. Here the position is otherwise. Unregistered dock workers demand that unregistered dock employer i.e. the Company shall refer their names on the requisition of registered employers made to such unregistered dock employer, for employment in dock work by such registered employers, of such unregistered dock workers. This demand resulting in the alleged dispute is contrary to clause 42 of the 1970 Scheme. A registered employer has no right to employ any registered dock worker or an unregistered dock worker, without allotment and allocation of such worker to such a registered dock employer, who must then employ, on being so allotted and allocated by the administrative body to any dock work. There cannot be any direct relation regarding employment of any dock worker in any manner whatsoever between an unregistered dock employer and registered dock employer vis-a-vis an unregistered dock employer and an unregistered dock worker in view of clause 42 of the 1970 Scheme, which forbids employment by any person, other than by registered employer of any dock worker not to speak of registered or unregistered dock worker. In sub-clause (2) of Clause 42 beginning with the words "notwithstanding" the Scheme of 1970 has provided for employment only by registered employer of unregistered dock worker and that only when the administrative body under circumstances specified in sub-clause (2) of the clause 42 of the Scheme of 1970 allots and allocate any unregistered dock worker to a registered dock employer for employment to a specific dock work when on such employment by registered dock employer of any unregistered dock worker, such dock worker would be only a **daily worker**.

5. Having regard to this factual and legal position, I hold that the dispute referred to for adjudication cannot be considered to be an industrial dispute within Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act and cannot, therefore, be entertained and adjudicated upon by this tribunal. There is a reference to an agreement dated 20-2-1970 in the Schedule to the reference and it says inter alia that taking into account the terms of settlement dated 20th February 1970. . . . This agreement is only a bag of wind. It is against the provisions of clause 42 of 1970 scheme. The employer company in the present case, in spite of the agreement, dated 20th February, 1970, is not entitled in law to supply unregistered dock workers like the present 12 workmen to any registered dock employer as it had been doing all these years on the alleged requisition made by the alleged registered dock employers, because of the positive bar created by clause 42 of the 1970 Scheme. Who can allot and allocate an unregistered dock worker like the present 12 workers for employment in any dock work by a registered dock employer? It is only the administrative

body. There is no case that the administrative body under the 1970 Scheme ever allotted any of the 12 workers to any registered dock employer for employment in any dock work at any time. So, the alleged agreement dated 20th February, 1970 being contrary to clause 42 of 1970 scheme is void ab initio and has no legal effect.

6. Accordingly, I hold that the dispute referred to for adjudication being basically violative of the law in Clause 42 of 1970 Scheme is not an industrial dispute and this tribunal has no jurisdiction to entertain the dispute under reference and adjudicate upon. In the result, the reference is rejected.

This is my award.

Dated, May 3, 1973.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer.

[No. L-36011/6/72-P&D]

V. Sankaralingam, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 1973

का. आ. 1661.—यतः मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एक स्कीम-प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 5434, तारीख 9 नवम्बर, 1971 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 11 दिसम्बर 1971 के पृष्ठ 6803 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य था, आक्षेप और सुभाव 15 दिसम्बर, 1971 तक मांगे गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 11 दिसम्बर, 1971 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1971 के प्रारूप पर आक्षेप पर आक्षेप या सुभाव मांगें जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट उक्त अवधि भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 2 दिसम्बर, 1972 में पृष्ठ 5497 पर भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 4003, तारीख 22 नवम्बर, 1972 के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि तक और बढ़ा दी गई थी ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 2 दिसम्बर, 1972 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से कोई भी आक्षेप और सुभाव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस स्कीम का नाम मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1957 में खण्ड 6क के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6क प्रशासनिक निकाय.—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निकाय जिसमें डाक कर्मकारों के ऐसे नियोजक होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नामनिर्दिष्ट करे, या किसी अन्य प्राधिकारी को इस स्कीम के दिन प्रति दिन का प्रशासन चलायाने के प्रयोजन के लिए प्रशासनिक निकाय के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रशासनिक निकाय, बोर्ड और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए और खण्ड 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्कीम के दिन-प्रति-दिन का प्रशासन चलाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार पर्याप्त कारणों के होने पर उप-खण्ड (1) के अधीन नियुक्त प्रशासनिक निकाय को हटा सकेगी :

परन्तु प्रशासनिक निकाय को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।”

[फा. सं. एस.-67014/2/71-पी एण्ड डी]

वी. शंकरलिंगम, जवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 1973

S.O. 1661.—Whereas certain draft scheme further to amend the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 6803 of the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th December, 1971 under the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment, No. S.O. 5434, dated the 9th November, 1971 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 15th December, 1971.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11th December, 1971,

And whereas the said period specified for the purpose of inviting objections or suggestions on the draft of the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1971 was further extended to a period of two months from the date of publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 2nd December, 1972 at page 5497 as No. S.O. 4003, dated the 22nd November, 1972;

And whereas the said Gazette was available to the public on the 2nd December, 1972;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. For Clause 6A of the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, the following clause shall be substituted, namely :—

“6A Administrative Body.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a body

consisting of such employers of dock workers as the Central Government may nominate in this behalf, or any other authority to be the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of this Scheme.

(2) The Administrative Body shall, subject to the supervision and control of the Board and the Chairman and subject to the provisions of clause 14, carry on the day-to-day administration of the Scheme.

(3) The Central Government may, for sufficient cause remove any Administrative Body appointed under sub clause (1):

Provided that the Administrative Body shall not be removed unless it has been given a reasonable opportunity of being heard."

[F. No. S-67014/2/71-P&T]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1973

का० प्रा० 1662—लोक परिसर (अप्राधिकृत आधिकारिकों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 5256, तारीख 5 दिसम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में स्तम्भ 1 और 2 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्:-

| 1 | 2 |
|---|--|
| उप-सचिव (प्रशासन, पूर्ति और सेवा), भारत सरकार | दिल्ली सघ राज्य क्षेत्र में, विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर। |
| विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली। | |

[सं० का० 21012(11)/72-नीति-3]

आर० बी० सक्सेना

उप-निर्देशक सम्पदा और पदेन
अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 23rd May, 1973

S. O. 1662—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 5256 dated the 5th December, 1972, namely:—

In the Table below the said notification, in columns 1 and 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely:—

| 1 | 2 |
|--|---|
| Deputy Secretary (Administration, Supplies and services) Government of India, Ministry of External Affairs, New Delhi. | Premises under the Administrative control of the Ministry of External Affairs, in the Union Territory of Delhi. |

[F. No. 21012(11)/72-Pol. III]

R. B. SAXENA

Deputy Director of Estates and
In-Office Under Secretary

